कल्पमेधा

सभ्यता की कहानी सार रूप में इंजीनियरिंग की कहानी है। वह लंबा और विकट संघर्ष, जो प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के भले के लिए काम कराने के लिए किया गया।

– एस डीकैम्प

न्याय की गरिमा

न्यायपालिका लोकतंत्र का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्तंभ होता है, जो कानून के शासन को बनाए रखने और संविधान की मौलिकता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। भारत में न्यायपालिका को न्याय का मंदिर कहा जाता है, जहां विवादों का निस्तारण कर नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसी भी तरह की परेशानी या जटिल परिस्थिति में नागरिकों के लिए न्यायपालिका अंतिम आस होती है। ऐसे में अगर न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे, तो उस भरोसे का क्या होगा, जो न्याय की उम्मीद पर टिका होता है। यह चिंता सरकार के उन आंकड़ों से उपजी है, जिनमें कहा गया है कि देश के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को वर्ष 2016 से अब तक मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें मिली हैं। सरकार की ओर से शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक वर्ष 2024 में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। यानी समय के साथ शिकायतों का यह सिलसिला बढ़ रहा है।

दरअसल, लोकतंत्र में न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करेगी। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए वह जनता के लिए साहस और आत्मविश्वास का स्रोत भी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी इसकी भूमिका अहम है। आम आदमी की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली की शुचिता को बनाए रखना बेहद जरूरी है और यह तभी संभव हो पाता है, जब न्यायिक अधिकारियों का आचरण पूरी तरह पाक-साफ हो। इसमें दोराय नहीं कि विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में आम नागरिक न्यायपालिका पर अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा होता है। न्यायिक प्रक्रिया भी तभी निष्पक्ष और निर्भीक हो सकती है, जब वह किसी भी तरह के अनुचित हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त हो।

नियमानुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा 'आंतरिक तंत्र' के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दो प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनके तहत शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुपालन के लिए कुछ मानक और सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इनका पालन न होने पर आंतरिक प्रक्रिया के तहत संबंधित न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। मगर, न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें बढ़ने का क्रम यह दर्शाता है कि आंतरिक जांच प्रक्रिया या तो धीमी है या फिर उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के मामले यदाकदा सामने आते रहते हैं, लेकिन उनकी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा का अभाव नजर आता है। पिछले वर्ष मार्च में सामने आए एक न्यायाधीश के दिल्ली स्थित आवास पर जले हुए नोटों की गड्डी मिलने के मामले में अब तक कोई खास प्रगति न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर यह मामला किसी प्रशासनिक अधिकारी या आम नागरिक से जुड़ा होता, तो जांच प्रक्रिया अब तक काफी आगे पहुंच गई होती। इस स्थिति के पीछे उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के मामलों में जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया का जटिल ढांचा भी एक बड़ा कारण है, जिसे सरल एवं स्पष्ट बनाए जाने की जरूरत है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा कायम रहे।

नया अध्याय

बांग्लादेश में हुए चुनावों के बाद जैसे नतीजे आए हैं, उससे साफ है कि अब वहां सत्ता और सियासत का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर इसलिए भी कि वहां कुल 300 में से बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अकेले 209 सीटें मिली हैं। इसके बरक्स जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों को सत्तहत्तर सीटें मिली हैं। जबकि वर्ष 2024 में बांग्लादेश में हुई व्यापक उथल-पुथल के दौरान छात्र आंदोलनों से निकली एनसीपी यानी नेशनल सिटिजंस पार्टी को सिर्फ छह सीटें मिल सकीं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। अब संभावना यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के हाथों में देश की कमान होगी। गौरतलब है कि बीएनपी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 'बांग्लादेश सबसे पहले' के नारे के साथ की थी।

अब जबकि बीएनपी को देश के मतदाताओं ने भारी बहुमत से जिताया है, तो उसके बाद यह देखने की बात होगी कि नई सरकार अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर इस नारे को किस हद तक केंद्र में रख पाती है। खासतौर पर चीन ने जिस तरह बांग्लादेश में दीर्घकालिक हित के मद्देनजर लंबी अवधि के लिए भारी निवेश किया है, उसमें नई सरकार के लिए अपने देश के हित के सवालों पर 'सबसे पहले' की नीति सुनिश्चित करना संवेदनशील फैसला होगा। मगर बांग्लादेश की असली परीक्षा भारत के साथ अपने संबंधों की दिशा तय करने के संदर्भ में होगी। दरअसल, इस क्षेत्र की भौगोलिक हकीकत यह तय करती है कि बांग्लादेश के संबंध में भारत की भूमिका निर्णायक रहेगी। बांग्लादेश की करीब चौरानबे फीसद सीमा भारत के साथ लगी हुई है। यानी सुरक्षा और व्यापार के मामले में बांग्लादेश के लिए भारत की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा कि मतभेद के कई बिंदुओं के बावजूद बांग्लादेश की नई सरकार भारत को लेकर क्या रुख अपनाती है। हाल के समय में बांग्लादेश में जिस तरह का तीव्र ध्रुवीकरण देखा गया, उसे संभालना और फिर से सहज माहौल बनाना वहां की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

सवालों में उलझी गुमशुदगी की गुत्थी

दिल्ली समेत देश भर में लोगों के बड़ी संख्या में लापता होने का संकट समूची व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर इस समस्या से निपटने के लिए ईमानदार प्रयास और जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

योगेश कुमार गोयल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में लोगों के बड़ी संख्या में लापता होने का संकट बढ़ता जा रहा है। यह समूची व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस मामले में दिल्ली जिसे देश की सत्ता, कानून और सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है, वह इस वर्ष की शुरुआत से ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही यहां आठ सौ से अधिक लोगों के लापता हो जाने की खबरों को सामान्य नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस भयावहता का दस्तावेज है, जिसे हम प्रायः 'शहरी जीवन की आपाधापी' कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़े सीधे-सीधे बताते हैं कि दिल्ली में हर रोज औसतन पचास से अधिक लोग ऐसे गायब हो रहे हैं, जिनका कोई सुराग, जांच की दिशा या ठोस जवाब फिलहाल व्यवस्था के पास नहीं है। यह मानवीय संकट देशव्यापी है, मगर दिल्ली में समस्या इसलिए गहरा गई है, क्योंकि यहां गुमशुदगी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में यहां गुमशुदगी के 807 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 63 फीसद महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। देश की राजधानी में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वर्षों से जो दावे किए जाते रहे हैं, वे इन आंकड़ों के सामने बिखरते नजर आते हैं। यह केवल अपराध का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस असुरक्षा की भावना का सवाल है, जो हर उस परिवार को भीतर से तोड़ रही है, जिनका कोई सदस्य अचानक गायब हो गया। लापता होने वाले लोगों के परिवारों को एक ऐसे इंतजार में डाल दिया गया है, जो उनके लिए दिन-ब-दिन असहनीय होता जा रहा है।

यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब हम लापता होने वाले लोगों की संख्या में नाबालिगों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में महज पंद्रह दिनों की अवधि में 190 से अधिक बच्चे लापता हुए, जिनमें अधिकांश लड़कियां हैं। किशोर वर्ग (12 से 18 वर्ष) सबसे अधिक जोखिम में दिखाई देता है। ये घटनाएं कोई संयोग नहीं हो सकतीं, क्योंकि इनमें एक विशेष स्वरूप नजर आता है, जिसके पीछे कोई न कोई संगठित या प्रणालीगत कारण हो सकता है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश भर में बच्चों के लापता होने पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र से कहा है कि ऐसे मामलों के राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार एकीकृत आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसके पीछे संगठित गिरोहों का हाथ तो नहीं।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, दो सप्ताह की अवधि में लापता हुए लोगों में से कुछ को ढूंढ़ लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। ऐसे में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि ये सभी मामले घर से भागने, पारिवारिक विवाद या किसी भ्रम का परिणाम हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में मानव तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण, अवैध तरीके से गोद लेने और संगठित अपराध के तंत्र लंबे समय से सक्रिय हैं। नाबालिग बच्चों तथा कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले लोगों को

भावनात्मक असुरक्षा और डिजिटल माध्यमों के जरिये फैलाया गया झूठा भरोसा कई बार गुमराह कर देता है।

महिलाओं के मामले में घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, आर्थिक शोषण, झूठे रोजगार के वादे और संगठित अपराध, ये सभी कारण उनके लापता होने से

> **लोगों के लापता होने का बढ़ता संकट इस बात को उजागर करता है कि सुरक्षा के नाम पर जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी, हेल्पलाइन और विशेष अभियानों की जमीनी सच्चाई क्या है। तकनीक तभी कारगर होती है, जब उसके पीछे तेज, संवेदनशील और जवाबदेह कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के लापता होने के शुरुआती 24 से 72 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने में देरी, लापरवाही या मामलों को गंभीरता से न लेने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। जब तक हर गुमशुदगी को संभावित अपराध मानकर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लापता होने के आंकड़े यों ही बढ़ते रहेंगे।**

जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में महिलाएं खुद घर से चली जाएं, लेकिन अधिकांश मामलों में उनका गायब होना किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़ा हो सकता है, जिसकी तह तक पहुंचना व्यवस्था के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। यदि हम वर्तमान संकट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। वर्ष 2025 में दिल्ली में 24 हजार से ज्यादा लोग लापता हुए थे, जिनमें साठ फीसद से अधिक महिलाएं थी। पिछले दस वर्षों में यहां दो लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और इनमें से करीब 52 हजार लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है। यह आंकड़ा किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से कम भयावह नहीं है। अगर देश भर की बात की जाए तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की लापता बच्चों की जानकारी देने वाली वेबसाइट के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, देश में औसतन हर दस मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।

यहां सवाल केवल पुलिस की कार्यक्षमता का नहीं है, बल्कि पूरे शहरी तंत्र का है। दिल्ली पुलिस हर बार यही कहती है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और अंतरराज्यीय समन्वय किया जा रहा है। 'जिपनेट' (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क) जैसे डेटाबेस मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य ही लापता लोगों का जल्द पता लगाना है। इसके बावजूद हजारों मामले वर्षों तक अनसुलझे पड़े रहते हैं। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं, प्राथमिकताओं, जवाबदेही और संवेदनशीलता की भी है। शहरों का तेजी से फैलता आकार, झुग्गी-बस्तियों की अनदेखी, प्रवासी आबादी की अस्थिरता और सामाजिक निगरानी की कमी, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां किसी का लापता हो जाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। डिजिटल युग में जहां ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, वहीं डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और आनलाइन प्रलोभन के जरिए अपराध भी पहले से कहीं अधिक संगठित हो चुका है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि समाज इस स्थिति को धीरे-धीरे 'सामान्य' मानने लगा है।

यह संकट इस बात को भी उजागर करता है कि सुरक्षा के नाम पर जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी, हेल्पलाइन और अभियानों की जमीनी सच्चाई क्या है। तकनीक तभी कारगर होती है, जब उसके पीछे तेज, संवेदनशील और जवाबदेह कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के लापता होने के शुरुआती 24 से 72 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने में देरी, लापरवाही या मामलों को गंभीरता से न लेने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। जब तक हर गुमशुदगी को संभावित अपराध मानकर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लापता होने के आंकड़े यों ही बढ़ते रहेंगे। लोगों के लापता होने का जो संकट बढ़ रहा है, वह एक ऐसे तंत्र की सामूहिक विफलता है, जिसने कमजोर, असहाय और जोखिम में खड़े लोगों को हाशिये पर छोड़ दिया है।

यह संकट साफ चेतावनी देता है कि यदि महिलाओं, बच्चों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर ईमानदार मंशा, त्वरित कार्रवाई और ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में ये आंकड़े और भी डरावने रूप में हमारे सामने होंगे। विकास का कोई भी माडल तब तक अधूरा है, जब तक उसमें इंसान की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित न हो। अब वक्त आ गया है कि हम गुमशुदगी को 'सामान्य खबर' मानने की आदत छोड़ें और हर लापता चेहरे को एक चेतावनी के रूप लें। अन्यथा हर नया साल इसी तरह लापता होती उम्मीदों, टूटते परिवारों और अनगिनत अनुत्तरित सवालों के साथ शुरू होता रहेगा।

श्रेष्ठता के समांतर

दुनिया मेरे आगे

गिरीश पंकज

ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। पुनर्जन्म होता या नहीं, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक डर लोगों के मन में बैठा रहता है। हमेशा बैठाया भी जाता है कि अच्छे काम करोगे, तो अगले जन्म में मनुष्य बनकर पैदा होगे और बुरे काम करोगे तो तरह-तरह के पशुओं में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। चौरासी लाख योनियों में भटकने की बात धर्मग्रंथ करते हैं। व्यक्ति के मन में भय इसलिए पैदा किया जाता है कि वह नैतिक दृष्टि से ठीक-ठाक रहे। उसके अंदर मानवता, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी जिंदा रहे। जिस समाज में ऐसे सज्जनों की बहुलता रहती है, वह समाज खुशहाल रहता है। इसलिए सदियों से हमारे धर्मग्रंथों और ऋषि-मुनियों ने मनुष्यों में सदाचरण पर जोर दिया और उस सदाचरण को बरकरार रखने के लिए उन्होंने स्वर्ग-नरक की कथाएं भी रचीं।

सच्चाई यह है कि इस स्वर्ग-नरक को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन धर्मभीरू समाज के मन में यह बात बिठा दी गई है कि ईश्वर हमें देख रहा है... हमारे हर गलत सही काम पर उसकी नजर है। इस भय से ही आम इंसान जीवन में गलत काम करने से बचता है। यह सिर्फ एक कल्पना है और एक तरह से मनुष्य को सन्मार्ग दिखाने, उस पर चलाने की एक उत्तम प्रविधि है। जैसे आजकल बहुत सारे अपराध सिर्फ इसलिए नहीं होते कि जगह-जगह खुफिया कैमरे लगे होते हैं और किसी दीवार पर एक पंक्ति लिखी होती है कि 'आप कैमरे की निगाह में हैं।' पहले लोगों से कहा जाता था कि आप ईश्वर की निगाह में हैं। उस चेतावनी को बहुत कम लोग मानते थे, लेकिन इस भौतिक चेतावनी को लोग गंभीरता से मानते हैं और गलत काम करने से बचते भी हैं। ज्यादा दुस्साहसी अपराधी पहले खुफिया कैमरे को तोड़ भी देते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग-नरक सब यहीं है। अच्छे काम करना और सुखमय जीवन जीना स्वर्ग से कम नहीं है। और बुरे काम करके उसका कुपरिणाम भोगना नरक है। यह सभी महसूस भी करते हैं। अपने सामने ऐसा घटित होते देखते भी हैं। न जाने कितने अरबपति व्यापारी, भ्रष्ट नेता या घोटालेबाज अफसर बेईमानी की कमाई करने के बाद एक दिन जब गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि देखो, उन्हें अपने किए का फल मिल गया। कल तक वे स्वर्ग भोग रहा थे, आज नरक भोग रहे हैं। दूसरी तरफ स्वर्ग वे भोग रहे होते हैं, जो संतोषी हैं और सुखी हैं। लोग जब दान-पुण्य करते हैं, तो उनके अंतर्मन में एक सुखानुभूति होती है। यह सुखद अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उदार मन का धनी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान करता है, तो उसकी ख्याति बढ़ती जाती है। तब उसके मन को जो परमानंद मिलता है, दरअसल वही स्वर्ग है।

> **लोग जब दान-पुण्य करते हैं, तो उनके अंतर्मन में एक सुखानुभूति होती है। यह सुखद अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उदार मन का धनी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान करता है, तो उसकी ख्याति बढ़ती जाती है। तब उसके मन को जो परमानंद मिलता है, दरअसल वही स्वर्ग है।**

जो व्यक्ति जितना सुखी है या पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वह जीवन में एक तरह से वास्तविक स्वर्ग का जीवन जी रहा है। अगर उसके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र आदि दुर्गुण भरे हुए हैं, तो उसका जीवन अपने आप में नरक है। वह कुंठित होकर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह अपने नारकीय जीवन को पहचान नहीं पाता। वह अपनी धूर्त मानसिकता और हल्केपन को अपनी चालाकी समझता है और हर घड़ी दूसरे के अहित को अपनी उपलब्धि मानकर प्रसन्न रहता है। जिस दिन ऐसे लोग आत्म-मंथन करते हुए यह विचार करने लगेंगे कि 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई', तो वे अपना रास्ता बदल सकते हैं। वे अपने हृदय को निर्मल कर लें, उदार कर लें और यह सोचने लगें कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, तो फिर उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। धर्म-कर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे लोग इसीलिए भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं।

धर्म-कर्म पर चलने का अर्थ यह नहीं कि लोग कट्टर हो जाएं और अपने-अपने धर्म के लिए आपस में भिड़ जाएं। अनेक लोग जीवन की सार्थकता लोक कल्याण के कार्य को ही समझते हैं। यही सच्ची धार्मिकता है। सोशल मीडिया के दौर में हम सब अनेक ऐसे वीडियो देखते हैं, जिसमें कोई पुलिसवाला किसी गरीब की मदद कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है, कोई अमीर व्यक्ति फटेहाल बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रहा है, कोई किसी की झोंपड़ी को पक्का करवा रहा है। परमार्थ के आने के वीडियो हम सब देखते हैं। कुछ लोग अपनी लघु फिल्मों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में लगे हुए हैं। यह सारे कार्य हृदय को प्रसन्नता से भर देते हैं। जो इसे देखता है प्रसन्न होता है। कुछ संदेश ग्रहण करता है। फिल्म बनाने वाले को भी संतोष होता है कि उसने एक नेक काम किया। श्रेष्ठ साहित्य की रचना करके भी सुख की अनुभूति होती है। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग-नरक सब यहीं है। श्रेष्ठ कर्म स्वर्ग है और निकृष्ट कर्म नरक। जो विवेकवान हैं, वे इस मर्म को समझते हैं। जो जानबूझकर भी अनजान बने रहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

मिलावट की मार

खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट आज देशव्यापी संकट का रूप ले चुकी है। यह केवल उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी का मामला नहीं, बल्कि सीधे-सीधे जनस्वास्थ्य पर हमला है। दूध, मसाले, तेल, मिठाइयां इत्यादि शायद ही कोई ऐसी वस्तु बची हो, जिसमें मिलावट की आशंका न हो। आम आदमी असमंजस में है कि वह खाए, तो क्या खाए, भरोसा करे तो किस पर। हालिया आंकड़े इस चिंता को और गहरा करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में बीते वर्षों की तुलना में लगभग दो फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में नमूने गैर-मानक पाए गए, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। यह संकेत है कि समस्या केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवस्थागत कमजोरियों और लालच की संस्कृति से जुड़ी है। भोजन जीवन के लिए जरूरी है। उसमें मिलावट जीवन पर वार है। यदि आज हम चुप रहे, तो कल की पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगीं। जब तक मिलावट करने वालों को त्वरित और कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक भय का अभाव बना रहेगा और उपभोक्ता असुरक्षित ही रहेगा।

– मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

स्मृति में रेडियो

कुछ दशक पूर्व रेडियो ही जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम हुआ करता था। इसने न केवल सूचना के प्रसार में अहम भूमिका निभाई, बल्कि मनोरंजन के क्षेत्र में भी कलाकारों को मंच प्रदान किया। तेरह फरवरी 1946 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था। भारत में सत्तर और अस्सी के दशक तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामूहिक रूप से रेडियो पर समाचार सुना करते थे। रेडियो पर अपना नाम सुनने की उत्सुकता लोगों के मन में विशेष आनंद भर देती थी। हालांकि टेलीविजन के आगमन के बाद रेडियो की लोकप्रियता में कुछ कमी आई। अब मोबाइल के युग में इसकी उपयोगिता और भी सीमित हो गई है। फिर भी बदलते समय के साथ रेडियो ने स्वयं को ढाला है। एफएम चैनलों, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से यह आज भी मनोरंजन और समाचार का प्रभावी माध्यम बना हुआ है। रेडियो भावनाओं और यादों से जुड़ा एक सशक्त माध्यम है, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

समाज का चेहरा

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता ने हमारे समाज के कुरूप चेहरे को सामने ला दिया है। इस मुद्दे पर केंद्रित 'स्त्री की गरिमा' (संपादकीय, 13 फरवरी) पढ़ा। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि उस सोच का नतीजा है, जिसमें स्त्री की गरिमा को अब भी हल्के में लिया जाता है। ऐसी घटनाओं पर भीड़ का मौन रहना अपराध को परोक्ष समर्थन देने जैसा है। जब सार्वजनिक स्थल महिलाओं के लिए असुरक्षित बनने लगते हैं, तो यह सभ्य समाज के दावे पर एक सीधा सवाल है। प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन असली लड़ाई सामाजिक जागरूकता की है। घर, स्कूल और समाज- तीनों स्तरों पर स्त्री सम्मान के संस्कार मजबूत किए बिना बदलाव संभव नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान चाहिए। इस बात की जरूरत है कि हम तमाशबीन बनने के बजाय सक्रिय नागरिक बनें।

– आशुतोष पांडेय, जम्मू

निज भाषा

गुयाना की संसद में मंत्री विकास रामकिसून का हिंदी में दिया गया भाषण केवल भाषाई उत्तर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास की घोषणा था। जब विपक्ष ने व्यंग्य किया कि उन्हें हिंदी नहीं आती, तब उन्होंने उसी भाषा में जवाब देकर यह दिखा दिया कि भाषा ज्ञान से अधिक संस्कार और विरासत का विषय होती है। गुयाना ऐसा देश है जहां आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी और गुयानी बोली जाती है, फिर भी भारतीय मूल के लोग हिंदी को अपनी पहचान मानते हैं। इसके उलट हमारे ही देश में कुछ नेता हिंदी से परहेज को राजनीतिक शान समझते हैं। यह विरोध भाषा का नहीं, दृष्टि का है। एक ओर जड़ों से जुड़ने का गर्व है, तो दूसरी ओर दूरी बनाने की जिद। सच यही है कि भाषाएं जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है, जब उसे राजनीति की बजाय संस्कारों से सींचा जाए।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा

समझौते में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस व उसके नेता राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों को लेकर किसानों को गुमराह करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने हर समझौते में किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है।

शाह ने रेखांकित किया कि सरकार ने देश के कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों की पूरी तरह से सुरक्षा की है। उन्होंने व्यापार समझौतों से भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचने के विपक्षी दल के आरोपों को 'हास्यास्पद' बताया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी संसद में खड़े होकर किसानों की सुरक्षा की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। कांग्रेस का देश को गुमराह करने का एक लंबा इतिहास रहा है और अब वे व्यापार समझौतों को लेकर झूठ फैला रहे हैं। शाह भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की शुरुआत करने के बाद गांधीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों के लिए बजट आबंटन लगभग 26,000 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर करीब 1.29 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपने 70 वर्षों में केवल एक बार ऋणमाफी देकर किसानों को गुमराह किया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि यूरोपीय संघ, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे डेयरी उद्योग को खत्म कर देंगे। मैं इस देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक समझौते में उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में भारतीय कृषि के लिए हानिकारक समझौते किए गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पदभार संभालते ही ऐसे प्रावधानों को रद्द कर दिया।

शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत के डेयरी क्षेत्र को खत्म कर दिया है। हमने डेयरी क्षेत्र का विस्तार किया है, इसे कमजोर नहीं किया। सभी समझौतों में डेयरी (क्षेत्र) को पूर्ण संरक्षण दिया गया है। शाह ने राहुल को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क को 50 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिए जाने की घोषणा की। पिछले महीने भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी की।

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ'की बात तो की, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने में विफल रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया। 10 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आज 81 करोड़ लोगों को पारदर्शी तरीके से मुफ्त अनाज मिल रहा है। हमने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 15 गुना अधिक अनाज खरीदा है।

किसानों से व्यापार समझौते के नाम पर हो रहा है विश्वासघात : राहुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए और किसानों के साथ विश्वासघात होने का आरोप लगाया। राहुल ने सरकार पर इस समझौते के जरिए 'आत्मसमर्पण' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा है।

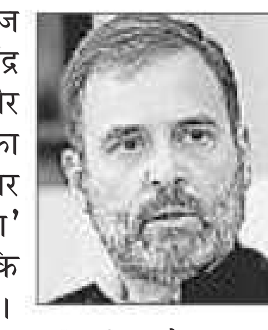

उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत किसी दूसरे देश को अपने कृषि क्षेत्र पर दीर्घकालिक नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दे रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 'एक्स' पर लिखा कि अमेरिका से व्यापार समझौते के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन (डीडीजी) के आयात का क्या मतलब है? राहुल ने कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम (अनुवांशिक रूप से परिवर्तित) अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिल्ड ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दुग्ध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? उन्होंने सवाल किया अगर भारत जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देता है, तो मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि वे कीमतों में गिरावट का एक और झटका कैसे झेल पाएंगे? राहुल ने कहा कि जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोले जाने के दबाव का संकेत है? उन्होंने सवाल किया कि गैर-व्यापार बाधाएं हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, खरीद को कमजोर करने या एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा?

संसद में आवारा कुत्ता लाने से संबंधित मामला

रेणुका चौधरी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी को अपनी कार में एक आवारा कुत्ते को संसद परिसर में लाने और सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने चौधरी के खिलाफ एक शिकायत पर संज्ञान लिया है और 23 फरवरी तक आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है।

संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान, एक दिसंबर को चौधरी आवारा कुत्ते को अपनी कार में संसद लेकर आई थीं और जब कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि 'अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद बृजलाल और इंदु बाला गोस्वामी ने चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसे राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।समिति ने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में इस मामले पर गौर किया और चौधरी से लिखित जवाब मांगा।

सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने चौधरी को 23 फरवरी तक आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है।

भाजपा के दोनों सांसदों ने संसद सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक बयान देने के आरोप में राज्य परिषद कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 188 के तहत चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।नोटिस के संबंध में पूछे जाने पर चौधरी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि वह संसदीय नियमों, मानकों, परंपराओं व प्रक्रियाओं के तहत जवाब देंगी और संविधान में निहित सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करेंगी।

रोमांचक उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देते कलाकार।

केरल : पुरस्कार विजेता किसान ने कर्ज के कारण की आत्महत्या

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

केरल के कन्नूर जिले के चेरुपुझा में 62 वर्षीय पुरस्कार विजेता किसान ने कथित तौर पर बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान चेरुपुझा के इदावरम निवासी अंबट्टू इलियास के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

परिवारिक सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर कीटनाशक का सेवन किया था और तीन दिन पहले अपने खेत में गंभीर हालत में पाए गए थे। जिले के एक निजी अस्पताल में इलियास का इलाज हो रहा था, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि लाखों रुपए का कर्ज होने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। इलियास लगभग चार दशकों से कन्नूर और पड़ोसी जिले कासरगोड के पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टे पर ली गई जमीन पर सब्जियां उगा रहे थे। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस मौसम में भी लगभग 2,500 केले के पौधे लगाए थे, लेकिन उनकी आय उपज के अनुरूप नहीं थी, जिससे वह परेशान थे।

सूत्रों के अनुसार, उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उनकी खेती-बाड़ी फलदायी तो थी, लेकिन उनके आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिवार वालों ने इलियास को एक जुझारु और आशावादी किसान बताया, जो चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करता था। उनका समर्पण नई संभावनाओं की तलाश में बंजर जमीनों को खोजने तक फैला हुआ था, यहां तक कि उन्होंने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए एक साल तक कासरगोड जिले की यात्रा भी की। वे जैविक खेती के तरीके अपनाते थे। फसल के लिए कीटनाशक खुद तैयार करते थे और पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण तकनीकों का इस्तेमाल करते थे

पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही भाजपा : ओवैसी

हैदराबाद, 15 फरवरी (भाषा)।

आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मतदाता सूचियों के एसआइआर के माध्यम से लोगों की नागरिकता अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है।

ओवैसी ने एआइएमआइएम के 68वें पुनरुत्थान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में शनिवार को आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि बिहार के बाद तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) किया जाएगा। हैदराबाद के सांसद ने आरोप लगाया कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जब एसआइआर कराया जाए, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी वास्तविक नाम शामिल किए जाएं। भाजपा एसआइआर के जरिए लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है। वह भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से संशोधन कराकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है।

तेलंगाना के चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूचियों की एसआइआर प्रक्रिया की घोषणा इस वर्ष अप्रैल-मई के दौरान होने की संभावना है। ओवैसी ने तेलंगाना में हाल ही में आयोजित मेडाराम जतारा आदिवासी उत्सव के दौरान कुछ यूट्यूबर्स द्वारा एक मुस्लिम पाव रोटी विक्रेता के कथित उत्पीड़न की भी निंदा की। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना पुलिस मुसलिम विक्रेता को परेशान करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करे। इस तरह की धमकी तथा सांप्रदायिक उत्पीड़न की हरकतें अस्वीकार्य हैं।

बजट सत्र का दूसरा चरण दो अप्रैल तक निर्धारित

बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा नौ मार्च को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 फरवरी।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद मतदान नौ मार्च को होगा। बजट सत्र का दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक निर्धारित है। सत्र 'दिलचस्प' होगा क्योंकि कई 'अहम' विधेयक को संसद में चर्चा और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्षी दल सत्र के पहले चरण की तरह विरोध को जारी रखते हैं तो अंततः यह उनके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नौ मार्च को लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नियम के अनुसार, इस पर पहले दिन ही चर्चा होती है। चर्चा के बाद मतदान होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया।

केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने कहा कि यदि विपक्ष सदन की कार्यवाही में खलल डालता है तो हम बिना किसी चर्चा के विधेयक पारित करा देंगे।

बजट सत्र का अगला चरण नौ मार्च को पुनः शुरू होगा जो दो अप्रैल को समाप्त होगा। अरुणाचल पश्चिम में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए रिजीजू ने बताया कि सत्र के दूसरे चरण के दौरान सरकार चर्चा के लिए विशिष्ट मंत्रालयों की पहचान करने की योजना बना रही है। लोकसभा में हम पांच मंत्रालयों में अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे और राज्यसभा में हम पांच अन्य मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर नहीं बल्कि मंत्रालयों पर चर्चा होगी।

मंत्री ने बताया कि सरकार राज्यसभा में चर्चा के लिए पांच मंत्रालयों का चयन करेगी और फिर लोकसभा के लिए पांच मंत्रालयों का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण रोचक होगा और कहा कि यदि विपक्ष सदन की कार्यवाही में खलल डालता है तो हम बिना किसी चर्चा के उसे पारित करा देंगे, यह उनके लिए करारा झटका होगा। जब उनसे पूछा गया कि सत्र का यह चरण विशेष रूप से रोचक क्यों होगा, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक लाएंगे, जिनमें एक बेहद अहम विधेयक भी शामिल है। हम अभी यह खुलासा नहीं करेंगे कि वह विधेयक क्या है।

पेज 1 का बाकी

'चिकित्सकों ने बनाया था अंसार इंटेरिम संगठन'

गनी, मारे जा चुके उमर-उन नबी और अदील राठेर, फिलहाल फरार उसका भाई मुजफ्फर राथर, मौलवी इरफान, कारी आमिर और तुफैल गाजी अप्रैल 2022 में श्रीनगर में स्थित ईदगाह में मिले थे। बैठक के दौरान उन्होंने 'अंसार इंटेरिम' नामक एक आतंकी संगठन बनाने का फैसला किया, जिसमें अदील को समूह का 'अमीर' (प्रमुख), मौलवी इरफान को 'उप-अमीर'और गनी को कोषाध्यक्ष नामित किया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि आतंकी समूहों में 'अंसार' को आमतौर पर विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जोड़ा जाता है। गिरफ्तार किए गए चिकित्सकों और उपदेशकों ने पूछताछ करने वालों को बताया कि सक्रिय आतंकियों से उनके सभी संपर्क टूट जाने के कारण एक नया समूह बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। बैठक के दौरान सदस्यों को भूमिकाएं और 'कोड' सौंपे गए। उमर ने समन्वयक की भूमिका संभाली और गनी के साथ मिलकर वित्त व खरीद का काम संभाला। साल 2023 में समूह ने हरियाणा के सोहना और नूंह क्षेत्रों से उर्वरक खरीदने का निर्णय लिया। उमर के निर्देश पर, फरीदाबाद की रसायन की एक दुकान से एनपीके (जिसे इस संदर्भ में आमतौर पर पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है) भी खरीदा गया।

पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार चिकित्सकों ने बताया कि उमर ने साधारण आइईडी का निर्माण सीखने के लिए आनलाइन वीडियो देखने शुरू किए थे और वह ट्राइएसीटोन ट्राइपेरोक्साइड तैयार करने में कामयाब रहा था, जो सबसे प्रमुख पेरोक्साइड विस्फोटकों में से एक है। अधिकारियों के अनुसार, अदील ने नए आतंकी समूह के लिए सदस्यों की तलाश शुरू कर दी थी और दक्षिण कश्मीर के दानिश उर्फ जसीर नामक एक व्यक्ति को अपने समूह में शामिल कर लिया था। अदील दानिश को फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय में किराए के एक आवास में ले गया, जहां दोनों ने उमर और गनी को टीएटीपी विस्फोटक सामग्री तैयार करते हुए देखा। बाद में उमर ने दानिश को 'फिदायीन' हमला करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस विश्वास का हवाला देते हुए अंतिम क्षण में अपना इरादा बदल दिया कि इस्लाम में आत्महत्या निषिद्ध है।

पुलवामा के चिकित्सक उमर को कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले एक तंत्र का सबसे कट्टरपंथी सदस्य और प्रमुख संचालक माना जाता है। सबूतों से पता चलता है कि उसकी मूल योजना राष्ट्रीय राजधानी या किसी धार्मिक महत्व के स्थल पर भीड़भाड़ वाली जगह पर एक व्यापक रूप से घातक विस्फोट करने वाला बम रखने और फिर भाग जाने की थी।

कृत्रिम मेधा का शक्तिपुंज बनने की ओर बढ़ रहा भारत

लगातार संरचनात्मक सुधार, नवाचार को प्रोत्साहन और शासन को अधिक सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ठोस व्यापार समझौते करने में विफल रही थी। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत पूर्वानुमान लगा पाने की क्षमता ने भारत में निवेशकों का भरोसा बहाल किया है। मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के कारण भारत 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतोंको मजबूती की स्थिति में अंजाम दे पाया है।

उन्होंने कहा कि मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत वृद्धि का उज्ज्वल केंद्र बना हुआ है।मोदी ने कहा, 'बजट 2026 का समग्र उद्देश्य विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, मूल्य संवर्धन बढ़ाना और कौशल एवं पैमाने को एक साथ लाने की परिस्थितियां तैयार करना है। इसका परिणाम आत्मनिर्भरता और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।' मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अगली छलांग इस पर निर्भर करेगी कि भारतीय उद्यम कितने साहस से नवाचार में निवेश करते हैं, दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण करते हैं और खुद को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, प्रौद्योगिकी रूप से आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वृद्धि इंजन के रूप में स्थापित करते हैं।

उन्होंने निजी कारपोरेट क्षेत्र से शोध एवं विकास में अधिक निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं को बढ़ाने और लाभांश बचाने के बजाय गुणवत्ता एवं उत्पादकता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 'सुधार एक्सप्रेस' की प्रगति पर संतुष्टि के सवाल पर कहा, 'स्वभाव से मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, सार्वजनिक जीवन एक रचनात्मक बेचैनी की मांग करता है। साथ ही, इस यात्रा में हुई प्रगति के पैमाने को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है।'जब उनसे पूछा गया कि क्या विकसित भारत के लिए 'मूनशाट' (बड़ा लक्ष्य) लेने का यह 'अब या कभी नहीं' वाला पल है और क्या इसी वजह से बजट पारंपरिक 'बही-खाता' दस्तावेज जैसा नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा, 'हमारे किसी भी बजट को साधारण बही-खाता दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है। यदि पिछले 25 वर्षों के मेरे नजरिए पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि हमारा काम टुकड़ों में नहीं होता है।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यापक रणनीति, कार्ययोजना और प्रभावी क्रियान्वयन है, जो राष्ट्रव्यापी सोच, उद्देश्य की निरंतरता और दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'यह बाध्यता से उपजा अब या कभी नहीं वाला क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा 'हम तैयार हैं' वाला क्षण है। 2026-27 का बजट विकसित राष्ट्र बनने की इस आकांक्षा को दर्शाता है।' प्रधानमंत्री मोदी ने इस लिखित साक्षात्कार में कहा कि उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा छोड़े गए ह्रासंरचनात्मक अंतरालह्न को दूर करने, साहसिक सुधार करने और विकसित भारत की नींव रखने का काम किया है। भारत ने हाल में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं, जिनसे शुल्क में व्यापक कटौती और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार पहुंच का विस्तार सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के साथ शुल्क संबंधी मतभेद कम करने और व्यापारिक सहयोग गहरा करने पर भी सहमति बनी है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का लापता भारतीय छात्र मृत मिला

अधिकारियों के साथ समन्वय और पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत ले जाने की व्यवस्था करना शामिल है। दूतावास ने कहा कि वाणिज्य दूतावास के अधिकारी परिवार के साथ संपर्क में हैं व सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं सेवाओं में उनका सहयोग करेंगे।

श्रीनिवासैया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में मास्टर आफ साइंस पाठ्यक्रम की पढ़ाई करते थे। बर्कले स्कैनर समाचार पोर्टल ने बताया था कि श्रीनिवासैया के बैग में उनका पासपोर्ट और लैपटाप था जो पार्क हिल्स इलाके में एक दरवाजे पर मिला था।

इससे पहले, स्थानीय पुलिस ने श्रीनिवासैया के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय कानून प्रवर्तन एजंसियों से संपर्क करने को कहा था।

शिअद में शामिल हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना

कोर समिति और वित्त समिति के सदस्य थे।हैं। इससे पहले खन्ना ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के महासचिव, पीपीसीसी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अरविंद खन्ना ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। अकाली दल ही वह मंच है जो किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठाता है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि पंजाब के लोग क्षेत्रीय पार्टी की सरकार चाहते है। लोग चाहते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होकर विकास करे। ऐसे में लोगों की उम्मीदें शिरोमणि अकाली दल से हैं।

किशन के कमाल से भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया

पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए। वहीं, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने एक-एक विकेट लिया।इससे पहले, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ओवर की छठी गेंद पर भारत को पहला झटका दिया।

उन्होंने अभिषेक शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच कराया। इशान के अलावा भारत के अन्य बल्लेबाजों को बड़े शाट खेलने के लिए संघर्ष करना पड़ा लेकिन सलामी बल्लेबाज इशान ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने शाहीन की शुरुआती दो गेंद पर छक्का और चौका मारा और फिर सलमान की गेंद को भी बाउंड्री पर भेजा। तिलक ने भी शाहीन पर चौका जड़ने के बाद लेग स्पिनर अबरार अहमद का स्वागत छक्के के साथ किया। तिलक और इशान ने सईम पर चौकों के साथ पावर प्ले में भारत का स्कोर एक विकेट पर 52 रन तक पहुंचाया। ईशान ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

भारत को दूसरा झटका नौवें ओवर की चौथी गेंद पर अयूब ने दिया। उन्होंने ईशान किशन के विकेट की गिल्लियां बिखेर दी। किशन ने 40 गेंदों में 10 चौके और तीन छक्के की मदद से 77 रन बनाए। इशान और तिलक के बीच 87 रनों की साझेदारी हुई।तिलक ने मोहम्मद नवाज पर छक्के के साथ 12वें ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा किया। 15वें ओवर में भारत को अयूब ने लगातार दो झटके दिए। पहले उन्होंने तिलक वर्मा को पगबाधा आउट किया। इसके बाद क्रिज पर आए हार्दिक पांड्या को बाबर आजम के हाथों कैच कराया। भारत को पांचवां झटका उस्मान तारिक ने दिया। उन्होंने सूर्यकुमार यादव को अपना शिकार बनाया। यादव 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए।

मुख्यमंत्री मान की संगरूर में तबीयत बिगड़ी, भर्ती

चंडीगढ़, 15 फरवरी (ब्यूरो)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रविवार को स्वास्थ्य जांच के लिए मोहाली में स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार संगरूर में अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें मोहाली ले जाया गया।

उन्होंने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दिन में वह महाशिवरात्रि के अवसर पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मत्था टेकने संगरूर जिले के धूरी में स्थित श्री रंकेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचे थे। फाजिल्का में मान के निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में भी उन्हें थकान और ह्रदयगति कम होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वे इसी अस्पताल में जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए भी भर्ती हुए थे।

खरीदारों के हित और अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए गठित आरइआरए (रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) यानी रेरा के कामकाज पर जो नाराजगी जताई है, वह उचित ही है. एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की एक पीठ ने कहा कि रेरा के गठन का मकसद रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, परियोजनाओं में देरी को रोकना और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना था, पर जमीनी स्तर पर तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है. रेरा का गठन जिनके हितों की रक्षा के लिए हुआ था, वे हताश हैं और ऐसा लगता है कि रेरा घर खरीदारों की सुरक्षा करने के बजाय डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को सुविधा दे रहा है. शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश में रेरा ऑफिस को शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शिमला में भीड़ कम करने और प्रशासनिक कारणों से कार्यालय स्थानांतरण का निर्णय लिया गया. विरोधी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि रेरा के करीब 90 फीसदी प्रोजेक्ट और 92 फीसदी लंबित शिकायतें शिमला, सोलन, परवाणू और सिरमौर जिलों से संबंधित हैं, जो 40 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जबकि धर्मशाला में केवल 20 परियोजनाएं हैं. सुनवाई के दौरान जब पीठ को बताया गया कि रेरा में एक सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, तो प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कई राज्यों में ऐसी संस्थाएं पुनर्वास केंद्र बन गयी हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी, पर रेरा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये. देश के रियल एस्टेट क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाने, अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और खरीदारों का विश्वास बहाल करने के लिए आरइआरए को 2016 में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में पेश किया गया था. पर अदालत की टिप्पणियां इस चिंता को रेखांकित करती हैं कि जब तक कार्यान्वयन में सुधार नहीं होता, कानून का वादा केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कानून को रद्द करने या उसमें संशोधन करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया, पर उसकी टिप्पणियां आरइआरए के प्रशासन के तरीके को लेकर बढ़ती न्यायिक निराशा को दर्शाती हैं. इन टिप्पणियों से राज्य सरकारों पर अपने नियामक प्राधिकरणों को मजबूत करने, प्रवर्तन में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ने की संभावना है कि कानून घर खरीदारों को सार्थक सुरक्षा प्रदान करे.

रियल एस्टेट क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाने, अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और खरीदारों का विश्वास बहाल करने के लिए आरइआरए को एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में पेश किया गया था.

बांग्लादेश के पटरी पर लौटने की उम्मीद

डॉ संजय भारद्वाज
प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जेएनयू
sbhardwaj@mail.jnu.ac.in

पिछले 18 महीनों में बांग्लादेश जिस तरह पटरी से उतर गया था, उसे देखते हुए चुनाव में बीएनपी की भारी जीत स्वागतयोग्य है. हालांकि बीएनपी के साथ पुराने रिश्ते को देखते हुए भारत को फूंक-फूंककर कदम उठाना होगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले से ही बीएनपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया. खालिदा जिया का जब देहांत हुआ था, तब हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गये थे. फिर चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को शुभकामनाएं दीं. बीएनपी भी चाहती है कि नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भाग लें. ऐसे में, आपसी रिश्तों के सुधरने की उम्मीद बनती है.

बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिला, जो पिछले 18 महीने के हालात में स्वागतयोग्य है. दरअसल कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह अपने प्रभाव में कर लिया था और बांग्लादेश पटरी से उतर गया था. नतीजों को देखते हुए उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश अब वापस पटरी पर आ जायेगा. हालांकि 13वीं जातीय संसद का चुनाव एक खास विचार के राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला था, जो इस्लाम की राजनीति में अधिक विश्वास रखते हैं. बांग्ला संस्कृति की मुख्य पक्षधर पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया. अतः बीएनपी एवं जमात-ए-इस्लामी के सामने चुनाव में कोई बड़ी चुनौती नहीं थी. जाहिर है कि इस चुनाव को समावेशी और अर्थपूर्ण नहीं कह सकते. वर्ष 2014, 2018 एवं 2024 के चुनावों पर भी इसी तरह के आरोप थे. उन सभी चुनावों में भागीदारी के लिए एकतरफा निर्णय लिये गये थे.

बांग्लादेश का आखिरी समावेशी चुनाव 2008 में ही हुआ था. वर्ष 2008 के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व आया और वही देश के आर्थिक विकास की वजह बना. संतुलित विदेश नीति से व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन मिला. अवामी लीग वह राजनीतिक पार्टी है, जिसके नेतृत्व में बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश के रूप में जन्म हुआ एवं उसने बांग्लादेश को बांग्ला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार दिया. इस चुनाव को हम सही अर्थों में आम चुनाव तभी कह सकते थे, जब जनता के सामने सभी विकल्प खुले होते और राजनीतिक दलों को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अवसर मतदाताओं को दिया जाता. वर्ष 2008 का चुनाव आखिरी चुनाव था, जिसमें बांग्लादेश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया था और लगभग 86 फीसदी वोटिंग हुई थी. इस बार के चुनाव में वोटिंग लगभग 59 प्रतिशत बताई गयी यानी देश के लगभग 40 फीसदी मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की. दरअसल विवादित चुनावों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की परंपरा भी रही है. इसके कारण हैं. चूंकि बांग्लादेश के चुनाव पर नजर रखने वाली घरेलू और विदेशी संस्थाएं हैं, लिहाजा चुनाव प्रक्रिया को एक हद तक विश्वसनीय बनाया जाना जरूरी होता है. मोटे तौर पर बांग्लादेश के चुनावों में दो फॉर्मूलों का जिक्र होता है- माइनस टू (यानी दोनों मुख्य पार्टियों, अवामी लीग और बीएनपी के मुख्य लीडर्स को बाहर करें), दूसरा, माइनस वन और मैनेज वन (यानी एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मैनेज करें). इस बार का चुनाव मैनेज वन-यानी बीएनपी को मैनेज करने का मामला ज्यादा लगता है. वर्ष 2006-2008 के बीच में इस फॉर्मूले की चाभी सेना के पास थी एवं 2024-26 तक जमात ड्राइवर सीट पर थी. इसलिए बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है. यह गनीमत है कि बेहतर को चुना गया. सिर्फ यही नहीं कि मैनेज वन के तहत बीएनपी को बड़ा चेहरा बनाने की कवायद की गयी होगी, बल्कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि तारिक रहमान एक ऐसा चेहरा हैं, जिस पर किसी भी बाहरी देश को- चाहे वह पाकिस्तान हो या अमेरिका- आपत्ति नहीं थी. इसी कारण तारिक रहमान के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमे एवं सजा निरस्त कर दिये गये. इस बार हुए चुनाव की एक खास बात यह है कि जो जमात बीएनपी की सहयोगी पार्टी के तौर पर जानी जाती रही है और जिसने बीएनपी के साथ मिलकर 2001 और 2006 का चुनाव लड़ा था, वही इस बार बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने थी.

हालांकि बीएनपी और जमात में भी कुछ फर्क है. बीएनपी जहां सॉफ्ट इस्लाम की पैरोकार है, वहीं जमात की छवि कट्टर इस्लामी-यानी हार्डलाइनर की है, पर कुल मिलाकर, बीएनपी इस्लामी राष्ट्रवाद पर ही विश्वास करती है. खालिदा जिया के पति और तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान बीएनपी के संस्थापक थे और सत्ता में आने पर उन्होंने बांग्लादेश को बंगाली राष्ट्रवाद से बांग्लादेशी राष्ट्रवाद में तब्दील किया था, जिसका मूल इस्लाम रहा. जियाउर रहमान के दौर में इस्लामी देशों से बांग्लादेश के संबंध मधुर हुए. सत्ता में आने के बाद खालिदा जिया ने वही नीति जारी रखी. उन्होंने पाकिस्तान-चीन से नजदीकी बनायी थी. इसी कारण बीएनपी की नयी सरकार की नीतियों के बारे में संशय है. हालांकि बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद लौटे तारिक रहमान ने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में जो कुछ कहा, उसका अर्थ यह था कि वह बीएनपी की पहले की नीतियों में बदलाव करेंगे तथा इस्लामिक राष्ट्रवाद की जगह सहिष्णुता और उदारवाद को तरजीह देंगे, लेकिन बीएनपी के इतिहास को देखते हुए उस पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं. ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जब 2001 के चुनाव हुए थे, तब भी भारत को बीएनपी से उम्मीद थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद खालिदा जिया ने भारत से दूरी बनायी थी. अब इस चुनाव में शानदार जीत के बाद बीएनपी सरकार बना रही है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं. जमात-ए-इस्लामी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने का काम करती रहेगी. ऐसे में, बीएनपी के साथ विभिन्न मुद्दों पर उसकी असहमति तय है. बांग्लादेश में अब भी अवामी लीग के समर्थक बड़ी संख्या में हैं. नयी सरकार का अवामी लीग के प्रति क्या रुख रहेगा? क्या तारिक रहमान (जिस तर्ज पर तारिक रहमान को माफ किया) अवामी लीग की ज्यादतियां माफ कर सकेंगे? नयी सरकार के सामने जुलाई चार्टर को लागू करने का भी दबाव रहेगा. जहां तक विदेश नीति की बात है, तो हकीकत में यदि बीएनपी की नीतियों में कोई बदलाव न आया, तो नयी सरकार बांग्लादेश को पाकिस्तान-अमेरिका के रास्ते पर ले जा सकती है. वैसे में, चीन भी अपनी रोटी सेंकता रहेगा, लेकिन भारत चूंकि बड़ा देश है और वहां लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश है, ऐसे में, बांग्लादेश द्वारा भारत की अनदेखी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं और आपसी विवाद, सुरक्षा के मुद्दे उलझा सकते है.

लिहाजा भारत को फूंक-फूंककर कदम उठाना होगा. हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले से ही बीएनपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया. खालिदा जिया का जब देहांत हुआ था, तब हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश गये थे. फिर चुनावी नतीजों की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को शुभकामनाएं दीं. उधर बीएनपी भी चाहती है कि नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भाग लें. ऐसे में, आपसी रिश्तों के सुधरने की उम्मीद बनती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार जमानत संहिता बने

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
@viraggupta

सुप्रीम कोर्ट के जजों के अनुसार जमानत देने वाली जिला अदालतें न्यायिक व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हैं. इसलिए जमानत से जुड़े हर मामले में गुण-दोष के आधार पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और महादेवन की पीठ ने अहम फैसले में कहा है कि जमानत की अर्जी में आरोपियों को अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना चाहिए. न्यायिक विवेक को सीधे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों के पूर्ण और स्पष्ट खुलासे से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कम होगा. शीर्ष अदालत ने इस फैसले पर अमल करने के लिए उच्च न्यायालयों के नियमों में बदलाव के सुझाव के साथ पुलिस को भी आदेश दिये हैं. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 2011 के बाद चार राज्यों में नौ से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. वकालत और एमफिल की फर्जी डिग्री हासिल करने वाले हिस्ट्रीशीटर आरोपी ने जमानत हासिल करने के लिए खुद को वकील के तौर पर पेश किया था. आरोपी के खिलाफ चोरी, ठगी, यौन-उत्पीड़न के साथ मार्कशीट और डिग्रियों के फर्जीवाड़े के अपराध दर्ज थे. जमानत रद्द करते हुए जजों ने कहा कि संगीन अपराधों से न्यायिक व्यवस्था और शैक्षणिक तंत्र में बढ़ते पराभव के मर्ज की अनदेखी नहीं की जा सकती.

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जमानत देने से जुड़े तीन बड़े न्यायिक सिद्धांत हैं. पहला, जमानत मिलने के बाद आरोपी सबूतों में छेड़छाड़ न करे. दूसरा, आरोपी आदतन अपराधी नहीं हो और जमानत मिलने के बाद वह नये अपराध नहीं करेगा. तीसरा, जमानत मिलने के बाद आरोपी के भागने की आशंका नहीं होनी चाहिए. इस तीसरे नियम के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के जज पारदीवाला की पीठ ने नये फैसले में कहा है कि फरार आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर बेल नियम है और जेल अपवाद. इसलिए अन्य फैसले में झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जमानत के बावजूद आरोपी के खिलाफ अनेक एफआइआर दर्ज करने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत लोगों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है. डॉक्टर आंबेडकर का जिक्र करते हुए जजों ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता को राहत दी है. पुलिस ज्यादती या गलत मुकदमों में फंसाये गये लोगों को जमानत के साथ फर्जी मुकदमों से जल्द राहत मिलना ही चाहिए. जनता दर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गलत एफआइआर या फर्जी आरोप पत्र में संलग्न पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार एफआइआर दर्ज हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करौल और एन कोटिस्वर सिंह की अन्य पीठ ने व्यापम घोटाला उजागर करने वाले व्हिसल ब्लोअर आनंद राय के खिलाफ एएसी/एसटी एक्ट में लगाये गये आरोप रद्द करने का अहम फैसला दिया है. जजों के अनुसार, आरोप तय करते समय जजों को सावधानी और संतुलन के साथ तथ्यों की ईमानदारी से समीक्षा करने की जरूरत है. मजिस्ट्रेट और जज जिम्मेदारी से काम न करें, तो अदालत की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है. सुप्रीम कोर्ट के जजों के अनुसार जमानत देने वाली जिला अदालतें न्यायिक व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हैं. इसलिए जमानत से जुड़े हर एक मामले में गुण-दोष के आधार पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल जरूरी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के आंकड़ों के अनुसार जेलों में लगभग 5.3 लाख लोग बंद थे, जिनमें 3.9 लाख लोग विचाराधीन कैदी थे. जमानत और फैसलों में विलंब से 2023 में 150 से ज्यादा विचाराधीन कैदियों की जेलों में मृत्यु हो गयी. जिला अदालतों में 3.6 करोड़ और उच्च न्यायालयों में 17.5 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संजय किशन कौल ने कहा था कि इसी गति से मुकदमों का निपटारा होता रहा, तो लंबित मामलों के निपटारे में 500 साल से ज्यादा लग सकते हैं. देशभर में पुलिस थाने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के डिजिटल और कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हैं. एफआइआर दर्ज होने के साथ ही आरोपी से जुड़े अन्य अपराधों का विवरण इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संबंधित जांच अधिकारी की होनी चाहिए. जमानत हासिल करने के लिए गलत हलफनामा देने वालों के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य और झूठा शपथ पत्र देने के मामले में कठोर दंड मिलना चाहिए. लेकिन सामान्य और रूटीन अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिलने में विलंब संविधान के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवज्ञा है.

पिछले साल तीन जजों की पीठ ने कौशल सिंह बनाम राजस्थान सरकार के फैसले में पुराने आपराधिक मामलों के खुलासे की अनिवार्यता की बात दुहरायी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश के कानून माने जाते हैं, जिनका पुलिस और जिला अदालतों में पालन न होना चिंताजनक है. जमानत से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजों के विरोधाभासी फैसलों की वजह से जिला अदालतों में मनमानी के साथ विलंब और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. जन विश्वास कानून और इनकम टैक्स कानून में बदलाव से अनेक अपराधों को अनापराधिक बनाया गया है. खतरनाक अपराधी जेल में रहें और मामूली अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों को जल्द जमानत और रिहाई मिले, इसके लिए भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानूनों में स्पष्ट प्रावधान के साथ जमानत संहिता बनाने की जरूरत है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करे नेपाल

हाल ही में आयोजित कांतिपुर सम्मेलन में कई वक्ताओं ने नेपाल की विदेश नीति सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे. विशेष रूप से नेपाल-भारत संबंधों के संदर्भ में परंपराओं और भावनाओं से परे देखने का आह्वान किया, और सुझाव दिया कि पुरानी परंपराओं और भावुकता से मुक्त होने के लिए नये सिद्धांतों की आवश्यकता है. इससे नेपाल आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों से बेहतर ढंग से जुड़ सकेगा. इस सम्मेलन में किये गये दावों के विपरीत, भारत-नेपाल संबंध संरचित ढांचे और व्यावहारिकता पर आधारित है. आज की अशांत वैश्विक परिस्थितियों में, नेपाल को सावधानी बरतनी चाहिए. उभरता हुआ वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों सहित कोई भी देश सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे या तो ट्रंप के समर्थन पाने के प्रयास में हैं, या अमेरिका और दुनिया के साथ अपने संबंधों को नये सिरे से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं. इन परिस्थितियों में नेपाल को किसी भी शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए. विशेष रूप से, अमेरिका के लिए चीन के मुद्दे के अलावा नेपाल की कोई प्राथमिकता नहीं है. यदि नेपाली शासन पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखने में सावधानी नहीं बरतते हैं, तो अमेरिकी प्रतिक्रिया निश्चित है. इसलिए, अपने आपको बचाये रखने की नयी कला विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाये रखने के साथ-साथ आंतरिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाये. बहुत पहले सुलझ चुके मुद्दों को उछालना उचित नहीं है. पड़ोसियों के साथ विश्वास और निष्पक्षता के आधार पर संबंधों को सही ढंग से संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि संकट की स्थिति में अन्य देश मदद के लिए आगे नहीं आयेंगे. जेन जी के विद्रोह को भविष्य के लिए सबक मानते हुए नेपाल के नये नेताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नयी वास्तविकताओं को समझना चाहिए.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

-लोक राज बराल

बोधि वृक्ष

परमपिता परमात्मा का सहारा

निःसंदेह इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हम सभी को जीवन के हर मोड़ पर कई लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है. विश्व में ऐसा कोई भी नहीं जो यह कह सके कि उसे किसी के सहारे या साथ की जरूरत नहीं है. क्योंकि जन्म लेते ही सभी को मां की गोद और मृत्यु के पश्चात श्मशान जाने के लिए चार मजबूत कंधों की आवश्यकता पड़ती ही है. इन दोनों के बीच जो समय गुजरता है, उसे ही हम जीवन कहते हैं. जीवन यात्रा के दौरान भी हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती ही है, जो मुसीबत की घड़ी में हमारी सहायता करे, हमें संभाले. मनुष्य जैसे सामाजिक प्राणी का जीवन साथियों के बिना मुश्किल हो जाता है. इसलिए जब बच्चा छोटा होता है, तो माता-पिता को साथी समझ कर चलता है. स्कूल में सहपाठियों को, समान आयु वाले बच्चों को साथी बनाता है और फिर विवाह के बाद पति-पत्नी एक-दूजे के साथी बनकर चलते हैं. पर ये सभी साथी केवल सांसारिक लेन-देन करने वाले होते हैं, जो हमारे दिल को थोड़े समय के लिए बहलाते हैं. इसीलिए इन्हें 'अल्पकाल का सहारा' माना जाता है, जो आज तो है, पर निश्चित नहीं कि कल रहेगा या नहीं. ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सदा-सदा के लिए हमारा सहारा कौन बनेगा. क्या कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है जो सदैव हमारा सहारा बनकर रहे. ऐसा सहारा केवल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का ही हो सकता है, जो सभी आत्माओं के अविनाशी साथी हैं. जो कभी भी, कैसी भी परिस्थिति में हमारा हाथ व साथ नहीं छोड़ते. जो याद करने पर उसी घड़ी हमारी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं. जिन्हें दुख के समय हम सभी पुकारते हैं. उनके सिवा संसार में कोई भी अंत तक सहारा नहीं दे सकता. स्मरण रहे! जो व्यक्ति कमजोर शाखा पर झूला बांधकर झूलता है, वह थोड़े समय की ही खुशी मना सकता है. अर्थात, वह जल्द ही गिर जाता है. अतः, हमें सभी अल्पकाल के सहारों को छोड़ परम सहारे परमात्मा को अपनाकर सदा-सदा के लिए सुरक्षित सहारा प्राप्त कर लेना चाहिए. जब हमें सर्वशक्तिमान का हाथ और साथ मिल जाता है, फिर सारा संसार हमारा साथ देता है.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

प्रबंध सूत्र

अक्सर बड़े बोल बन जाते हैं फंदा

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

पाकिस्तान ने पहले बहुत बयान दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे. फिर जब बायकॉट का परिणाम समझ में आया, तो डर कर उसने अपना बायकॉट खत्म किया. इसे एक तरह से अपने कहे से मुकरना कहा जाता है. अपने कहे से मुकरना बहुत खराब माना जाता है, विशेषकर कारोबार की दुनिया में. विश्वस्त आदमी उसे ही माना जाता है, जो कभी अपनी बात से न पलटे. कारोबार में शब्दों की बहुत कीमत होती है, कई बार तो लिखे हुए कांट्रैक्ट से अधिक. हर बाजार में, हर धंधे में ऐसे लोग होते हैं, जिनके शब्दों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे लोग भी होते हैं, जिनके लिखे कांट्रैक्ट पर भी कोई भरोसा नहीं करता. बड़बोले लोगों के सामने भले ही लोग कुछ न बोलें, पर उनकी पीठ पीछे उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है.

आज जितने कार्टून ट्रंप के बड़बोलेपन पर बनते हैं, उतने कार्टून किसी और विषय पर नहीं बनते. बड़ी-बड़ी बातें, फिर उनके विपरीत जाकर फैसला करने से लोगों का भरोसा कम हो जाता है. बड़ा बोलकर कोई तात्कालिक तारीफ हासिल कर सकता है, पर एक न एक दिन तो परिणाम बताना ही पड़ेगा. यदि परिणाम पहले की बातों के अनुरूप न निकले, तो बहुत बेइज्जती होती है. मानव जीवन में शब्दों का महत्व है, परंतु शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं कर्म. जब कोई व्यक्ति या संस्था केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है, तो उसका मूल्यांकन परिणामों से होता है. यदि परिणाम विपरीत हों, तो वही बातें उपहास का कारण बन जाती हैं. इसलिए रहीम ने कहा- 'बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल. 'रहिमन' हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल.' बड़ी बातें फंदा बन जाती हैं. इसलिए, बड़ी-बड़ी बातें करने से बचना चाहिए, कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए. रहीम ने कहा- 'बड़े न बोलें बोल.' इसका आशय है, विनम्रता और संयम ही व्यक्ति की शोभा है.

पर, 'बड़े न बोलें बोल' पर अमल सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही मुश्किल है. सौ रुपये की बनियान खरीदकर भी सोशल मीडिया पर बताना और इसे कामयाबी के तौर पर पेश करना अब आम हो गया है. अब बताना ज्यादा जरूरी है, भले ही कामयाबी हो या नहीं. बड़बोलापन अब एक सहज सोशल मीडिया संस्कार हो रहा है. यह खतरनाक है. कोई भी हमेशा कामयाब नहीं होगा, किसी का बड़बोलापन हमेशा सकारात्मक नतीजे लेकर नहीं आयेगा. शांत रहना अब मुश्किल हो रहा है, सोशल मीडिया के दौर में. रोज कुछ कहना, लगातार कहना है. ऐसे में बोलने में संयम बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बाद में अपनी बात से पलटना होता है, तो बहुत अपमानजनक स्थिति बन जाती है. परिणाम ही असली बयान होते हैं.

आपके पत्र

डीपफेक पर सख्ती सही कदम

केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआइ से बने भ्रामक कंटेंट पर कड़े निर्देश जारी किये हैं. आपत्तिजनक या फर्जी सामग्री को तीन घंटे के भीतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाना होगा. कंटेंट पोस्ट करते समय क्रिएटर्स को स्पष्ट बताना होगा कि वीडियो, चित्र या टेक्स्ट एआइ से तैयार है या नहीं. यदि कोई गलत जानकारी देगा, तो उसकी पहचान की जायेगी. नियम का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम है.

रश्मि मांझी, ईमेल से

झारखंड बने तकनीक का हब

झारखंड खनिज संपन्न राज्य होने के बावजूद ग्रामीण-आदिवासी बहुल है. ऐसे में यहां के गांव-देहात तक तकनीक पहुंचाने की जरूरत है. इससे राज्य में रोजगार बढ़ने के साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा. इसके लिए प्रत्येक जिले में डिजिटल साक्षरता केंद्र खोले जायें. आइटीआइ में एआइ, ड्रोन, रोबोटिक्स कोर्स जोड़े जाएं. रांची को साइंस सिटी का हब बनाकर मोबाइल वैन से आदिवासी पंचायतों में विज्ञान प्रदर्शनी लगायी जाए. इस तरह झारखंड तकनीक का हब बन पायेगा.

सुमित सागर, हजारीबाग

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

प्रयागराज माघ मेला संपन्न : महाशिवरात्रि पर 40 लाख श्रद्धालुओं ने लगायी गंगा में डुबकी

ऊं नमः शिवाय के जयघोष से गूंज उठी संगम नगरी

22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया 44 दिनों तक चले माघ मेले में

एजेंसियां, प्रयागराज

संगम की रेती पर सजे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम 'माघ मेला 2026' का रविवार को समापन हो गया. माघ मेले के अंतिम और छठवें स्नान पर्व 'महाशिवरात्रि' पर श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बना. रविवार को 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगायी. महाशिवरात्रि के पावन मौके पर शिव की नगरी काशी भी शिवमय नजर आयी. काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ भक्ति ही भक्ति दिखायी दी. हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों की गूंज, भोर से पहले ही सड़कों पर उमड़ी आस्था की लहर और बाबा के दरबार तक पहुंचने की बेकरारी में घंटों कतार में खड़े श्रद्धालु दिखे. दोपहर बाद भव्य शिव बारात भी निकाली गयी, जिसमें श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी. रामनगरी अयोध्या भी शिवभक्ति में सराबोर नजर आयी.

नेपाल : पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़े शिवभक्त

काठमांडू. नेपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को पशुपतिनाथ मंदिर और देशभर के अन्य शिव मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के सभी चारों कपाटों को देर रात दो बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था. इस वर्ष मंदिर में लगभग आठ लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनमें से 30 प्रतिशत भारतीय हैं. पिछले वर्ष इस अवसर पर पशुपति क्षेत्र में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे. पशुपतिनाथ के साथ-साथ लोग घाटी के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों जैसे गोकर्णेश्वर और माखन महादेव में भी दर्शन किये. राजधानी के बाहर स्थित शिव मंदिरों में भी प्रार्थना करने वालों का तांता लगा रहा. पशुपतिनाथ मंदिर में प्रार्थना के लिए सैकड़ों नागा बाबाओं सहित लगभग 4,500 साधु काठमांडू पहुंचे हैं.

ग्लोबल बाइट्स

बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के 70 मीटर दायरे में मोबाइल पर प्रतिबंध

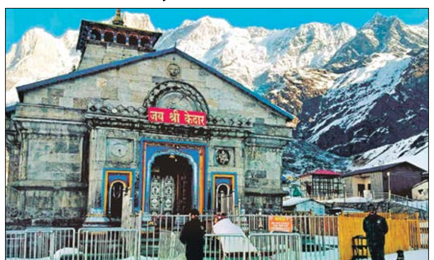

देहरादून. आगामी चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में मंदिर परिसर से 70 मीटर दायरे में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. श्रद्धालु मंदिर के नजदीक जाकर रील व वीडियो नहीं बना सकेंगे. धामों की पवित्रता व सुगम दर्शन व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन व मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है. यह निर्णय धाम की पवित्रता तथा तीर्थयात्रियों को सरल सुगम दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्री-केदार धाम में व्यवस्थाओं को मंदिर समिति की ओर से प्रशासन से समन्वय कर बेहतर बनाया जायेगा.

लेन-देन के संबंध नहीं, अपनत्व है भारत की पहचान : भागवत

गोरखपुर. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत आज विश्व में सद्भावना और सामाजिक समरसता का एक वैश्विक केंद्र बन कर उभरा है. उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत सोच लेन-देन आधारित संबंधों पर नहीं, बल्कि एकत्व और आपसी अपनत्व की भावना पर आधारित है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत द्वारा रविवार को आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि समाज की पहचान स्वार्थ से नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ाव से होती है.

हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रमकता चिंताजनक : अमेरिकी कमांडर

नयी दिल्ली. अमेरिकी सेना के हिंद-प्रशांत कमान के कमांड के एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने रविवार को कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी का एक ही उद्देश्य ताकत के जरिये शांति बनाये रखना है. उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती जबरन कार्रवाई और आक्रामकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयम दिखाने के लिए भारतीय सेना की प्रशंसा की. पपारो वर्तमान में नयी दिल्ली की यात्रा पर हैं.

असम में गैंडे के हमले में एक वन रक्षक की मौत, दूसरा घायल

जोरहाट. असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रविवार को गैंडे के हमले में एक वन रक्षक की मौत हो गयी, जबकि एक अन्य घायल हो गया. वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना कोहोरा रेंज में सुबह की गश्त के दौरान घटी. अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान सहाबुद्दीन के रूप में और घायल की पहचान रामेन बोरा के रूप में हुई है.

जयपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर विदेशी महिला यात्री को कुत्ते ने काटा

जयपुर. जयपुर अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल-2 पर रविवार की दोपहर एक कुत्ते ने दिल्ली से यहां पहुंची विदेशी महिला यात्री को काट लिया, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगा. वहां मौजूद लोगों ने महिला को तुरंत संभाला और हवाई अड्डा प्रबंधन को इसकी सूचना दी. इसके बाद महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया. हवाई अड्डा प्रबंधन ने बताया कि विदेशी महिला यात्री बेट-एल नूरियल दोपहर दो बजे दिल्ली से जयपुर पहुंची थी. 37 वर्षीय नूरियल इस्राइल से भारत घूमने आयी हैं.

भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जतायी है : रूबियो

म्यूनिख. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जतायी है. यह बयान भारत द्वारा यह बात दोहराने के कुछ दिनों बाद आया है कि कच्चे तेल की खरीद के संबंध में नयी दिल्ली के निर्णयों के लिए राष्ट्रीय हित मार्गदर्शक कारक होगा और ऊर्जा नीति के प्रमुख आधार पर्याप्त उपलब्धता, उचित मूल्य निर्धारण और आपूर्ति की विश्वसनीयता हैं.

साक्षात्कार. केंद्रीय बजट, अहम ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखे विचार

भारत ने 38 देशों से अपनी शर्तों पर किये व्यापार समझौते : मोदी

एजेंसियां, नयी दिल्ली

हमारी सरकार ने सुधार को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है और यह सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि काम में भी दिखा है. राजनीतिक स्थिरता और नीति की स्पष्टता से निवेशकों का भरोसा भारत में बढ़ा है. इसी कारण भारत अब मजबूत स्थिति में व्यापार समझौते कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआइ को दिये एक विशेष इंटरव्यू में बताया कि देश ने 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किये हैं. उन्होंने कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं का क्षेत्र और एमएसएमई सेक्टर ने भारत को वैश्विक व्यापार वार्ताओं में ताकत दी है. उन्होंने कहा कि हमारे एफटीए टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी और अन्य क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के बजट सिर्फ साधारण बही-खाता दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे देश के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप होते हैं. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय उत्पादों ने निर्यात के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं. उन्होंने डिफेंस बजट में हुई बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप करे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के रक्षा बलों को समर्थन देने और उन्हें मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी.

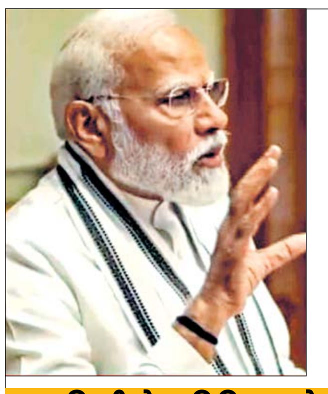

यूपीए सरकार के कुप्रबंधन से कभी नहीं हुई ट्रेड डील

पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संप्रग सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत व्यापार वार्ताओं में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सका और एक भी बातचीत निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी. संप्रग सरकारों ने कुछ व्यापार समझौते करने की कोशिश की, लेकिन यह यात्रा अनिश्चितता और अस्थिरता से भरी रही.

विकसित भारत की अगुआई महिलाएं करेंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है, जो 2013 की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय उत्पादक निवेश पर ध्यान दे रही है. उन्होंने यह भी दोहराया कि विकसित भारत की अगुवाई महिलाएं करेंगी और नीतिगत फैसलों में महिला कल्याण केंद्रीय मार्गदर्शक है. महामारी के बाद के दौर को अवसर बताते हुए उनका संदेश साफ है- स्थायी प्रतिस्पर्धा नवाचार, दक्षता और बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही आयेगी, और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

निजी क्षेत्र, डिजिटल नेतृत्व और एआइ की नींव

प्रधानमंत्री ने अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन में निजी क्षेत्र को निर्णायक बताया और रिसर्च, सप्लाई चेन व गुणवत्ता में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया. डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रोजगार का बड़ा स्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआइ ने लेनदेन की संस्कृति बदल दी है और भारत डिजिटल नेतृत्व की पंक्ति में खड़ा है. साथ ही, कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर विस्तार के जरिये एआइ इकोसिस्टम की मजबूत नींव रखी जा रही है. अगले दशक के लिए संरचनात्मक सुधार, डीप इनोवेशन और सरल शासन तीन प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गयी हैं.

जमात-ए-इस्लामी ने दी बांग्लादेश चुनाव परिणामों को चुनौती

ढाका. बांग्लादेश में हाल में संपन्न हुए चुनावों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी जमात-ए-इस्लामी ने रविवार को परिणामों को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग से उन 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की पुनर्गणना कराने की मांग की, जहां उसके उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से पराजित किया गया था. पार्टी ने बीते गुरुवार को हुए चुनावों में अपने पूर्व सहयोगी बीएनपी की जीत को स्वीकार करने वाले फेसबुक संदेश को भी वापस ले लिया. चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किये गये थे. तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 49.97 प्रतिशत मतों और 209 सीट के साथ दो-तिहाई बहुमत से सत्ता हासिल की.

जम्मू-कश्मीर में 800 म्यूल खातों के नेटवर्क का भंडाफोड़

एजेंसियां, नयी दिल्ली/श्रीनगर

सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में म्यूल खातों के लगातार बढ़ते नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और अधिकारियों को आशंका है कि इन खातों के माध्यम से भेजे गये धन का उपयोग अलगाववादी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि तीन वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र में संचालित 8,000 से अधिक म्यूल खातों की पहचान की गयी है और इनसे लेन-देन रोक दिया गया है, जिससे धन शोधन के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है. उन्होंने इन खातों को साइबर अपराध श्रृंखला में सबसे कमजोर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया, क्योंकि इन खातों के बिना हेरफेर किये गये पैसे का क्रिप्टोकरेंसी में बदलना और इसका पता लगाना असंभव होगा. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बैंकों के साथ परामर्श करने के लिए कहा है. एजेंसियों का मानना है कि म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाले बिचौलिये सीधे तौर पर पीड़ित को शिकार नहीं बनाते, लेकिन कमीशन लेकर धन शोधन में भूमिका निभाते हैं, जिसमें धोखाधड़ी से प्राप्त धन को कई खातों में स्थानांतरित किया जाना और पकड़े जाने से बचने के लिए इसे छोटे-छोटे लेन-देन में विभाजित करना शामिल है.

अमेरिका में मिला लापता भारतीय छात्र का शव

न्यूयॉर्क. अमेरिका में एक सप्ताह से भी कम समय पहले लापता हुआ 22 वर्षीय भारतीय स्नातकोत्तर छात्र शव मिला है. भारतीय दूतावास ने यहां यह जानकारी दी. कर्नाटक के रहने वाले और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में पढ़ने वाले छात्र साकेत श्रीनिवासैया सोमवार से लापता थे. सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में छात्र के शव की बरामदगी की पुष्टि की. पोस्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस ने लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया के शव की बरामदगी की पुष्टि कर दी है. श्रीनिवासैया के प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. श्रीनिवासैया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में मास्टर ऑफ साइंस पाठ्यक्रम की पढ़ाई करते थे.

एआइ समिट आज से : फ्रांस-ब्राजील के राष्ट्रपति होंगे शामिल

एआइ महाकुंभ में जुटेंगे 45 देशों के 25 लाख प्रतिनिधि

एजेंसियां, नयी दिल्ली

भारत 16 फरवरी से कृत्रिम मेधा (एआइ) पर केंद्रित वैश्विक नेतृत्व की नयी पटकथा लिखने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडिया एआइ इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो पांच दिवसीय एआइ इंपैक्ट समिट के साथ भारत मंडपम में आयोजित होगा. यह आयोजन भारत को एआइ युग का नियम-निर्माता और नवाचार का केंद्र स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. यह एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरेना में आयोजित होगा, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लायेगा. इस एक्सपो में एआइ तंत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के मंडप भी होंगे. इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पवेलियन शामिल हैं. इस एक्सपो में 300 से अधिक चुनिंदा प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शन होंगे, जिन्हें तीन मुख्य विषयों लोग, ग्रह और उन्नति के आधार पर तैयार किया गया है. एक्सपो में 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप शामिल होंगे.

500 से अधिक सत्र होंगे, 3250 वक्ता करेंगे मंथन

समिट में 45 से अधिक देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा पीएम मोदी के निमंत्रण पर भाग लेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में शामिल होंगे. 500 से अधिक सत्रों में 3,250 से ज्यादा वक्ता एआइ के भविष्य, नैतिकता और वैश्विक लाभ पर मंथन करेंगे.

पहले दिन प्रवेश पर प्रतिबंध : एआइ समिट में प्रवेश पर कार्यक्रम के पहले दिन कुछ प्रतिबंध होंगे और इसके साथ आयोजित होने वाली प्रदर्शनी 17 फरवरी से सभी के लिए खुलेगी.

टेक दिग्गजों की मौजूदगी

गूगल के सीइओ सुंदर पिचई, ओपनएआइ के प्रमुख सैम ऑल्टमैन, गूगल डीपमाइंड के डेमिस हेसाबिस समेत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व सम्मेलन में शिरकत करेगा. प्रधानमंत्री शीर्ष सीइओ के साथ संवाद कर भारत की एआइ नीति और अवसरों पर चर्चा करेंगे.

स्पेशल

एआइ प्लेज के साथ बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत एआइ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. दरअसल, एआइ रिस्पोंसबिलिटी प्लेज कैंपेन के तहत के देश में 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक शपथ लेने की कोशिश की जायेगी. इसके साथ ही भारत मंडपम में एआइ इंपैक्ट समिट की शुरुआत होगी. यह रिकॉर्ड 24 घंटे में एआइ जिम्मेदारी अभियान में मिलीं सबसे ज्यादा शपथ की कैटेगरी में होगा. इस शपथ के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय ने एक ऑफिशियल पोर्टल तैयार किया है. एआइ शपथ में कोई भी हिस्सा ले सकेगा. एआइ रिस्पोंसबिलिटी के तहत के प्लेज की शुरुआत 16 फरवरी से शुरुआत होगी, जो आने वाले 24 घंटे तक जारी रहेगी. शपथ की मदद से एआइ के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना है.

एआइ के प्लेज पोर्टल पर शपथ लेने की प्रक्रिया

- सबसे पहले टेक द प्लेज पर क्लिक करें. इसके बाद पूरा नाम, ईमेल आईडी या फोन नंबर एंटर करें.
- फिर एक छोटे से एआइ क्विज को कंप्लीट करें. इसके लिए कोई मार्क्स आदि की जरूरत नहीं होगी.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक डिजिटल प्लेज नजर आने लगेगा.

नदी के नीचे चार लेन की यह टनल भारत की पहली और दुनिया की दूसरी होगी

ब्रह्मपुत्र के नीचे साथ दौड़ेंगी ट्रेन और बसें

प्रभात खास

नेशनल कंटेंट सेल

भारत में अब नदी के नीचे से रेल और गाड़ियां साथ दौड़ेंगी. केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रोड-कम-रेल सुरंग के निर्माण को हरी झंडी दे दी है. यह परियोजना इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (इपीसी) मॉडल पर तैयार होगी. यह सुरंग न केवल भारत की पहली अंडरवाटर रोड-रेल टनल होगी, बल्कि दुनिया की दूसरी ऐसी संरचना मानी जा रही है, जहां सड़क और रेल दोनों एक साथ पानी के नीचे से गुजरेंगे. परियोजना से असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को रणनीतिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी.

छह घंटे का सफर सिमटकर 20 मिनट

नेशनल हाइवे-715 पर स्थित नुमालीगढ़ और एनएच-15 पर गोहपुर के बीच वर्तमान दूरी लगभग 240 किलोमीटर है. सिलीघाट के पास कालियाभंभोरा पुल से होकर गुजरने में करीब छह घंटे लगते हैं और वाहनों को काजीरंगा नेशनल पार्क तथा विश्वनाथ क्षेत्र से होकर निकलना पड़ता है. नयी 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने के बाद यह सफर महज 20 मिनट में पूरा हो सकेगा.

अंडरवॉटर रेल-रोड टनल

- **कहां बनेगी :** गोहपुर-नुमालीगढ़ के बीच
- **लंबाई :** 15.8 किमी
- **लेन :** 4 लेन की टनल
- **लागत :** ₹18,662 करोड़
- **निर्माण :** करीब 5 साल

एक्सप्लेनर | पर्यटन स्थल, आर्थिक केंद्र भी जुड़ेंगे

यह प्रोजेक्ट असम के 11 आर्थिक केंद्रों, तीन सामाजिक केंद्रों, दो प्रमुख पर्यटन स्थलों और आठ लॉजिस्टिक नोड्स को जोड़ने की परिकल्पना पर आधारित है. इसके साथ ही चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों, दो हवाई अड्डों और दो अंतर्देशीय जलमार्गों से बेहतर एकीकरण सुनिश्चित किया जायेगा. बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग, व्यापार और पर्यटन को सीधा लाभ मिलेगा. पूर्वोत्तर भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नयी रफ्तार मिलेगी.

सामरिक दृष्टि से मजबूत होगा पूर्वोत्तर

सरकार के अनुसार निर्माण चरण में लगभग 80 लाख रोजगार दिवस सृजित होंगे. यह परियोजना उत्तर-पूर्व की सुरक्षा और पहुंच को भी सुदृढ़ करेगी. सीमावर्ती राज्यों तक तेज आवाजाही सामरिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है.

ऐसी एकमात्र टनल इंग्लिश चैनल के नीचे है : दुनिया में फिलहाल ऐसी संयुक्त अंडरवाटर टनल का प्रमुख उदाहरण चैनल टनल है, जो इंग्लिश चैनल के नीचे युनाइडेट किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है. 1994 में शुरू हुई इस टनल की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है, जिसमें 37.9 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है.

व्यापार समझौतों को लेकर झूठ फैला रहे राहुल गांधी : शाह

गांधीनगर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को राहुल गांधी पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार समझौतों को लेकर किसानों को गुमराह करने व झूठ फैलाने का आरोप लगाया. शाह ने जोर दिया कि सरकार ने देश के कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों की पूरी तरह से सुरक्षा की है. शाह ने ट्रेड डीलों से भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचने के विपक्षी दल के आरोपों को हास्यास्पद बताया. शाह भारत की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

राहुल बोले- किसानों से हुआ विश्वासघात : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए रविवार को पीएम से कई सवाल किये और किसानों के साथ विश्वासघात होने का आरोप लगाया.

अब केवल परमाणु ऊर्जा ही वैश्विक तापक्रम वृद्धि को रोक सकती है। -जेम्स लवलॉक

एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) को मंजूरी दिया जाना देश के शहरी भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता राज्य सरकारों, स्थानीय निकाय और निजी क्षेत्र के प्रयासों पर निर्भर करेगी।

अमल की चुनौती

ऐसे समय में, जब गांवों से शहरों की ओर पलायन, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र का विस्तार और बेहतर जीवन सुविधाओं की तलाश ने शहरों पर अभूतपूर्व दबाव डाला हुआ है, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) को मंजूरी दिया जाना देश के शहरी भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। देश की लगभग 35 फीसदी आबादी शहरों में रहती है और अनुमान है कि 2047 तक यह आंकड़ा 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का इंजन माने जाने वाले शहर, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60 फीसदी से अधिक योगदान भी देते हैं, बुनियादी सुविधाओं की कमी, अव्यवस्थित यातायात, जलभराव, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और आवास संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना से कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश की कमी और स्थानीय निकायों की वित्तीय कमजोरी प्रगति की राह में अड़चन बनी हुई है। अर्बन चैलेंज फंड इन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास है। इस फंड के तहत, केंद्र सरकार परियोजना की कुल लागत का 25 फीसदी तक केंद्रीय सहायता के रूप में देगी, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 50 फीसदी राशि बाजार से जुटाई जाए। हालांकि किसी भी योजना की कामयाबी केवल धन के आवंटन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके क्रियान्वयन की क्षमता पर भी निर्भर करती है। भारत के अधिकांश नगर निगम वित्तीय रूप से कमजोर हैं और उनकी आय के स्रोत भी सीमित हैं। आर्थिक सर्वेक्षण- 2026 के अनुसार भारतीय शहर अपने राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 फीसदी से भी कम प्राप्त करते हैं। दूसरी चुनौती समावेशिता की है, क्योंकि अगर फोकस केवल बड़ी परियोजनाओं पर रहा, तो असमानता बढ़ सकती है। निष्पादन और पारदर्शिता का भी सवाल है। ऐसे में, परियोजना की मजबूत निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट को शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि परियोजनाएं वाकई लोगों की जरूरतों के अनुरूप बन सकें। इसके अतिरिक्त, देश के कई शहर बाढ़, हीटवेव और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। लिहाजा, शहरी नियोजन में पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है निजी निवेश की भागीदारी, जिसे सरकार शुरुआती प्रोत्साहन तो दे सकती है, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे की विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल को मजबूत करना होगा। पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध मंजूरी और जोखिम-साझेदारी की स्पष्ट व्यवस्था निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकती है। वस्तुतः, अर्बन चैलेंज फंड की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और निजी क्षेत्र कितनी गंभीरता और समन्वय से काम करते हैं।

रणनीतिक हितों पर आंच नहीं

ताजा अधिनियम का मूल उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा तंत्र पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखना है। भले ही यह क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुल रहा है, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण कार्य संप्रभु निगरानी में ही रहें।

विनय झैलावत
पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता

हाल ही में संसद द्वारा पारित 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति)' विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में असैन्य परमाणु क्षेत्र से संबंधित सभी कानूनों को शामिल किया गया है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अब तक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 2010 के अंतर्गत आता रहा है। 1962 के अधिनियम ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। इससे सरकार को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा को विनियमित करने का अधिकार मिला और परमाणु सामग्री के अनुसंधान, विकास और उपयोग पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। नए अधिनियम में भारत के परमाणु कानूनी ढांचे को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया गया है। इससे नियामक निगरानी के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी संभव हो सकेगी।

इसमें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। यह अधिनियम निजी कंपनियों को भारत के परमाणु क्षेत्र में, संयंत्र संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और परमाणु ईंधन निर्माण, जिसमें 'यूरेनियम-235 का रूपांतरण, शोधन और संवर्धन' शामिल है, में भाग लेने की अनुमति देता है। हालांकि, 'कुछ संवेदनशील गतिविधियां' पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहेंगी। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने विद्युत मिश्रण में एक स्थिर भूमिका बनाए रखी है और अब विस्तार के लिए तैयार है। वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विकसित किए जा रहे स्वदेशी 700 मेगावाट और 1000 मेगावाट रिएक्टरों के साथ, 2031-32 तक क्षमता 22 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। 'शांति' अधिनियम भारत की परमाणु यात्रा के अगले चरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत को उम्मीद है कि वह 2033 तक स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) चालू कर देगा। सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इस दौरान विदेशी निर्माता नवगठित निजी संस्थाओं को अपनी तकनीकें आक्रामक रूप से बेचेंगे। परमाणु क्षमता स्थापित करने की इच्छुक भारतीय निजी कंपनियां और औद्योगिक उपभोक्ता लगभग एक दशक तक अप्रमाणित स्वदेशी डिजाइनों का इंतजार नहीं करेंगे। उन्हें अन्य बाजारों में पहले से ही व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे विदेशी विकल्प कम जोखिम भरे प्रतीत हो सकते हैं। एकल-संचालक मॉडल परमाणु ऊर्जा के विस्तार में मूलभूत बाधा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अन्य सभी विकास प्राथमिकताओं के साथ पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। शांति अधिनियम परिष्कृत नीतिगत संरचना का उदाहरण है, जिसमें चार स्तरीय न्यायनिर्णय तंत्र है। यह नियामक निश्चितता सुनिश्चित करता है। यह एक सूक्ष्म दायित्व ढांचा है, जो सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखते हुए निवेश योग्य परियोजनाएं तैयार करता है। इसमें रणनीतिक सीमांकन है, जो व्यावसायिक अवसरों और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

हालांकि परमाणु परियोजनाओं के समय-सीमा निर्धारण में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। रिएक्टर निर्धारित समय से वर्षों देरी से चालू होते हैं, जिससे लागत में वृद्धि आम बात है। 'शांति' अधिनियम इन चुनौतियों का समाधान नहीं करता, बल्कि दूसरों को उन क्षेत्रों में प्रयास करने के लिए कानूनी गुंजाइश प्रदान करता है। ऊर्जा परिवर्तन के इस चरण में देश अपने परमाणु ढांचे की नींव की समीक्षा कर रहा है, ताकि यह वर्तमान जरूरतों और भावी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो सके। दशकों से, भारत के परमाणु कार्यक्रम की तकनीकी क्षमताएं मजबूत हुई हैं। इसके स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य व्यापक हुए हैं। इन सबने एक ऐसे आधुनिक, व्यापक कानून की आवश्यकता पैदा की है, जो आज की वास्तविकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करे।

'शांति' अधिनियम एक श्रेणीबद्ध जवाबदेही ढांचा स्थापित करता है, जिसके तहत, संचालकों की जवाबदेही की सीमाएं विधेयक की दूसरी अनुसूची में विस्तार से बताई गई हैं। यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान और अन्य शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है। यह अनुसंधान, विकास और नवाचार से संबंधित कार्यों जैसी सीमित गतिविधियों के लिए लाइसेंस में छूट प्रदान करता है। यह अधिनियम सुरक्षा, सुरक्षा उपायों, गुणवत्ता आश्वासन और समन्वित आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रणालियों में सुधार करता है। इसके अलावा, यह अधिनियम परमाणु गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार को अनन्य अधिग्रहण अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम विवादों के निवारण के लिए एक परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिसे अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त मामले के तहत अपील सुनने का अधिकार है।

यह अधिनियम केंद्र सरकार को परमाणु क्षति से संबंधित मुआवजे के दावों के निपटारे के लिए दावा आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार देता है और गंभीर मामलों को संभालने और समय पर निपटारे के लिए एक समर्पित आयोग का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा तंत्र पर रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखना है। भले ही यह क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुल रहा है, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण कार्य संप्रभु निगरानी में ही रहें। कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण और संस्थागत निगरानी को मजबूत करके यह अधिक कुशल, नवोन्मेषी और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा तंत्र की नींव रखता है। यह अधिनियम स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा के विस्तार का समर्थन करने के साथ यह सुनिश्चित करता है कि रणनीतिक हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रेंज काफ्का

प्रेम एक भ्रम है, जो दूरी में फलता है, लेकिन निकटता में मुरझा जाता है। प्रेम महज एक भावना नहीं है, यह जटिल है। यह आनंद है, लेकिन यातना भी, निकटता है, लेकिन दूरी भी। जीवन है, लेकिन मृत्यु भी।

प्रेम एक भ्रम ही तो है

मैं निरंतर कोई अवर्णनीय बात समझाने और बताने का प्रयास करता रहा हूं, जिसे मैं केवल अपनी आत्मा में महसूस करता हूं और जिसका अनुभव केवल आत्मा के स्तर पर ही हो सकता है। दरअसल, यह वही भय है, जो हर चीज में फैला हुआ है। जरूरी नहीं कि यह भय केवल भय ही हो, यह उस चीज की लालसा भी हो सकती है, जो भय से परे हो। यह एक तरह की अपूर्णता का एहसास है और जब कोई अकेला होता है, तो उसे हर पल इसे सहना पड़ता है। मुमकिन है कि यह अतिशयोक्ति या झूठा एहसास हो। पर एकमात्र सत्य तो यह तड़प ही है। तड़प का सत्य क्या वाकई सत्य है या कई झूठी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति? मेरी बात सुनने में विकृत लग सकती है, लेकिन यही है, जो मैं महसूस कर रहा हूं। जब कोई कहता है कि तुम ही हो, जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, तो यह कहना झूठ भी हो सकता है। जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी तड़प एक छुरी है, जो मुझे भीतर से आहत कर रही है, तो यह सच है। यही प्रेम है। हालांकि मैं जानता हूं कि चाहे तुम कितना भी चाहो, लेकिन मुझसे प्रेम नहीं कर सकतीं। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है, उससे शायद तुम दुखी भी हो, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारा प्यार, तुम्हें तुमसे दूर कर सकता है। मैं ऐसा ही हूं। मेरी दुनिया बिखर रही है। मैं बिखरने का शोक नहीं मना रहा, मैं तो हमेशा से बिखरता ही रहा हूं। मैं समझता हूं कि कोई दूर बैठे किसी के बारे में सोच सकता है और पास बैठे किसी को थामे रह सकता है। इसके अलावा, सबकुछ मानवीय शक्ति से परे है। सोचता हूं कि काश हम साथ में होते। साथ जीते, साथ मरते। पर यह इच्छा ही है। जब मैं छोटा था, तब अंकगणित की कक्षा में शिक्षक मेरी नोटबुक को ध्यान से पलट रहा होता, और मेरी इच्छा होती कि मैं किसी तरह कक्षा से बाहर आ जाऊं, उस जानी-पहचानी दुनिया में, जहां गणित की कक्षा जैसा तनाव न होता। लेकिन यह इच्छा ही रह गई, कभी पूरी नहीं हुई। सोचता हूं कि तुम्हें पत्र लिखूं, लेकिन इसका मतलब अज्ञात के सामने खुद को उजागर करने जैसा होगा। मुझे अज्ञात के सामने खुद को परोसना अच्छा नहीं लगता। इस अज्ञात तत्व को खत्म करने के लिए ही मनुष्य ने रेलगाड़ी, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज के आविष्कार किए। लेकिन अज्ञात की शक्तियां मजबूत हैं, इसलिए ही डाक के बाद तार, टेलीफोन, बेतार के तार का आविष्कार हुआ। पत्र लिखना मुझे कमजोर और असुरक्षित बनाता है, जो मैं होना नहीं चाहता। प्रेम मेरे लिए एक सपना है, जो जागते ही टूट जाता है। हम दूर हैं, लेकिन जो साथ होते हैं, क्या उनमें प्रेम होता है? प्रेम एक भ्रम है, जो दूरी में फलता है, लेकिन निकटता में मुरझा जाता है। सच्चा प्रेम आत्म-समर्पण है, लेकिन वह समर्पण हमें नष्ट भी कर सकता है। प्रेम महज एक भावना नहीं है, यह जटिल है। यह आनंद है, लेकिन यातना भी, निकटता है, लेकिन दूरी भी। जीवन है, लेकिन मृत्यु भी।

'लेटर टु मिलेना' पुस्तक के अनूदित अंश

असुरक्षा को स्वीकार करें

सूत्र

प्रेम केवल सुख का मिलन नहीं, बल्कि स्वयं को खोकर सत्य को पाने की तड़प है। प्रेम महज एक भावना नहीं है, यह जटिल है। यह आनंद है, लेकिन यातना भी, निकटता है, लेकिन दूरी भी। अपने भीतर की असुरक्षा को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि वहीं अनंत संभावनाएं जीवित रहती हैं।

दूसरा पहलू

वह कुआं अपने अंदर न जाने कितने आख्यानों को समेटे हुए है। यदि आप महाकवि सूरदास के महात्म्य को नहीं जानते तो कुआं समझ से परे है।

सूरदास की दिव्य दृष्टि और कुएं में गिरने का आख्यान

भूपेंद्र कुमार

सूरकुटी महाकवि सूरदास की कर्मस्थली है। यही वह स्थल है, जहां वल्लभाचार्य ने सूरदास को ब्रह्म संबंध का ज्ञान दिया।

सूरकुटी पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपकी नजर सामने मौजूद कुएं पर पड़ेगी। सूरदास इसी कुएं में गिर पड़े थे। वे अपने आराध्य को पुकारने लगे। सूरदास को बचाने भगवान कृष्ण आए और उन्हें दिव्य दृष्टि मिली।

नीरव और शांत वातावरण में वक्त भी जैसे ठहर गया है। जनवरी की अलसाई-सी धूप व नीला दमकता आसमान। जंगल के बीच बनी पगडंडी और दोनों तरफ शांत तपस्या में लीन वृक्ष। सहसा पगडंडी खत्म होती है और सामने है... वह कुआं। अपने अंदर न जाने कितने आख्यानों को समेटे हुए। आगरा-मथुरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर चलते हुए दाईं ओर लगा 'सूर सरोवर' का बोर्ड ध्यान खींचता है। लेकिन अगर आप महाकवि सूरदास के महात्म्य को नहीं जानते , तो इस पवित्र स्थान को भी नहीं जान पाएंगे। करीब एक किलोमीटर चलकर रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। दाईं तरफ जाएंगे तो जंगल से गुजरते हुए सूरकुटी पहुंच जाएंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के पास आगरा के रुनकता गांव में माना जाता है। कहीं-कहीं यह भी जानकारी दी गई है कि उनका जन्म सीही गांव में हुआ था, जो दिल्ली या फरीदाबाद में है। पर इससे सब एकमत हैं कि उनकी कर्मस्थली रुनकता के पास कीठम में यमुना का गऊ घाट रही। लगभग पांच सौ साल पहले का वह समय कैसा होगा, जब इस आख्यान ने जन्म लिया होगा। सूरदास का नाम आते ही कृष्ण स्मरण में आते हैं। सूरकुटी महाकवि सूरदास की कर्मस्थली है। यह वह स्थल है, जहां वल्लभाचार्य ने सूरदास को ब्रह्म संबंध का ज्ञान दिया, यानी प्रेम के माध्यम से ईष्ट को पाना। उन्होंने सूरदास से श्रीकृष्ण लीला के पद गाने के लिए कहा।

जैसे ही जंगल से निकलकर सूरकुटी पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपकी नजर सामने ही मौजूद कुएं पर पड़ेगी। सूरदास इसी कुएं में गिर पड़े थे। वे अपने आराध्य को पुकारने लगे। सूरदास को बचाने भगवान कृष्ण आए और उन्हें दिव्य दृष्टि मिली। कान्हा आए और कहा, बाबा कहां नीचे गिरे हो, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। फिर हाथ छुड़ाकर जाने लगे, तो सूरदास ने कहा, *कर छुटकाए जात हो, निबल जानि कर मोहि, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए।* यानी आप मेरा हाथ छोड़कर चले जाते हैं, मुझे निर्बल जानकर, मेरे हृदय से जाएं तो आपको बलशाली मानूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़कर दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। कृष्ण के बालरूप का अद्भुत चित्रण इसे साबित करता है, *मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी।* सूरकुटी की मौजूदा हालत बहुत अच्छी नहीं है। यहां दृष्टिबाधितों के लिए विद्यालय भी है। पास में ही सूरदास की प्रतिमा और मंदिर है। सामने है यमुना की धारा और गऊघाट। वही जहां आंखें नहीं होने पर भी उन्होंने कृष्ण की अद्भुत बाललीला देखी। यही तो है दिव्य दृष्टि का आख्यान।

आंकड़े

पर्यावरण और प्रगति

भारत पर्यावरण व प्रगति के संतुलन में नेतृत्व कर रहा है। रेलवे ने व्यापक विद्युतीकरण के माध्यम से हरित परिवहन की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है।

स्विट्जरलैंड	100
भारत	99.2
चीन	82
स्पेन	67
ब्रिटेन	39

आंकड़े रेलवे विद्युतीकरण के प्रतिशत में। | स्रोत : इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज

सभी श्रद्धालु पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सावता माली खेती के कारण नहीं जा सके। अंत में स्वयं भगवान अपने भक्त से मिलने खेत पर पहुंचे।

सच्ची भक्ति भाव की होती है

अंतर्यात्रा
संकलित

संत सावता माली अत्यंत सरल, निष्कपट और कर्मनिष्ठ भक्त थे। उनका जीवन खेत-खलिहान और प्रभु-स्मरण में ही व्यतीत होता था। वह पंढरपुर के विठोबा के अनन्य उपासक थे। एक बार आषाढ़ी एकादशी का पावन अवसर आया। सभी श्रद्धालु पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सावता माली का हृदय भी दर्शन के लिए व्याकुल हुआ, किंतु खेत में बोई गई फसल को छोड़कर जाना संभव न था।

उन्होंने मन को समझाया और हल उठाकर पुनः खेत में लग गए। उनके अधरों पर नामस्मरण था और नेत्रों में विठ्ठल की छवि।

मिट्टी से सने हाथों में भी भक्ति की सुवास थी और श्रम के प्रत्येक कण में समर्पण झलकता था। उसी समय एक दिव्य प्रकाश खेत की मेड़ पर प्रकट हुआ। सावता ने दृष्टि उठाई, तो देखा कि स्वयं विठोबा खड़े हैं। प्रभु ने कहा, 'सावता, तुम दर्शन को नहीं आ सके, तो देखो मैं ही तुम्हारे पास चला आया। जो कोई अपने कर्म में स्थित रहकर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं दूर नहीं रहता।'

सावता माली की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह भूमि पर दंडवत हो गए और भावविभोर होकर प्रभु के चरणों का स्पर्श किया।

उस दिन उन्हें अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति स्थान की नहीं, भाव की होती है; और ईश्वर अपने भक्त के श्रमस्थल को ही तीर्थ बना देते हैं।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 16 फरवरी, 1953

केन्या में पुलिस का आतंक तथा जातिभेद का नग्न तांडव

केनिया में पुलिस का आतंक तथा जातिभेद का नग्न तांडव

केन्या में पुलिस के आतंक और जातिभेद के खुले तांडव के खिलाफ वहां के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के लिए अब सिरदर्द बन गया है। ब्रिटेन केन्या से हर कीमती चीज लेना चाहता है।

मोहल्ले का झगड़ा नहीं दलित विमर्श

दलित-विमर्श समकालीन विमर्शों का मूल है। सभी विमर्शों को मिला लें, तो यह अस्सी फीसदी से अधिक आबादी की रचनात्मक अभिव्यक्ति है।

श्यौराज सिंह बेचैन

मुद्दा

विगत माह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 'हिंदी साहित्य समकालीन विमर्श' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में साहित्य, सिनेमा, सांस्कृतिक और राजकीय सेवाओं में वंचितों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। इन पंक्तियों के लेखक द्वारा बीज वक्तव्य देने के बाद हिंदू कॉलेज से सेवानिवृत्ती प्रोफेसर राय साहब ने हिंदी साहित्य में चार दशकों से चल रहे विमर्शों को इन मुहावरों में समेट दिया, 'स्त्री विमर्श घरों के झगड़े हैं और दलित-आदिवासी विमर्श मोहल्लों के झगड़े हैं।' इसलिए संवाद स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि से ही शुरू करना पड़ा।

विविधता पूर्ण अभिव्यक्तियां विमर्शों की आत्मा हैं। दलित-विमर्श समकालीन विमर्शों का मूल है। सभी विमर्शों को मिला कर देखें, तो यह देश की अस्सी फीसदी से अधिक आबादी की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। हालांकि संत साहित्य में जन्म-जाति को लेकर समता, स्वतंत्रता मूलक मूल्यों की पृष्ठभूमि है, जिसमें ईश्वर की दृष्टि से समानता की बात होती है। यह विमर्श अमेरिका और अफ्रीका के 'ब्लैक पैंथर' से मराठी के 'दलित पैंथर' में आया और हिंदी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उद्देश्य मनुष्य से मनुष्य की मुक्ति के लिए अन्याय और अपमान का अंत कर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समता मूलक सभ्य समाज बनाना है।

आज से ठीक तीस साल पहले 25 फरवरी, 1996 को संपादक मूलचंद गौतम की पत्रिका की ओर से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 'परिवेश सम्मान' दिया गया था। तब मुख्य अतिथि काशीनाथ सिंह ने कहा था-'यदि दलितों द्वारा लिखा हुआ ही दलित साहित्य माना जाएगा, तो घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना पड़ेगा।' यह सुनकर वाल्मीकि विचलित थे। इसे परंपरा से चले आ रहे हिंदी लेखकों के संस्कारों में समाई वर्चस्व की भावना या सामंती स्वभाव की ठसक भी कह सकते हैं।

डॉ. आंबेडकर ने अपनी पुस्तक 'अनटचेबल्स' में अशरीरी अस्पृश्यता को रेखांकित किया। यह दासप्रथा से भी अधिक अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। संविधान ने अस्पृश्यता निवारक कानून अमल में लाकर ऐसी कुप्रथाओं का अंत कर दिया। लोकतांत्रिक स्वभाव के अनुसार, नैतिक उपक्रम करने की वंचितों की दस्तक एक जैसी रही है।

विमर्श का विस्तार साहित्य और सिनेमा में एक जैसा दिखाई पड़ता है। गांधीवादी प्रभाव में बनी 'अछूत कन्या' जैसी फिल्में संविधान और आंबेडकर के प्रभाव तक आते-आते आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15', अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेई की 'आरक्षण' तक आया दिखता है। कालांतर में मराठी दलित निर्देशकों ने सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। नागराज मंजुले की 'सैराट' (2016) और 'फंड्री' फिल्म के बाद 'नीरज घेवान' के निर्देशन में आई 'होम बाउंड' ऑस्कर तक पहुंची है। लेकिन नीरज कहते हैं, 'आज भी किरदारों के नाम उच्च जाति सूचक ही होते हैं।' दलित-आदिवासियों को लेकर मुस्लिम निर्देशकों के नजरिये में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें भी दलितों में नायक दिखाई नहीं पड़ते। वे भी 'लगान' में 'कचरा' के दम पर ऑस्कर पाना चाहते हैं।

साहित्य और सिनेमा की जो प्रवृत्तियां लोकतंत्र की प्रक्रिया में आड़े आती हैं, उनमें खास है परंपरागत जाति पूर्वाग्रह। यह इस हद तक गहरे पैठा कि, न केवल नीरज, बल्कि दलित प्रतिभाएं पहले भी जाति छिपाने को विवश होती रही हैं। डॉ. आंबेडकर को जातिगत पूर्वाग्रह का दंश झेलना पड़ा था। 1960 में 'दया पवार' ने 'अछूत' आत्मकथा में हिकारत के प्रसंगों की भरमार कर दी। 'सारिका' मई 1975 में कमलेश्वर ने बाबूराव बागुल का लेख छाप कर हिंदी मानस की गहरी तंद्रा तोड़ दी थी। जब नीरज घेवान कहते हैं कि सिनेमा जगत में मैंने 35 साल तक अपनी जाति छिपा कर काम किया, तो लगता है हम फिर वहीं खड़े हैं। डॉ. आंबेडकर के आधुनिक विचारों ने मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि और स्थिति में भी समान होने का प्रश्न बनाया। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, 'मेरा अनुभव कह रहा है कि जिन लोगों में कोई दुर्गुण नहीं होता, उनमें सद्गुण भी बहुत कम होते हैं।' लिंकन के अनुभव की रोशनी में देखें, तो इतिहास के कई किरदार स्मरण हो आते हैं।

हिंसक अंगुलिमाल डाकू बुद्ध की शिक्षाएं पाकर हिंसा-डकैती छोड़कर भिक्षु 'अर्हत' हो जाता है, 'रत्नाकर' लुटेरे से महर्षि-आदिकवि हो जाते हैं। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हजारों योद्धाओं की लाशों पर से गुजर कर प्रायश्चित करते हैं और अंततः 'बुद्ध' की शरण में जाकर उनकी शिक्षाओं के प्रचारक बन जाते हैं। पर क्या हम आज यह सोच सकते हैं कि यूक्रेन-रूस युद्ध पुतिन और जेलेंस्की को बौद्ध बना देगा, और श्रेय लेने को बेताब ट्रंप शांति की कोई वजह भी कायम करेंगे? सिद्धार्थ और देवदत्त के बाल्यकाल की कथा बताती है, देवदत्त ने 'हंस' को तीर मारा था और बड़े भाई सिद्धार्थ ने न केवल हंस का तीर निकला था, अपितु उसकी तीमारदारी कर जान बचाई थी। वही 'बुद्ध' विश्व में शांति और अहिंसा के प्रतीक बने।

हम दुनिया के डाटा को भारत में रखे जाने का निमंत्रण दे रहे : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा-केवल डिजिटल इस्तेमाल नहीं, नेतृत्व भी जरूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में तकनीक का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब केवल डिजिटल अपनाना ही काफी नहीं है, बल्कि डिजिटल नेतृत्व जरूरी है। जैसे यूपीआई के जरिये हमने डिजिटल पेमेंट में नेतृत्व दिखाया, वैसे ही अगली लहर डाटा और एआई की है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा, डाटा सुरक्षा के लिए डिजिटल निजी डाटा संरक्षण कानून लाया गया। दक्षता के लिहाज से भारतीय युवाओं की पहचान दुनिया में पहले से मजबूत है। अब जरूरत है उस बुनियादी ढांचे की जो एआई को चलाता है और वो है डाटा सेंटर। एआई को कंप्यूटिंग पावर और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज क्षमता बढ़ाकर हम भारतीय एआई इकोसिस्टम की नींव रख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों ने निवेश की घोषणाएं की हैं। बजट के टैक्स इंसेंटिव निवेश को तेज करेंगे, लागत घटाएंगे और भारत को डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसका परिणाम भी युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के रूप में सामने आएगा। हम दुनिया के डाटा को भारत में रहने का निमंत्रण दे रहे हैं। केंद्रीय बजट के बारे में पीएम ने कहा, खर्च ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पादकता बढ़े और यह हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता रही है। ज्यादा पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे और पूंजी निवेश पर हमारे फोकस को दिखाता है जो दीर्घकालिक विकास के मजबूत चालक हैं। वित्त वर्ष 2027 के बजट में पूंजीगत व्यय को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो 2013 की तुलना में पांच गुना अधिक है। यह अल्पकालिक लोकलुभावनवाद के बजाय उत्पादकता, रोजगार और भविष्य की आर्थिक क्षमता सृजित करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के एक सचेत रणनीतिक निर्णय को दर्शाता है। एजेंसी

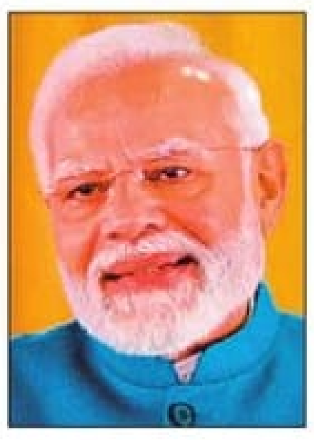

हर फैसला महिला कल्याण पर आधारित

पीएम मोदी ने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए मेरी सरकार के हर निर्णय में महिलाओं का कल्याण सर्वोपरि रहता है। पिछले दस वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखा है।

रक्षा बजट 15 फीसदी तक बढ़ाया

मोदी ने कहा, पिछले दशक में हमने रक्षा क्षेत्र में जो सुधार किए हैं, उनके लाभ ऑपरेशन सिंदूर में स्पष्ट दिखे। इसलिए, रक्षा बजट, आधुनिकीकरण आदि, ये सभी हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से हैं और इन्हें किसी विशेष मुद्दे से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना होगा। इसलिए इस वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो पिछले बजट से 15 प्रतिशत अधिक है। यह किसी भी मंत्रालय या विभाग को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। पीएम ने कहा, मेरी सरकार पहले दिन से ही स्पष्ट रही है कि वह देश की रक्षा बलों का समर्थन करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। विश्व में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे देश के रूप में, भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपने रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप करे।

हमारे युवाओं के लिए बड़े अवसर... ये समझौते ऐसे समय हुए हैं जब विनिर्माण और सर्विस दोनों सेक्टर नई छलांग के लिए तैयार हैं। इनके जरिये युवाओं के लिए अवसरों की एक बड़ी दुनिया खुलेगी। मुझे भरोसा है कि हमारी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दुनिया पर असर छोड़ेगी और जब हमारे युवा अपने काम से भागीदार देशों के आम लोगों के मन में भरोसा जगा देंगे, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मैं कभी संतुष्ट नहीं होता... प्रधानमंत्री ने कहा, स्वभाव से मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। मेरा मानना है कि सार्वजनिक जीवन में एक निश्चित रचनात्मक बेचैनी, अधिक करने की निरंतर ललक, तेजी से सुधार करने की इच्छा और बेहतर सेवा करने की चाहत आवश्यक है। हालांकि, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सुधार एक्सप्रेस की यात्रा में हासिल की गई प्रगति के पैमाने को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है।

सोच-समझकर की जनसंपर्क की हताश कोशिश : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साक्षात्कार को जनसंपर्क की सोच-समझकर की गई हताश कोशिश करार दिया। पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, व्यापार समझौते पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण विपक्ष की घेराबंदी और हमलों से घिरे प्रधानमंत्री अब सुर्खियां बटोरने की अपनी पसंदीदा रणनीति का सहारा ले रहे हैं।

रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस साल का बजट पूरी तरह विफल रहा है और बौद्धिक थकावट के सभी संकेत दिखाता है। इसपर बाजारों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और न ही इसने निवेशकों को प्रभावित किया है। इसलिए, उन्हें बजट पेश होने के दो सप्ताह बाद साक्षात्कार देना जरूरी लगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हमेशा की तरह, मोदी के अंदाज में कुछ ऐसे बयान हैं जिनका वास्तविकता में कोई खास मतलब नहीं है। मोदी लाखों किसानों के साथ किए गए धोखे और अन्य समझौतों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साक्षात्कार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और हताशा भरा जनसंपर्क अभियान है। प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके भी हैं। ब्यूरो

न्यूज डायरी

सीएम मान की तबीयत बिगड़ी, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब होने पर रविवार को उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार संगरूर के धुरी में कार्यक्रम के दौरान उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया जिसके बाद एहतियातन अस्पताल लाया गया। अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि मुख्यमंत्री को नियमित जांच के लिए लाया गया था। सभी आवश्यक परीक्षण किए गए हैं और उनकी स्थिति स्थिर है। अत्यधिक थकान की शिकायत के चलते उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। ब्यूरो

मणिपुर : दो महिलाओं समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर में सुरक्षाबलों ने दो महिलाओं समेत तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। सुरक्षा बलों ने शनिवार को तेंगनौपाल जिले के सनराइज ग्राउंड के पास से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की दो महिला कैडरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान अकोइजम सखेनबी (23), चोंगथम हेमबेबी (17) और इंगुडम इंगोचा सिंह (50) के रूप में हुई है। सिंह के पास से पांच कारतूसों से भरी .32 पिस्टल भी बरामद की गई। ब्यूरो

निजी उड़ानों और बिना नियंत्रण वाले हवाईअड्डों की होगी गहन जांच

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार गैर-नियमित उड़ान संचालकों और बिना नियंत्रण वाले हवाईअड्डों की उड़ान व्यवस्था का गहन अध्ययन कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। यह कदम 28 जनवरी को पुणे के बारामती में हुए विमान हादसे के बाद उठाया गया है। ब्यूरो

मेघालय कोयला खदान विस्फोट : तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित

शिलांग। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में 5 फरवरी को अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जस्टिस आरएस चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह उत्तराखंड हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एच नोंगप्लुह और पूर्व आईएएस अधिकारी पीएस दखर इसके सदस्य हैं। एजेंसी

आज फिर बदलेगा मौसम...पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी होने के आसार

डोडा में हिमस्खलन...दर्जनों वाहन फंसे मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने से बढ़ी गर्मी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हिमस्खलन हुआ है, जिसके चलते भद्रवाह-पठानकोट अंतरराज्यीय मार्ग पर यातायात ठप हो गया है और दर्जनों वाहन फंस गए। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव अगले 24 घंटे में मौसम करवट ले सकता है। इससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, पंजाब और हरियाणा समेत मैदानी राज्यों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। दक्षिण भारत में एक नया चक्रवाती हवाओं का झोंका मौसम को प्रभावित कर रहा है और इसके प्रभाव से तमिलनाडु और केरल में बारिश हो रही है।

भद्रवाह के पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा ने बताया कि हिमस्खलन भद्रवाह कस्बे से लगभग 18 किलोमीटर दूर थंथेरा और गुलदांडा के बीच शाम करीब 5 बजे हुआ। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गुलदांडा एक प्रसिद्ध शीतकालीन पर्यटन स्थल है और हिमस्खलन के समय पर्यटकों को ले जा रहे 250 से अधिक वाहन इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जो हिमस्खलन के कारण फंस गए हैं। सड़क साफ करने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को लगाया गया है। इस बीच, कश्मीर घाटी में रविवार को दिन में तेज धूप रही। इससे दिन का पारा सामान्य से आठ डिग्री तक अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा अपडेट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 16 फरवरी से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू होने का अनुमान है। यह प्रभाव 17-18 फरवरी तक और बढ़ सकता है। 17-19 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में और 17 और 18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

भद्रवाह-पठानकोट अंतरराज्यीय मार्ग पर हिमस्खलन के बाद सड़क पर जमा बर्फ को हटाती बीआरओ की मशीनें।

उत्तराखंड के पांच जिलों में अलर्ट... *आईएमडी के अनुसार, 17 फरवरी से उत्तराखंड के 5 जिलों रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत कई अन्य स्थानों पर बर्फबारी जारी रहने से न्यूनतम तापमान माइनस 12 से माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों तक सर्दी का एहसास बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और बर्फ गिरने से मौसम का मिजाज बदलेगा और ताबो, लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी में बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे शीत दिवस और कोहरे की स्थिति रहेगी।*

एमपी में भी गरज के साथ बारिश

मैदानी राज्यों की बात करें तो 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं, 18 और 19 फरवरी को मध्य प्रदेश में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान और बिहार में मौसम आमतौर पर साफ और शुष्क रहेगा, हालांकि न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।

पूर्वोत्तर में हल्की बारिश की संभावना... पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में कम से कम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी और उसके बाद उत्तर-पश्चिम भारत में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। अगले 24 घंटों में कम से कम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और उसके बाद पश्चिमी भारत में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे तमिलनाडु और केरल के दक्षिण जिलों में बारिश हो रही है। 16 फरवरी को आंधी-तूफान नुमा हवाओं, बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश जारी रह सकती है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 10 से 15 सेमी. के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। फिलहाल, दक्षिण में धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

अब भारत में बनेगी लड़ाकू विमान राफेल की घातक हैमर मिसाइल

कल होने वाले भारत-फ्रांस रक्षा संवाद में होगा समझौता मिसाइल पहाड़ी इलाकों में छिपे बंकरों को भेदने में भी माहिर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के निर्माण को लेकर इस सप्ताह अहम समझौता होने जा रहा है। इस समझौते के तहत राफेल की घातक हैमर मिसाइलें अब भारत में बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वॉट्रिन के बीच बंगलूरू में मंगलवार को होने वाले रक्षा संवाद के दौरान हैमर मिसाइलों के संयुक्त निर्माण का समझौता होगा।

भारत-फ्रांस के बीच छठा वार्षिक रक्षा संवाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी अगले 10 सालों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। फ्रांस की रक्षा कंपनी साफ्रान और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) इस मिसाइल के निर्माण के लिए हाथ मिलाएंगी। सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल होगा। हैमर मिसाइल दुश्मन के बंकरों, ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों को 70 किलोमीटर दूर से भी पूरी सटीकता से तबाह कर सकती है। फिलहाल वायुसेना अपने राफेल विमानों में फ्रांस से आयातित हैमर मिसाइलों का उपयोग कर रही है। भारत में इनका निर्माण होने से मिसाइल की लागत में भारी कमी आएगी। पहाड़ी इलाकों में छिपे लक्ष्यों को भेदने में माहिर यह मिसाइल जीपीएस के बिना भी काम कर सकती है। इसे जाम करना लगभग नामुमकिन है।

एच125 हेलिकॉप्टर... दोनों मंत्री कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच125 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) की फाइनल असेंबली लाइन के आभासी उद्घाटन पर भी मौजूद रहेंगे। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे।

रक्षा सहयोग में वृद्धि... वार्षिक रक्षा संवाद के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और औद्योगिक साझेदारी का विस्तार करेंगे। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के प्रतिष्ठानों में अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती संबंधी घोषणा भी की जा सकती है।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बैठक

अक्तूबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद यह कैथरीन वॉट्रिन की पहली भारत यात्रा है। यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत ने हाल ही में 114 राफेल लड़ाकू विमानों और कई स्केल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद के अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह बैठक औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करेगी।

द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सहयोग मजबूत आधार... दोनों देशों के संबंधों में रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। साल 2024-25 से ही यह दीर्घकालिक संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इधर जनवरी 2024 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। हाल ही में भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी ने यूरोपीय देशों के साथ सामूहिक सहयोग को नई दिशा दी है।

- भारत और फ्रांस तीन प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास- थल सेना के लिए शक्ति, नौसेना के लिए वरुण और वायुसेना के लिए गरुड़ का आयोजन करते हैं। इन साझा अभ्यासों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय मजबूत हुआ है।

संसद परिसर में लावारिस कुत्ता लाने पर कांग्रेस सासंद रेणुका को विशेषाधिकार हनन नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी को संसद परिसर में लवारिस कुत्ता लाने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने दो भाजपा सांसदों की शिकायत पर विचार शुरू कर दिया है और उनसे 23 फरवरी तक जवाब मांगा है। यह शिकायत भाजपा सांसद बृज लाल और इंदु बाला गोस्वामी ने नियम 188 के तहत दी थी। आरोप है कि 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान कुत्ता लाने पर आपत्ति जताने वाले सदस्यों के बारे में कांग्रेस सांसद रेणुका ने कहा था कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं, कुत्ते नहीं। भाजपा सांसदों ने अपनी शिकायत में कहा कि रेणुका की यह टिप्पणी सांसदों की गरिमा के खिलाफ है और इससे संसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। ब्यूरो

शीत सत्र में लावारिस कुत्ता लेकर जाने पर हुआ था विवाद

तीन महीने तक निकासी के बाद एफपीआई ने बाजार में डाले 19,675 करोड़

नई दिल्ली। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने फरवरी के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में 19,675 करोड़ रुपये डाले हैं। लगातार तीन महीने की भारी बिकवाली के बाद एफपीआई ने खरीदारी की है।

2025 में 1.66 लाख करोड़ की बिकवाली

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी में भारतीय बाजार से 35,962 करोड़, दिसंबर में 22,611 करोड़ और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपये निकाले थे। कुल मिलाकर, एफपीआई ने 2025 में भारतीय शेयरों से शुद्ध रूप से 1.66 लाख करोड़ रुपये (18.9 अरब डॉलर) की निकासी की है। यह एफपीआई के प्रवाह की दृष्टि से सबसे खराब साल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई फरवरी के 11 कारोबारी सत्रों में से सात में शुद्ध खरीदार रहे, जबकि चार सत्रों में बिकवाली की। इसके बावजूद एफपीआई ने इस महीने शुद्ध रूप से 1,374 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। एजेंसी

30-34 साल की सेवा में सिर्फ एक पदोन्नति, सीआईएसएफ के 500 निरीक्षकों ने की समीक्षा की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 500 से अधिक निरीक्षकों ने पदोन्नति में लंबे समय से हो रहे ठहराव को लेकर बल मुख्यालय से न्यायसंगत और समयबद्ध कैडर समीक्षा की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 30 से 34 वर्षों की सेवा में केवल एक ही पदोन्नति मिलती है, जिससे उनके कैरियर में ठहराव की स्थिति बन गई है।

कहा, उनके सेवाकाल में महज एक पदोन्नति मिलती है, जिससे ठहराव की स्थिति बन गई है

इन निरीक्षकों ने 2 फरवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें सीआईएसएफ की कैडर समीक्षा तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि वे उपनिरीक्षक के रूप में भर्ती होते हैं और निरीक्षक पद तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद सहायक कमांडेंट (ग्रुप 'ए' गजटेड रैंक) तक पदोन्नति में भारी देरी होती है। सीआईएसएफ में इस समय करीब 3,000 निरीक्षक और लगभग 17,000 उपनिरीक्षक हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पदोन्नति कोटा में व्यवस्थित कमी, अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तुलना में रैंक असमानता और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमी के कारण स्थिति गंभीर हुई है। निरीक्षकों ने कहा, अन्य बलों के अधिकारी उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं। एजेंसी

अमेरिकी व्यापार समझौता किसानों के साथ विश्वासघात : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने पीएम से सोशल मीडिया पर पूछे कई सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री से कई सवाल किए और किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि यह मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत किसी दूसरे देश को अपने कृषि क्षेत्र पर दीर्घकालिक नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दे रहा है।

एक्स पर राहुल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी) आयात करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? उन्होंने पूछा कि अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे। ब्यूरो

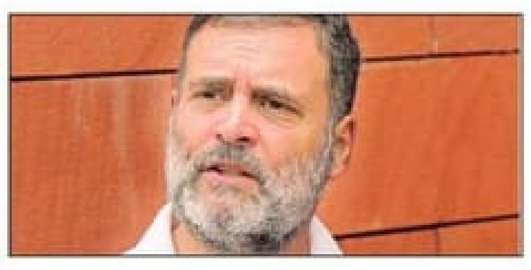

राहुल को देश को बदनाम करने की आदत : भाजपा...नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता को सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की खरतनाक आदत है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, राहुल गांधी की राजनीति पलटू राजनीति है। व्यापार वार्ता से पहले राहुल ने कहा, मोदी डरे हुए हैं।

चिंताजनक | 88 फीसदी युवाओं ने बदलाव किया महसूस, 94% भविष्य को लेकर चिंतित

जलवायु संकट की चिंता को लेकर युवाओं में बढ़ रहा आक्रोश

अमर उजाला नेटवर्क

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरणीय चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालने वाली वैश्विक समस्या बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ताजा रिपोर्ट और भारत में किए गए जनमत सर्वेक्षण से सामने आया है कि ईको एंजायटी यानी जलवायु से जुड़ी चिंता 21वीं सदी की पहली पीढ़ी के बीच तेजी से फैल रही है। दुख, निराशा, असहायता और गुस्से जैसी भावनाएं युवाओं में आम होती जा रही हैं, जबकि 94 प्रतिशत युवाओं ने माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।

यूएनईपी ने अपनी रिपोर्ट नेविगेटिंग न्यू होराइजंस : ए ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लेनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग में चेताया कि दुनियाभर में युवाओं के बीच ईको एंजायटी एक उभरता हुआ संकट बन चुकी है। इसे क्लाइमेट ग्रीफ या जलवायु से जुड़ा दुख भी कहा जाता है, जो पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरों की प्रतिक्रिया है। डाउन टू अर्थ ने अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 300 से अधिक युवाओं के बीच जनमत सर्वेक्षण किया। इसमें 88 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि वे अपने आसपास जलवायु में बदलाव महसूस कर रहे हैं, जबकि 67 प्रतिशत ने माना कि ये बदलाव उनके रोजमर्रा के जीवन और जीवनशैली को पहले ही प्रभावित कर चुके हैं।अध्ययन यह भी संकेत देते हैं कि पिछले 25 वर्षों में जन्मी पीढ़ी ने शायद कभी सामान्य जलवायु का अनुभव ही नहीं किया।

36 फीसदी खाद्य गुणवत्ता में बदलाव को लेकर डरे

सर्वेक्षण में युवाओं से पूछा गया कि वे किन संकेतों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। दो-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने बढ़ते तापमान और असमय गर्मी या वर्षा को इसका प्रमुख संकेत माना। लगभग 40 प्रतिशत ने धुंध या कोहरे भरे दिनों को, 36 प्रतिशत ने खाद्य गुणवत्ता में बदलाव को और 32 प्रतिशत ने कीट-पतंगों की बढ़ती संख्या को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। 38 प्रतिशत युवाओं ने अत्यधिक ठंड को भी इसका एक लक्षण बताया।

असर सभी पर, लेकिन गरीबों पर सबसे ज्यादा

जब युवाओं से पूछा गया कि क्या जलवायु परिवर्तन का असर अलग-अलग आर्थिक वर्गों पर अलग तरह से पड़ता है, तो 61 प्रतिशत ने कहा कि यह अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। लैंगिक आधार पर राय लगभग एक जैसी रही। करीब 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि जलवायु परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है।

चिंता, असहायपन और डर : युवाओं पर भावनात्मक बोझ... जलवायु संकट का भावनात्मक असर सर्वेक्षण में साफ झलकता है। प्रतिभागियों को अपनी भावनाएं चुनने के लिए छह विकल्प दिए गए...डरा हुआ और उदास, चिंतित, गुस्सा, असहाय, ठगे हुए और उदासीन। 57 प्रतिशत युवाओं ने खुद को चिंतित, 54 प्रतिशत ने असहाय और 43 प्रतिशत ने डरा हुआ और उदास बताया। कई युवाओं ने गुस्से और ठगे जाने की भावना भी व्यक्त की।भविष्य को लेकर आशंकाएं भी गहरी हैं।

प. बंगाल में भाजपा मुसलमान मतदाताओं के भी घर-घर देगी दस्तक

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा मुसलमान मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। पार्टी का प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा एक महीने के अंदर हर विधानसभा सीट के अल्पसंख्यक परिवारों से संपर्क कर उन्हें भाजपा सरकारों के शासन में अल्पसंख्यकों के हुए विकास पर जागरूक करेगा।

पार्टी का लक्ष्य है कि वह पांच से दस फीसदी तक अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट हासिल कर सके। अभी एक से दो फीसदी मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट करते हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। पार्टी के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिये स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी का अधिकार छीन रहे हैं। ब्यूरो

बदरी-केदार परिसर के 70 मीटर में मोबाइल फोन पर रहेगा प्रतिबंध

श्रद्धालु मंदिर के नजदीक जाकर नहीं बना सकेंगे रील व वीडियो

देहरादून। आगामी चारधाम यात्रा के दौरान बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में मंदिर परिसर से 70 मीटर दायरे में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु मंदिर के नजदीक जाकर रील व वीडियो नहीं बना सकेंगे। धामों की पवित्रता व सुगम दर्शन व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन व मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है।

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा, बदरी-केदार धाम में व्यवस्थाओं को मंदिर समिति की ओर से प्रशासन से समन्वय कर बेहतर बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों के 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग व रील, वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय धाम की पवित्रता तथा तीर्थयात्रियों को सरल सुगम दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यात्रा प्रारंभ होने से पहले मंदिर समिति के सभी विश्राम गृहों को तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सुसज्जित किया जाएगा। साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, शौचालय व आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ब्यूरो

काम की खबरें

1 सड़कों पर उड़ रही धूल से जुड़ी शिकायत करें

दिल्ली में सड़कों पर उड़ रही धूल से संबंधित और प्रदूषण की समस्या को लेकर नगर निगम ऐप 311 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में नगर निगम ने लोगों से अपील की है। हेल्पलाइन 155305 पर भी कॉल कर सकते हैं।

2 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए आज तक आवेदन

जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 14 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। एमबीबीएस के बाद दो वर्ष के भीतर इंटर्नशिप कर चुके डॉक्टर नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। 16 फरवरी आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके बाद टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होगी।

3 सेवक स्टेशन पर रुकेगी महानंदा एक्सप्रेस

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलीपुर द्वार जंक्शन के बीच चलने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को सेवक स्टेशन पर दो मिनट का प्रयोगात्मक ठहराव दिया गया है। गाड़ी संख्या 15483 अलीपुर द्वार से जाते समय सेवक स्टेशन पर दोपहर 1.26 बजे पहुंचेगी और वहां से 1.28 बजे चलेगी।

4 कई इलाकों में बाधित रहेगी पानी की आपूर्ति

भूमिगत जलाशय की सालाना सफाई के चलते तुगलकाबाद, कालकाजी, वसंत कुंज समेत दिल्ली की कई कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कुछ कॉलोनियों में सोमवार और अन्य कॉलोनियों में मंगलवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।

5 डीडीए पुस्तकालय में छात्र पंजीकरण करें

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के आरंभ पुस्तकालय में छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें छात्रों को पुस्तकालय में शिफ्ट के अनुसार किताबों को पढ़ने और प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अवसर मिलेगा। डीडीए वेबसाइट dda.gov.in में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आज का मौसम

28.0° अधिकतम | 12.0° न्यूनतम

सूर्योदय : 07:00 | सूर्यास्त : 18:11

अनुमान
अगले दो दिनों के बीच भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं।

शहर 30s

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता अभियान चलाया। नंद नगरी डीटीसी डिपो में आयोजित कार्यशाला में 37 डीटीसी और 32 क्लस्टर बस चालकों को सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश, जीरो डेथ मिशन और महिला सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया गया। वहीं, कड़कड़ी मोड़ रेड लाइट पर चलाए गए अभियान में 2500 वाहन चालकों को जिम्मेदार यातायात व्यवहार के लिए प्रेरित किया गया।

पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का शिलान्यास आज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की कई परियोजनाओं का सोमवार को शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार शाम झिलमिल रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 1075 करोड़ रुपये बताई गई है।

‘विधानसभा समितियों में उपस्थित रहें सदस्य’

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बिजेन्द्र गुप्ता ने सदन की विभिन्न समितियों के सदस्यों को परामर्श जारी किया है। उन्होंने सदस्यों से नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा बुलाए जाने पर सदन की समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

फ्लैटों का निरीक्षण करने जाएंगे मंत्री

नई दिल्ली। भलस्वा इलाके में गरीब लोगों के लिए बनाए गए फ्लैटों का निरीक्षण करने के लिए सोमवार शाम दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद जाएंगे। यहां पर बनाए गए फ्लैट गरीबों को दिए जाने थे, लेकिन वर्षों तक आवंटन न होने की वजह से वह जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा इनकी मरम्मत करवाई जा रही है ताकि इन्हें जल्द आवंटित किया जा सके। इसी क्रम में मंत्री सूद इन फ्लैट का निरीक्षण करेंगे।

आज के कार्यक्रम

- डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित स्टेडियम में सोमवार शाम चार बजे से वसंतोत्सव 2026 का भव्य आयोजन होगा, छात्र-छात्राएं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
- पलाश महोत्सव का आज अंतिम दिन है। बांसेरा पार्क, अशोक गार्डन, लाला हरदयाल पार्क और स्मृति वन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

जल बोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर लगाएगा

पाइप लाइन में लीकेज, पानी चोरी पता चलेगी

■ राजीव शर्मा

नई दिल्ली। राजधानी में पानी की हानि (वाटर लॉस) कम करने के लिए जल बोर्ड एक और नई पहल करने की तैयारी कर रहा है। पानी की बड़ी लाइनों पर इलेक्ट्रॉमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर लगाए जाएंगे।

आधुनिक तकनीक पर काम करने वाले इन फ्लोमीटर के लगने के बाद जैसे ही पाइप लाइन में लीकेज या चोरी के कारण पानी का दबाव कम होगा, कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद लाइन को चेक करके पानी चोरी और लीकेज की जांच कर उसका निराकरण किया जा सकेगा। इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्लोमीटर लगाने के लिए निविदा जारी करके अनुभवी कंपनियों आमंत्रित किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक फिलहाल 25 से ज्यादा लोकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो मीटर के लिए चयनित कर ली गई हैं। इनमें 50 एमएम से लेकर 600 एमएम व्यास की पाइप लाइन शामिल हैं। इनके अलावा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर लगाने के लिए भी कुछ स्थानों को चिह्नित किया गया है। इनके अलावा पूर्व में लगाए गए, लेकिन खराब हो चुके फ्लोमीटर की मरम्मत करके इन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इनके लिए बैटरी और अन्य उपकरण भी खरीदे जाएंगे इन फ्लोमीटर को लगाने वाली कंपनी पांच साल तक इनका रखरखाव और मरम्मत भी करेगी, ताकि समय-समय पर आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके।

40 फीसदी तक पहुंच गया था दिल्ली का वॉटर लॉस : दिल्ली में बड़ी मात्रा में वॉटर लॉस होता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 11 साल पहले दिल्ली में वॉटर लॉस 30 फीसदी था, लेकिन पूर्व सरकार के कार्यकाल में वॉटर लॉस 30 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी तक बढ़ गया था। यानी हर साल करोड़ों का पानी चोरी और लीकेज में बर्बाद हो जाता था। मौजूद सरकार ने बीते साल इसे रोकने के लिए प्रयास किए हैं। इसके तहत वाटर टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, ताकि टैंकरों की लोकेशन ट्रेस हो सके। इसके जरिए नॉन रेवेन्यू पानी की मात्रा को कम किया जा रहा है। सरकार इस वॉटर लॉस को घटाकर 10 फीसदी तक लाने की योजना पर काम कर रही है।

25 से ज्यादा लोकेशन फ्लो मीटर के लिए चयनित कर ली गई हैं

- फ्लोमीटर लगाने और इनके रखरखाव पर 13 करोड़ रुपये खर्च करेगा जल बोर्ड
- लाइनों में पानी का फ्लो कम होते ही संदेश दे देगी आधुनिक प्रणाली, पानी की बर्बादी व चोरी रुकेगी

हैदरपुर जलशोधन संयंत्र में कंट्रोल रूम से निगरानी

पानी की प्रमुख लाइनों पर फ्लो मीटर लगाने के साथ-साथ एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। यह कंट्रोल रूम हैदरपुर जल शोधन संयंत्र में स्थापित होगा। स्काडा सिस्टम के जरिए पाइप लाइनों में पानी के फ्लो की जानकारी ली जाएगी और फ्लो कम होने के बाद कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे।

‘भू आधार भूखंड स्वामित्व में पारदर्शिता तय करेगा’

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ‘भू आधार’ भूखंड के स्वामित्व में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसका 14 अंकों का कोड भू संदर्भित होगा, जिससे भूमि की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा।

सीएम ने भू-आधार कार्ड योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना वर्ष 2016 से है, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की यह योजना दिल्ली के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली में इस प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सरकार द्वारा अब इसे ‘मिशन मोड’ पर लागू करने का जिम्मा राजस्व विभाग की आईटी शाखा को सौंपा गया है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भी सहयोग लेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि डेटा के समन्वय में यह मदद करेगा और धोखाधड़ी वाले लेन-देन तथा बहु पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाएगा। जनता के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें अपनी जमीन की पहचान के लिए कई दस्तावेजों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, एक ही नंबर से जमीन की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि एकीकृत और आधुनिक भूमि रिकॉर्ड से नागरिकों को संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिलता है और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट होती है।

■ एक नंबर से जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी

नेहरू प्लेस में आज से बहुमंजिला कार पार्किंग की शुरुआत

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली और आसपास के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार को नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में छह मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग लोगों के लिए शुरू हो जाएगी।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। इस छह मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग को डीडीए ने तैयार किया है। इस पार्किंग में एक हजार वाहनों को खड़े करनी क्षमता विकसित की गई है।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि नेहरू प्लेस में 62.4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पार्किंग में 660 कारों को, 352 दोपहिया वाहनों को पार्क कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगों के लिए 56 स्थानों को तय किया गया है। जहां पर दिव्यांग अपने वाहन खड़े कर सकेंगे।

निगम पार्किंग व्यवस्था को एकीकृत करने की तैयारी में

नई दिल्ली, व. सं.। राजधानी में पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए नगर निगम प्रशासन योजना बना रहा है। इसे लेकर निगम प्रशासन सार्वजनिक समेत निजी पार्किंग को अपने दायरे में लाएगा। इसके लिए निगम ड्राफ्ट प्लान बनाएगा। इस ड्राफ्ट प्लान को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम की योजना है कि दिल्ली में सभी सार्वजनिक व निजी पार्किंग स्थलों की निगरानी एक ही सरकारी विभाग करे। जिससे पार्किंग स्थलों को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके।

एक्सचेंज बोनस ₹2500/-*
डाउन पेमेंट ₹10,999/-* से शुरू
Hero GoodLife Stand a chance to win Gold and Silver Coins and many more assured benefits*

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. World's no 1 disclaimer - Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2025 Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market(CY25). Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. Available at select dealerships. *Limited period offer, T&C Apply. #Ex-showroom price of Glamour X Drum variant in Delhi.

TOLL FREE NO. 1800 266 0018

Authorised Dealers: South Delhi: Pul Prahladpur Badarpur: Singla Hero - 9289922771, Lajpat Nagar: Sapphire Hero- 9289923175, Adchini (Main Mehrauli Road): Pashupati Hero - 9289922381, Okhla Phase II: ARC Hero- 9289922461, East Delhi: Durgapuri (Loni Road, Shahadra): Himgiri Hero- 9289922380, Pushta Kartar Nagar: Aman Hero- 9289922735, Dilshad Garden: RK Hero- 9289923010, Patparganj Pandav Nagar: Singla Autoneeds Hero- 9289923222, North Delhi: Azadpur: Shraman Hero- 9289923185, Pitampura: Shraman Hero – 9289924252, Rithala (Rohini): Metro Hero- 9289922597, Budh Vihar: JMD Autoworld Hero- 9289924188, Central Delhi: Karol Bagh (Faiz Road): EssAay Hero- 9289922382, Upper India Hero- 9289924343, West Delhi: Roshan Vihar (Najafgarh): Avni Hero- 9289922671, Paschim Vihar (Peeragarhi): Shivganga Hero- 9289922796, Palam Dabri Road (Dwarka): Singla Hero- 9289922530, Raja Puri: Singla Hero- 7836078383, Samalkha: Singla Hero- 7836078484, Janak Puri: Singla Hero- 9911884416, Tilak Nagar: Khanna Hero- 9289922383, Bali Nagar: Khanna Hero- 9289924309, Nawada: Khanna Hero- 9289924310. Authorised Dealers: Ghaziabad: Meerut, Delhi Road- Globe Hero- 9289922073, Shiv Puri, Vijay Nagar- Aman Hero- 9289232123; Sahibabad: Sahib Hero- 9289922486; Noida: H-206A, Sector 63- Dhansri Hero- 9289923044, Sector 5, B 124- Uppal Hero- 9289922462, Sector-58 C-70- Singla Hero- 9289923059; Buland Shahar: Shri Durga Hero- Delhi Road, 9289922504, RajeBabu Road- Krishna Hero- 9289922410. Authorised Dealers: Gurugram: Sec–18, Noble Enclave: Globe Agencies- 9289233915, Himgiri Hero- 9289923046, Basai Road Sector 11: Sharma Hero- 9289923221, Autoneeds Hero- 9289922051, Jasodha Hero- 9289922495, Wazirabad: Himgiri Hero- 9289924247, Railway Road: Himgiri Hero- 9289924248; Sohna: No. 160/2 Delhi Road: Auto Links Hero- 9289924089; Faridabad: Sehgal Hero- 9289922419, NIT: Sehgal Hero- 7217627327, VPS Jindal Motors, Neelambata Road, 9289235889.

FCB INTERFACE/0894/FEB26/HINDI

हिन्दुस्तान 1936 सत्य · सार्थक · संदेश

भारत पर भरोसा

भारत की ताकत पर संदेह करने वालों की संख्या भारत में भी कम नहीं हैं, मगर ऐसे तमाम लोगों को एक बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस की बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। गुटेरस ने दोटूक कहा है कि भारत एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था है, जिसका वैश्विक मामलों में प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, यह बात भी गौर करने की है कि भारतीयों की तकनीकी प्रतिभा पर स्वयं भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी भी शंका करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को जवाब देते हुए गुटेरस ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत बिल्कुल सही जगह है। वह भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं, जो अपनी वैज्ञानिक तरक्की का लाभ पूरी दुनिया को देता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सभी को लाभ मिलना चाहिए। एआई केवल विकसित देशों या दो महाशक्तियों का विशेषाधिकार नहीं है। कोई दोराय नहीं कि भारत में अगर वैज्ञानिक तरक्की होगी, तो उसका लाभ पूरी दुनिया को होगा। एआई के लोकतांत्रिकरण के लिए भारत का आगे रहना जरूरी है। एआई की कमान अगर महाशक्ति देशों के हाथों में रहेगी, तो दुनिया ऐसे महत्वपूर्ण विकास से वंचित रह जाएगी।

गुटेरस के इस कथन पर सबका ध्यान जाना चाहिए- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति के लाभ के लिए एक सार्वभौमिक साधन बन जाए। विश्व में बहुध्रुवीयता से ही सबको लाभ होगा। आश्चर्य नहीं, गुटेरस भारतीय नेताओं के साथ बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की भूमिका पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। विगत दशक में बुरे तजुर्बे के बाद वह सच्ची बहुध्रुवीयता के समर्थक हो गए हैं। वह अब मानने लगे हैं कि उभरती अर्थव्यवस्था की भूमिका लगातार बढ़ती जानी चाहिए और उन्हें व्यापार, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मजबूत नेटवर्क बनाने चाहिए। यहां यह ध्यान रहे, गुटेरस ने अमेरिका के साथ हो रहे भारत के व्यापार समझौते का नहीं, बल्कि यूरोप के साथ हुए व्यापार समझौते को अच्छा उदाहरण बताया है। दुनिया में

विश्व में सुधार के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आगे आना जरूरी है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भारत को एक ऐसी ही उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं।

एक नई व्यवस्था या नए नेटवर्क की स्थापना होनी चाहिए। एक ऐसा नेटवर्क बनना चाहिए, जिसमें केवल विकसित देश ही मजबूत न रहें। दुनिया जान गई है, चंद विकसित देश अगर मजबूत होंगे, तो वह कभी भी बहुध्रुवीयता को पसंद नहीं करेंगे। भारत उन देशों में शुमार है, जो बहुध्रुवीयता या गुटनिरपेक्षता का शुरू से ही झंडाबरदार रहा है। आज दुनिया के सामने यह त्रासद तथ्य बहुत उजागर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी भी संघर्ष को सुलझाने और शांति बनाए रखने में असमर्थ साबित हो रहा है। मुट्ठी भर देश मजबूत हैं, जिनका लक्ष्य सार्वभौमिक शांति कतई नहीं है। ये देश मात्र अपना हित देख रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में समस्याओं के समाधान को बल नहीं मिल रहा है।

आखिर आज दुनिया में समाधान की ओर जाने वाला रास्ता कहां है? गुटेरस ने भारत की चर्चा करते हुए खुलकर स्वीकारा है कि सुरक्षा परिषद में मूलभूत सुधार की जरूरत है। एक ऐसी परिषद चाहिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जरूरतों के मुताबिक नहीं, बल्कि आज की जरूरत के मुताबिक हो। सुधार के लिए नई अर्थव्यवस्था का आगे आना जरूरी है और भारत को एक ऐसी ही उभरती व्यवस्था के रूप में गुटेरस देख रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सुखद तथ्य है कि वह वैश्विक नेटवर्क में भारत को एक केंद्रीय भूमिका में देखना चाहते हैं। अतः भारत को बहुत रणनीतिक ढंग से बन रहे नए अवसरों का लाभ उठाना होगा। अपनी शक्ति पर संदेह करना छोड़कर आगे बढ़ना होगा।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

16 फरवरी, 1951

अमरीकी सहायता

भारत को इस वर्ष भूकम्प, बाढ़, अनावृष्टि, टिड्डी दल आदि दैवी प्रकोपों के कारण भयंकर रूप में खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। मार्च 1952 तक वह अपने को पूर्णतया स्वावलम्बी बना लेना चाहता है। इस दिशा में उसने प्रगति भी की है। अन्न का उत्पादन पहले से बढ़ा भी है। किन्तु दैवी प्रकोपों ने उसके प्रयत्नों को गम्भीर धक्का पहुंचाया है। इस प्रकार जो संकट उत्पन्न हो गया है, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए भारत को इस वर्ष 60 लाख टन अन्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा। उसने इसमें से 40 लाख टन की व्यवस्था अन्य सूत्रों से कर ली है और शेष 20 लाख टन के लिए अमरीका की सरकार से अनुरोध किया था कि वह इसे भारत को मुहय्या कर दे। भारत ने अमरीका से कहा था कि इस अनाज की कीमत वह चुका देगा, किन्तु इस समय नकद रुपया देने की स्थिति में वह अपने को नहीं पाता है।

भारत ने यह अनुरोध अपने राजदूत की मारफत पिछले दिसम्बर के मध्य में किया था। इस संबंध में अमरीकी शासन अभी तक कोई निश्चयात्मक कदम नहीं उठा पाया। अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्य इस हक में थे कि अमरीका को 20 लाख टन अन्न सहायता स्वरूप भारत को दे देना चाहिए। इसके विपरीत अमरीका में इस किस्म की चर्चा भी हुई कि जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में दूर पूर्व के संबंध में अमरीकी नीति का विरोध कर रहा है, तो अमरीका क्यों भारत की सहायता करे? इस तरह अमरीका से यह अन्न मिलने की बात अनिश्चित बनी रही। जब अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री हूवर की वर्तमान राष्ट्रपति श्री ट्रमन से इस विषय में भेंट हुई, तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो गयी। श्री हूवर रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं और अमरीकी कांग्रेस में पार्टियों की संख्या-बल की दृष्टि से जो स्थिति है, उसको देखते हुए अमरीकी शासन चाहे तब भी रिपब्लिकन पार्टी के सहयोग के बिना सहायता का विधेयक आसानी से मंजूर नहीं हो सकता। हूवर ने इस मामले में मानवीय और उदार दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि अन्न की मांग को राजनीतिक सौदेबाजी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह ईसाइयत का तकाजा है- पीड़ित मानवता को सहायता पहुंचाने का प्रश्न है।

ऊर्जा सुरक्षा से न हो कोई समझौता

भारत ऊर्जा के लिए किसी एक देश या स्रोत पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा, तो रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। हरसंभव विकल्प खुले रखकर चलना बेहतर है।

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हकीकत बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया पर इस समझौते का एलान किया और खुशखबरी दी कि अब अमेरिका में भारतीय आयात पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने रिश्तों का हवाला दिया और यह भी कहा कि उनके आग्रह पर ही ऐसा किया गया है।

बात यहीं नहीं थमी। उन्होंने यह एलान भी कर दिया कि अब भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। व्यापार समझौते से शेयर बाजार में तो कुछ समय के लिए तो बहार आने जैसा माहौल बना, मगर राजनीतिक मोर्चे पर भूचाल आ गया। विपक्ष द्वारा सवाल किया जाने लगा, क्या सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या भारत अपने दशकों पुराने भरोसेमंद रणनीतिक मित्र रूस के साथ रिश्ते को भी दांव पर लगा देगा? इनसे भी बड़ा सवाल यह था और है कि अमेरिका से तेल व गैस जैसी चीजें खरीदने का सौदा क्या भारत के हित में है? अगर ऐसा है, तब भी क्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका जैसे देश पर बहुत ज्यादा निर्भर होना हमारी स्थिति को नाजुक नहीं बनाएगा?

सरकार बार-बार सफाई दे रही है कि भारत अपनी 'ऊर्जा संप्रभुता' से समझौता नहीं करेगा। असल में, तेल या गैस खरीदना कोई मामूली व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसे ऊर्जा सुरक्षा के बजाय ऊर्जा संप्रभुता कहना भी यही दिखाता है कि बात कितनी बड़ी है। देखने में लग सकता है कि सरकार और विपक्ष इस सौदे पर राजनीतिक खेल कर रहे हैं, मगर सच यही है कि ऊर्जा केवल आर्थिक विषय नहीं है; यह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, औद्योगिक विकास, पर्यावरण व सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के कितने आयाम हैं और उसके सामने कौन-कौन से वास्तविक विकल्प मौजूद हैं?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ सिर्फ तेल या गैस मिल जाना या इसे खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेना भर नहीं है। वैसे भी, अगर याद करें, तो कुछ साल पहले तक ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बिजली के लिए होता था। तेल और गैस के साथ तो इसका नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन दुनिया भर में तेल व गैस ही नहीं, कोयले जैसी चीजों को भी ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जाहिर है, यह सब जीवाश्म ईंधन से बने ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, जिनके भंडार सीमित हैं और जो कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। इनसे बनने वाली बिजली पर यही खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे सतत चलने वाले स्रोतों की न सिर्फ खोज हो रही है, बल्कि उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तमाम जोखिम व आलोचनाओं के बावजूद परमाणु ऊर्जा की भी इस समीकरण में अब एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

यहां यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा की आपूर्ति या उसकी उपलब्धता भर से काम नहीं चलता, इसे चार तरह से देखना पड़ता है। निस्संदेह, उपलब्धता जरूरी पहलू है, लेकिन यह भी देखना पड़ता है कि वह किफायती है या नहीं, कहां-कहां तक या किस-किस तक पहुंच रही है और कितनी टिकाऊ या भरोसेमंद है? इन चार पैमानों पर हिसाब जोड़कर ही वह ऊर्जा रणनीति बन सकती है, जिसे ऊर्जा सुरक्षा या ऊर्जा संप्रभुता कहा जा सकता है।

भारत की दिक्कत यह है कि वह पहले पैमाने पर ही काफी विकट स्थिति में है। खासकर कच्चे तेल के मामले में अपनी जरूरत का 80 से 85 प्रतिशत तक तो वह आयात करता है। यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने का भारत की अर्थव्यवस्था पर हमेशा बुरा असर पड़ता रहा है। अब जैसे-जैसे सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, प्राकृतिक गैस के मामले में भी आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यहां आपूर्ति में रुकावट या दामों में उछाल से अचानक महंगाई भड़क सकती है। इससे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में आता है, और तब राजनीतिक असंतोष पैदा हो सकता है। इसीलिए पेट्रोल, डीजल की कीमतों के साथ-साथ इन पर लगने वाले टैक्स, सब्सिडी और इनकी सप्लाई का पक्का इंतजाम किसी भी सरकार के लिए बहुत अहम विषय होता है। ऐसे में, अमेरिका के साथ सौदे के बिंदु सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी अहम विषय हैं।

भारत को पारंपरिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता घटाकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को तेजी से विकसित करना है। अभी देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बन रही है, जो यकीनन बड़ी उपलब्धि है। आंकड़ों के अनुसार, अभी तक देश में इन स्रोतों से लगभग 200 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। अगले दस साल में इसे बढ़ाकर सालाना 600 से 900 टेरावॉट आवर बिजली बनाने का लक्ष्य है। आसान भाषा में एक टेरावॉट आवर का मतलब सौ करोड़ यूनिट बिजली है।

यहां एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि अक्षय ऊर्जा (रीन्यूएबल एनर्जी) थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की होती है। कभी धूप की तेजी, कभी हवा के होने या न होने से इसकी आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका स्टोरेज का इंतजाम भी बड़ी समस्या है। जर्मनी ने बहुत तेजी से इसकी क्षमता बढ़ाई, तो अचानक उसे एक झटका भी झेलना पड़ा, जब ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ीं और सप्लाई भी वैसी भरोसेमंद न हुई। भारत को ऐसे उदाहरणों से भी सबक लेकर चलना होगा।

अमेरिकी सौदे के बारे में अभी बहुत कुछ साफ होना है और शायद बहुत कुछ बदल भी सकता है, इसलिए फिलहाल यही कहना उचित है कि ऊर्जा की व्यवस्था केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर कूटनीतिक संतुलन मांगता है। अगर भारत किसी एक आपूर्तिकर्ता या स्रोत पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा, तो यह रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर अरब देशों, रूस, अमेरिका और वेनेजुएला जैसे रास्तों से अपनी जरूरतें पूरी करने का फायदेमंद फॉर्मूला बन जाए, तो यह इसके लिए फायदे का सौदा बन सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई के शिखर सम्मेलन से भारत करे नई शुरुआत

यहां स्कैन करें

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

आज (16 फरवरी) से नई दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शुरुआत हो रही है। यह पहला मौका है, जब भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2023 से एआई सम्मेलन की शुरुआत हुई है और एआई के प्रति दुनिया का नजरिया जिस तरह सिलसिलेवार बदला है, उसका प्रतिबिंब यह सम्मेलन साबित हो रहा है।

इसका पहला शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, जिसमें सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 2024 में दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नैतिकता, समावेशन, सुरक्षित व जिम्मेदार एआई पर विमर्श हुआ। साल 2025 में इसका तीसरा शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ, जिसमें साझा सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और वास्तविक दुनिया में इसके इस्तेमाल पर चर्चा की गई। लिहाजा, यह पहला मौका है, जब 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है।

यह वास्तव है कि वैश्विक एआई एजेंडा को आकार देने में उभरती आर्थिक ताकतों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह हमारे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुक्त बाजार वाले लोकतंत्र के तौर पर भारत के लिए एआई संबंधी वैश्विक नियमों को आकार देना आवश्यक है।

यह पहला मौका है, जब भारत एआई सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में एआई के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली सम्मेलन का उद्देश्य एआई को 'एक्शन' से 'इम्पैक्ट' की ओर ले जाना है, जिसमें मापने योग्य परिणामों, साझा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और समावेशी नवाचार पर चर्चा होगी। अभी दुनिया भर की सरकारें, नीति-निर्माता और तकनीकी उद्यमी एआई को नियंत्रित करने को लेकर वैश्विक विमर्श में जुटे हैं, ताकि इसके नुकसान को कम किया जा सके और इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। तकनीकी क्षेत्र के उद्यमी इस बात से तो सहमत हैं कि एआई परिवर्तनकारी होगी, लेकिन इसके खतरों के बारे में उनकी सोच अलग-अलग है। जैसे- ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि उन्नत एआई से नैतिकता, सुरक्षा व दुरुपयोग संबंधी गंभीर खतरे जुड़े हैं। वह इस क्षेत्र में मजबूत शासकीय ढांचे की कमी की बात दोहराते रहे हैं। उधर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एआई को 'मानवता के लिए महत्वपूर्ण तकनीक' मानते हैं। वह इसके जिम्मेदार विस्तार पर जोर देते हैं।

बहरहाल, भारत के लिए अपने एआई मंचों को नियंत्रित करना निहायत जरूरी है। यहां एक अरब से अधिक उपभोक्ता मोबाइल व अन्य माध्यमों से किसी न किसी रूप में जेनरेटिव एआई का उपयोग कर रहे हैं। यदि उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो भारतीय गलत सूचना और धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। डीप फेक वीडियो और फर्जी कॉल के कारण कई लोगों को हजारों करोड़ रुपये की चपत लग भी चुकी है। अच्छी बात है कि फर्जी वीडियो और एआई-निर्मित सामग्री पर नियम बनाने को लेकर भारत पहले ही नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है।

भारत दो बड़े उद्देश्यों पर काम कर रहा है। पहला, वह खुद का एआई मंच बनाना चाहता है, ताकि वैश्विक कंपनियों पर उसकी पूरी निर्भरता न रहे। दूसरा, वह संसार के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय नियम व मानक बनाने की मांग कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय नेता यह मानते हैं कि आज मुख्य रूप से अमेरिका और चीन वैश्विक एआई क्षमताओं का निर्धारण करते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अनुसार, अमेरिका ने 2024 में 40 विश्वस्तरीय मॉडल विकसित किए, जबकि चीन ने 15। यही कारण है कि भारत जैसे देश विदेशी एआई तंत्रों पर निर्भर हो गए हैं। इसीलिए, भारत बुनियादी स्तर के कई महत्वपूर्ण एआई मॉडल विकसित कर रहा है, जिनमें इंडियाएआई मिशन के तहत विकसित मॉडल भी शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नए डाटा संरक्षण जैसी कई पहल भी कर रहा है।

नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में बहुपक्षीय घोषणापत्र भी जारी हो सकता है, जिसका महत्व बेशक पिछले सम्मेलनों जैसा ही होगा, लेकिन उसमें क्रियान्वयन, समावेशन और साझा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर स्पष्ट बदलाव दिख सकता है। इस सम्मेलन का समापन 20 फरवरी को होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शब्द सम्हारे बोलिए

आजकल लोग शब्दों का इस्तेमाल इतनी बेहोशी से करते हैं कि उनका सही अर्थ खो जाता है। हर तरफ शब्दों का गुबार छाया रहता है। मीडिया को हर वक्त 'बाइट' चाहिए। वह शब्दों को इकट्ठा करता रहता है। राजनीति में तो गदर मचा रहता है। राजनेता एक-दूसरे के लिए ऐसे-ऐसे अपशब्द उछालते हैं, जैसे चाकू-छुरे भोंक रहे हों। जैसे ही सत्ता का सवाल आता है, सब कुछ भुलाकर वही लोग, जो जानी दुश्मन थे, दोस्त बन जाते हैं। मानो शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे हालात में कबीर साहब का दोहा याद आता है: *शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।*

शब्द सम्हलकर बोलिए। किसी घायल मन के लिए सहानुभूति के दो बोल उसके जख्मों पर मरहम का काम करते हैं और कर्कश बोल घाव को कुरेद देते हैं। शब्द आते कहां से हैं? वे प्रकट होते हैं मन से, उनके पीछे है भाव या विचार, जो शब्दों का अपने वाहन की तरह प्रयोग करता है। यह मन कैसा है- साफ-सुथरा, प्यार भरा या विषाक्त? शब्द ही हैं, जो दूसरों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए भी।

शब्द और मौन का अटूट रिश्ता है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति हुई है आकाश से। आकाश, यानी खालीपन। मूलतः शब्द बोला जाता था, उसके बाद जब लेखन की कला विकसित हुई, तो वह लिखा जाने लगा। शब्द का असर तभी होता है, जब बोलने वाले के भीतर गहराई हो, समझ हो और शब्द सिर्फ वमन की तरह प्रयोग न हो। आजकल लोग इतने भरे हुए हैं अंदर से कि उसे बाहर फेंकने के लिए बोलते हैं। इसीलिए किसी के बोलने में असर नहीं होता।

ओशो कहते हैं, आपके शब्दों का गर्भपात होता है। अखबार पढ़ा नहीं कि भागे किसी को बताने, क्योंकि न्यूज क्या है। ज्ञान की किताब पढ़ी नहीं कि बेचैन हो गए, किसको उपदेश दें? यह गर्भपात है। शब्दों को जरा भी मौन में जीने की सुविधा नहीं है। शब्दों को मौन के गर्भ में रखना चाहिए। वहीं वे पलें-बढ़ें और परिपक्व हों। वहीं आपके भाव और मन की ऊर्जा शब्दों में प्रवेश करती है। इसलिए, कोई व्यक्ति, जिसमें सघन मौन की क्षमता है, वह कुछ भी बोले, तो उसके बोलने में काव्य हो जाता है। आप जितना कम बोलें उतना आपका आशय गहरा होता है।

शब्द जरूरी हैं, पर उनसे भी ज्यादा निःशब्द चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं, वे वही लोग होते हैं, जिनके पास मौन की क्षमता होती है।

शब्द जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा निःशब्द चाहिए। उसके आसपास मौन की आभा होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जिन लोगों के शब्दों में प्राण होते हैं, वे वही लोग होते हैं, जिनके पास मौन की क्षमता होती है। अगर आपके शब्द मौन से निकलें, तभी वे औषधि समान होंगे। दूसरों का दुख हरेंगे, उनकी पीड़ा पर मरहम लगाएंगे।

अमृत साधना

अनुलोम-विलोम
विश्व बाल कैंसर दिवस

बच्चों में बढ़ते कैंसर पर ध्यान देना होगा

अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर पीड़ित बच्चों, किशोरों और उनके परिजनों के प्रति समर्थन, जागरूकता और एकजुटता प्रदर्शित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि उनको प्रारंभिक निदान, उचित उपचार और एक समान स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। बावजूद इसके बाल कैंसर पर हमें और अधिक ध्यान देना होगा। अध्ययन बताते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 1,000 से ज्यादा बच्चों में कैंसर का पता चलता है। इस तरह, हर साल 20 वर्ष से कम उम्र के करीब 4,00,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। 15 वर्ष से कम आयु-वर्ग में प्रति दस लाख बच्चों में 17.14 कैंसर के मामले सामने आते हैं। इसी तरह, 15 से 39 वर्ष की आयु के किशोरों, युवाओं व वयस्कों में प्रति एक लाख पर 74.9 मामले सामने आते हैं। हालांकि, बच्चों और किशोरों में तुलनात्मक रूप से कैंसर कम दिखता है, फिर भी अमेरिका जैसे विकसित देशों में शैशवावस्था के बाद बच्चों में बीमारी से होने वाली मौतों का यह एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि कैंसर पीड़ित बच्चों में जीवित रहने की दर उच्च आय वाले देशों में 80 प्रतिशत तक और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में केवल 20 प्रतिशत तक होती है। जाहिर है, भारत जैसे देशों में चिंता गहरी है।

बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर, वयस्कों में होने वाले कैंसर की तरह ही जीन में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, जिससे कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। कुछ आनुवंशिक परिवर्तन, जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, वे भी कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं। कैंसर का कारण बनने वाले आनुवंशिक परिवर्तन विकास के दौरान कोशिकाओं में स्वतः भी हो सकते हैं। बच्चों में होने वाले सभी कैंसरों में से लगभग आठ से 10 प्रतिशत मामलों में जीन में वंशानुगत रोगजनक भिन्न होता है, हालांकि यह प्रतिशत कैंसर के प्रकारों के अनुसार अलग-अलग होता है। वास्तव में, बाल कैंसर के 12 से अधिक प्रमुख प्रकार और 100 से अधिक उप-प्रकार होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत जीवित रहने की दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसे शत-प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। कैंसर पीड़ितों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए प्रारंभिक निदान, विशेषज्ञ देखभाल और सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, अन्यथा इस तरह के लक्ष्य मात्र कागजों की शोभा बढ़ाएंगे।

हिमांशु कुमार, टिप्पणीकार

आधुनिक इलाज से स्थिति संभल रही

यह सही है कि दुनिया भर में बच्चों को होने वाले कैंसर ने चिकित्सा विज्ञान के सामने गंभीर चिंता पैदा की है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नए शोधों ने इस चिंता को काफी हद तक कम भी किया है। ऐसा सिर्फ विदेश में ही नहीं होता। भारत में भी इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के सफल प्रयास हुए हैं। एम्स का ही उदाहरण लें। आंकड़े बताते हैं कि करीब दस साल पहले कैंसर से पीड़ित बच्चों में से 50 फीसदी से भी कम को बचा पाना संभव हो पाता था, क्योंकि हमारे पास उस तरह की तकनीक नहीं थी, लेकिन अब हर चार में से तीन बच्चे ठीक हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि 75 फीसदी बच्चे कैंसर को हराने में सफल साबित हो रहे हैं, जो संकेत है कि भारत में कैंसर के इलाज ने कितनी तरक्की कर ली है। अच्छी बात है कि इसमें लगातार सुधार भी हो रहा है, यानी चिकित्सा विज्ञान इस दिशा में लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है।

यहां मध्य प्रदेश की चर्चा जरूरी है। पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि वहां के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक कैंसर विभाग में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे कैंसर से उबर चुके हैं। खबर बताती है कि बीते दो वर्षों में वहां 316 बच्चों का कैंसर का इलाज किया गया, जिनमें से लगभग 270 बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। इस संस्थान में पूरे राज्य से कैंसर पीड़ित मरीज भेजे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि गंभीर स्थिति के मरीज भी अब ठीक हो रहे हैं। यानी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के मामले में भी पूर्ण सफलता पाई जा सकती है, बशर्ते समय पर सही रणनीति बनाई जाए और उस पर संजीदगी से अमल किया जाए। मध्य प्रदेश में आम आदमी के साथ-साथ डॉक्टरों में बच्चों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए समय-समय पर सम्मेलन आदि कराए जा रहे हैं, जिनसे डॉक्टरों में इस रोग को लेकर समझ बढ़ी है और वे कहीं अधिक दक्षता से इसके इलाज में सफल हो पा रहे हैं। साफ है, इस तरह के प्रयास यदि पूरे देश के स्तर पर किए जाएं, तो और भी बेहतर तस्वीर हम देख सकेंगे।

ऐसा नहीं है कि यह बदलाव भारत में ही हो रहा है। दुनिया भर के देश, खासतौर से विकसित मुल्कों में नई-नई तकनीकों से न सिर्फ रोग की पहचान की जा रही है, बल्कि उनका इलाज भी किया जा रहा है। इसीलिए, यह कहना गलत होगा कि कैंसर को लेकर बेशक कभी भय का माहौल रहा करता था, लेकिन आज इसे ऐसी बीमारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका इलाज संभव है। इससे मरीजों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे रोग पर जल्द विजय पाने लगे हैं।

समिधा मिश्र, टिप्पणीकार

बाजार नियामक सेबी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुताबिक कीमतें रखने का प्रस्ताव रखा

सोने-चांदी के ईटीएफ में घाटे से बचाने के लिए नए नियम जल्द

तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने सोने और चांदी के ईटीएफ के कारोबारी नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसका मकसद है कि इनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के ज्यादा करीब रहें और निवेशकों को सही भाव पर खरीद-फरोख्त का मौका मिल सके। इससे आम निवेशकों को काफी फायदा होगा और अनचाहा नुकसान होने से बचाव हो सकेगा।

दरअसल, दुनियाभर में सोने और चांदी की खरीद-बिक्री 24 घंटे होती है। अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज में भी इनकी कीमतें लगातार ऊपर-नीचे हो जाती हैं लेकिन भारत में ईटीएफ की खरीद-बिक्री शेयर बाजार के समय मुताबिक सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक ही होती है। इस दौरान इनके भाव एक तय सीमा (फिक्स्ड प्राइस बैंड) के भीतर ही घट-बढ़ सकते हैं।

इस तय सीमा और समय अंतर की वजह से अक्सर भारतीय ईटीएफ की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दाम से पिछड़ जाती हैं या उनमें बड़ा अंतर आ जाता है। इसके चलते आम निवेशकों को सही दाम पर खरीद-बिक्री नहीं मिल पाती और कई बार बिना वजह नुकसान हो भी जाता है। इसके चलते ही सेबी ने ईटीएफ की खरीद-बिक्री के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने हाल ही में प्रस्ताव से जुड़ा सलाह दस्तावेज जारी किया है और मार्च 2026 तक लोगों से राय मांगी है, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- भारतीय शेयर बाजार के कारोबारी समय के मुताबिक कीमतों का नया दायरा तय होगा
- एक दिन में 20 फीसदी तक कीमतों में उछाल या गिरावट दर्ज हो सकेगी

क्या है नया प्रस्ताव

सेबी ने 'डायनामिक प्राइस बैंड' लागू करने का सुझाव दिया है। इसका मतलब यह है कि कीमतों की सीमा बाजार की स्थिति के अनुसार बदली जा सकेगी। शुरुआत में एक तय सीमा रहेगी, लेकिन अगर बाजार में तेज हलचल होती है तो दायरा बढ़ाया जा सकेगा। हर बड़े बदलाव के बाद कुछ समय का अंतर भी दिया जाएगा, ताकि बाजार स्थिर हो सके और घबराहट में खरीद-फरोख्त न हो।

निवेशक ऐसे समझें

नया दायरा छह फीसदी का होगा। यानी एक दिन में ईटीएफ के भाव छह फीसदी तक ऊपर या नीचे हो सकते हैं। अगर बाजार में तेज हलचल होती है तो दायरे को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकेगा और हर बार यह तीन फीसदी तक बढ़ेगा। हर बदलाव के बाद बाजार को स्थिर होने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। एक दिन में कुल दायरा 20% की सीमा तक जा सकेगा।

बाजार खुलने से पहले दिशा तय होगी

सेबी ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जो है 'प्री-ओपन सेशन' की शुरुआत। शेयर बाजार की तरह अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए भी बाजार खुलने से पहले एक खास सत्र हो सकता है। इसका मकसद यह है कि रातभर में विदेशी बाजारों में जो भी बदलाव हुए हैं, उन्हें भारतीय बाजार खुलने से पहले ही समायोजित कर लिया जाए। इससे सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में दिखने वाले भारी गैप को कम किया जा सकेगा और निवेशकों को एक संतुलित शुरुआत मिलेगी।

बाजार 30s

वित्त-बीमा कारोबार अलग करेंगे

नई दिल्ली। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने वित्तीय सेवा और बीमा कारोबार को दो अलग-अलग सूचीबद्ध इकाइयों में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने यह कदम अपनी भावी व्यावसायिक कार्ययोजना को और अधिक स्पष्ट एवं केंद्रित करने के उद्देश्य से उठाया है।

घरों के दाम धीमी रफ्तार से बढ़े

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में घरों की औसत कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार पिछले साल काफी धीमी रही और इसमें महज छह प्रतिशत का इजाफा हुआ। 2024 में क्षेत्र में घरों की कीमतें 49 प्रतिशत तक उछल गई थीं। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी 'प्रॉपटाइगर' के आंकड़ों में यह बात सामने आई है।

हीरो ईवी क्षेत्र में पहुंच बढ़ाएगी

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने स्कूटर, प्रीमियम बाइक और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, जहां फिलहाल इसकी हिस्सेदारी कम है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 12,487 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,275 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

दस माह में देश ने जोड़ी 52 गीगावाट बिजली क्षमता

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह अप्रैल-जनवरी के दौरान सभी ऊर्जा स्रोतों से रिकॉर्ड 52 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर एक हजार मेगावाट) से अधिक बिजली क्षमता जोड़ी है।

बिजली मंत्रालय ने बताया कि यह किसी एक साल में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। इसने वित्त वर्ष 2024-25 में हासिल किए गए 34,054 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 (31 जनवरी तक) के दौरान, सभी स्रोतों से रिकॉर्ड 52,537 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (31 जनवरी तक) में जो नई बिजली क्षमता जोड़ी गई, उसका 39,657 मेगावाट हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया। इसमें 34,955 मेगावाट सौर बिजली और 4,613 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।

नायरा को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकी

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस के अलावा दुनिया के अन्य देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद होने के बाद रोसनेफ्ट के समर्थन वाली वाली भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी को घरेलू बाजार में भी कच्चा तेल मिलना बंद हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक, वेदांता लिमिटेड की केयर्न ऑयल एंड गैस ने पाबंदियों के इस माहौल के बीच नायरा को राजस्थान के अपने तेल क्षेत्र से से कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी है। नायरा में रोसनेफ्ट समेत कई रूसी कंपनियों का स्वामित्व है। कच्चा तेल उसकी कुल जरूरत का लगभग 5-10 प्रतिशत था।

कर्ज लेकर शेयरों की खरीदारी महंगी होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने शेयर बाजार में काम करने वाले ब्रोकरों और बैंक के बीच कर्ज देने के नियमों में कड़े बदलाव का फैसला किया है। इसका सीधा असर निवेशकों पर दिख सकता है। उनके लिए ब्रोकर से उधार लेकर (लीवरेज) शेयरों की खरीद-बिक्री महंगी हो सकती है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

नए नियमों में अब बैंकों को सिर्फ तभी रकम देनी होगी, जब ब्रोकर 100% सुरक्षित कोलेटरल (जमानत) दे पाए। अगर कोई ब्रोकर बैंक से एक लाख की रकम लेता है, तो बैंक के पास भी उसके बराबर की नकदी या गारंटीकृत सुरक्षित संपत्ति जमा होगी। पहले ब्रोकर आंशिक जमानत से भी कर्ज ले पाते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। इसके साथ ही बैंक अब ऐसे किसी भी कर्ज की अनुमति नहीं देंगे, जिसे ब्रोकर अपनी खुद की ट्रेडिंग या निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल करें। पहले कुछ ब्रोकर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे रकम का इस्तेमाल बाजार में सौदेबाजी के लिए कर लेते थे।

निवेशकों-कारोबारियों पर ऐसे असर: केंद्रीय बैंक ने मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के नियम भी कड़े किए हैं। इस व्यवस्था के तहत ब्रोकर अपने ग्राहकों को उनके निवेश की तुलना में कई गुना अधिक लीवरेज देते हैं। लेकिन अब सुरक्षित कर्ज महंगा होने से ब्रोकर इसकी लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इसके चलते मार्जिन ट्रेडिंग का उपयोग महंगा हो सकता है।

गिरवी शेयरों की निगरानी : नए नियमों में अब गिरवी रखे शेयरों और उनके मूल्य की लगातार निगरानी की जाएगी। अगर शेयरों के मूल्य में तेज गिरावट आती है तो ब्रोकर ग्राहक से तुरंत रकम वापस (मार्जिन कॉल) मांग सकता है। इसके साथ ही इक्विटी शेयरों पर 40% हेयरकट लागू होगा। यानी किसी निवेशक ने 100 रुपये का शेयर गिरवी रखा है तो ब्रोकर उसे केवल 60 रुपये के बराबर मानेगा।

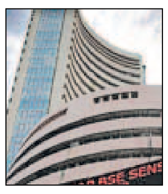

ये फायदे होंगे

विशेषज्ञों का मानना है कि कई ट्रेडर जो उधार पैसा लेकर बड़े-बड़े ट्रेड करते थे, अब कम करेंगे। इसका सीधा असर यह है कि दिन-प्रतिदिन की ट्रेडिंग गतिविधि थोड़ी धीमी दिख सकती है। वहीं, लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा।

इंडिगो जल्द एक हजार पायलट की भर्ती करेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बड़े स्तर पर पायलट भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कंपनी 1,000 से ज्यादा पायलटों की नियुक्तियां करेगी।

यह फैसला दिसंबर 2025 में सामने आए परिचालन संकट के बाद लिया गया है, जब स्टाफ की कमी के चलते एयरलाइन को सिर्फ सात दिनों में 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। खबरों के मुताबिक, नई भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन शामिल होंगे। यह हाल के वर्षों में किसी भारतीय एयरलाइन की ओर से शुरू की गई सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। यह विमानन कंपनी हर महीने औसतन चार नए विमान अपने बेडे में शामिल कर रही है।

यूबीएस नियुक्तियां करेगी

नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की दिग्गज बैंकिंग कंपनी यूबीएस ने हैदराबाद में अपना नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शुरू किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगले दो वर्षों में भारत में करीब 3,000 पेशेवरों को नौकरी देगी। यह केंद्र डेटा आकलन, रिस्क मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करेगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अप्रैल में हो सकता है लागू

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के करीब पहुंच चुका है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इसे अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है।

इसे वृहद आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) नाम दिया गया है। इस पर भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब डॉलर का है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक इसे दोगुना करना है। इसके अलावा दोनों देशों ने दोहरा अंशदान संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जो भारतीय या ब्रिटिश कर्मचारी अस्थायी रूप से दूसरे देश में काम करेंगे, उन्हें दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा का दोहरा भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

भारत के इन क्षेत्रों को होगा फायदा

इस समझौते के तहत भारत के 99 प्रतिशत उत्पाद ब्रिटेन में बिना किसी शुल्क के भेजे जा सकेंगे, इससे भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर (जूते), रत्न-आभूषण, स्पोर्ट्स सामान और खिलौना उद्योग को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। जबकि भारत में ब्रिटेन से आने वाली कारों और व्हिस्की पर कम शुल्क लगेगा। कारों के मामले में भारत अभी 110 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाता है। समझौते के तहत इसे पांच साल में घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा, हालांकि यह एक तय कोटा प्रणाली के तहत होगा ताकि घरेलू उद्योग को अचानक नुकसान न हो।

सर्राफा बाजार में तेज हलचल संभव

समीक्षा

नई दिल्ली, एजेंसी। इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। विशेषज्ञों ने यह बात कही है।

उन्होंने कहा कि निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आंकड़ों जैसे मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और फेडरल रिजर्व की नीतियों पर खास नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, व्यापारी संभावित ब्याज दरों में कटौती का समय और गति समझने के लिए अमेरिका के श्रम संबंधी आंकड़े, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के विवरण और फेड के अधिकारियों के बयानों पर नजर रखेंगे।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा कि सोने और चांदी की कीमतों में और अधिक मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन जीडीपी पर आने वाले अमेरिकी आंकड़े और व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति संख्या और फेडरल रिजर्व के अधिकारी की टिप्पणी पर ध्यान केंद्रित होने से अस्थिरता बनी रहेगी।

बीते हफ्ते चांदी 2.2 प्रतिशत तक लुढ़की

घरेलू बाजार में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी का वायदा भाव पिछले सप्ताह 5,532 रुपये यानी 2.2 प्रतिशत गिर गया, जबकि सोने का भाव 444 रुपये यानी 0.3 प्रतिशत बढ़ा। एंजेल वन के उपाध्यक्ष प्रथमेश माल्या ने कहा कि फरवरी 2026 में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 13 फरवरी को कीमतें 1,80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर से घटकर लगभग 1,53,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने निकट अवधि में दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे पिछले सप्ताह सोने की कीमतों पर असर पड़ा है।

भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों ने वापसी की

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने फरवरी के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में 19,675 करोड़ रुपये डाले हैं। एफपीआई का यह प्रवाह लगातार तीन माह की भारी बिकवाली के बाद हुआ है।

एफपीआई ने जनवरी में भारतीय बाजार से 35,962 करोड़, दिसंबर में 22,611 करोड़ और नवंबर में 3,765 करोड़ रुपये निकाले थे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में एफपीआई ने भारतीय शेयरों से शुद्ध रूप से 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है। यह एफपीआई के प्रवाह की दृष्टि से सबसे खराब वर्षों में रहा है। एफपीआई ने इस महीने शेयरों में 19,675 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हाल की खरीदारी को वैश्विक वृहद चिंताओं में कमी, खासकर अमेरिका के नरम महंगाई आंकड़ों से समर्थन मिला है।

- फरवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में 19,675 करोड़ रुपये निवेश किए

कवायद | **पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन योजना में इक्विटी निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 फीसदी कर सकता है**

सरकारी कर्मी एनपीएस में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी में निवेश सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सीमा को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अपने कोष पर लंबी अवधि में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिल सकेगा।

खबरों के अनुसार, पेंशन नियामक ने संकेत दिए कि सरकार इक्विटी निवेश को सुरक्षित और निरंतर वृद्धि के आधार पर आगे बढ़ाने चाहती है। घटते ब्याज दरों के माहौल में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है।

इसी के चलते नियामक ने सरकारी कंपोजिट एनपीएस योजना में शेयर निवेश को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया है और उसे आगे बढ़ाकर 25 फीसदी करने की तैयारी है। इसका सीधा असर सेवानिवृत्ति कोष पर पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में अधिक निवेश लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। पीएफआरडीए का कहना है कि पेंशन फंड संभवतः सरकारी कर्मचारियों की मांग के अनुरूप नई 25 प्रतिशत की सीमा की ओर धीरे-धीरे बढ़ेंगे, जिन्होंने अधिक इक्विटी आवंटन की मांग की है।

बॉन्ड में निवेश कम हुआ

जैसे-जैसे शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है, वैसे ही कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश थोड़ा कम हुआ है जबकि सरकारी प्रतिभूतियों (जीएसईसी) में निवेश का अनुपात लगभग पहले जैसा ही बना हुआ है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि उम्मीद है कि लंबे समय में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर रिटर्न बनाए रखने के लिए नियामक नए निवेश विकल्पों पर विचार कर रहा है।

19 फीसदी तक बढ़ाई जा चुकी है इक्विटी शेयरों में निवेश की सीमा, पहले यह 15% थी

नए विकल्प संभव

इसके अलावा, पेंशन नियामक एनपीएस में एक नए परिसंपत्ति वर्ग के रूप में वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक इसमें कोई निवेश नहीं किया गया है लेकिन इसकी संचालन प्रणाली तैयार कर ली गई है। चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इसमें पहला निवेश किया जा सकता है। नियामक ने वैकल्पिक निवेश श्रेणी के तहत सीमित सीमा के साथ गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी निवेश की अनुमति दी है लेकिन इसके लिए सख्त सीमाएं तय की गई हैं।

कारोबारी चर्चा

कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव

एल.के. सिंहानिया एजुकेशन सेंटर में नए सत्र के लिए रिकॉर्ड एडमिशन, देशभर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया

एल.के. सिंहानिया एजुकेशन सेंटर, गोटन में सत्र 2026-27 के एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विद्यालय के उपप्राचार्य प्रणय कुमार और आईटी हेड संदीप शर्मा तथा अन्य सहकर्मी देश के विभिन्न शहरों में जन-संपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने एडमिशन विभिन्न राज्यों उत्तर-पूर्व, असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। फरवरी से विद्यालय राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है।

पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी मंच बना सिंघानिया विश्वविद्यालय

पचेरी बड़ी स्थित मारवाड़ इंडोर एरीना में 3 से 5 फरवरी तक पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 सह ट्रायल चयन का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं पैरा थ्रोबॉल सोसाइटी राजस्थान के तत्वावधान में किया गया, जिसकी मेजबानी सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई। उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉ. मनोज कुमार (सेवानिवृत्त आईएएस), मुख्य अतिथि ओलंपिक्स जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान, गेस्ट ऑफ ऑनर अल्बर्ट प्रेम कुमार तथा कार्यक्रम की अध्यक्ष निर्मला रावत की गरिमामयी उपस्थिति रही।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, शिक्षाविद डॉ. अतुल कोठारी ने किया संबोधित

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 11 से 13 फरवरी, 2026 तक आयोजित की कई।

'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास' विषय पर आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यशाला के भव्य उद्घाटन पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि अच्छी आदतें ही वास्तविक मूल्यों की पहचान होती हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करता है, वही नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर रहता है।

पीएनबी ने अपने 13वें स्थापना दिवस के पूर्व 'पीएनबी सोल्जरथॉन 2026' की घोषणा की

देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने द्वारका स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में 'पीएनबी सोल्जरथॉन 2026' की घोषणा की, जो बैंक के 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत का प्रतीक है। यह पीएनबी की इस प्रतिष्ठित मैराथन का दूसरा संस्करण है और इस वर्ष, यह हाफ मैराथन 'सोल्जरथॉन' थीम के तहत आयोजित की जा रही है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता के साथ-साथ फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के संकल्प को दोहराती है। प्री-लॉन्च समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर डॉ. सुरेंद्र पूनिया (वीएसएम), लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर और भारतीय सेना के पूर्व स्पेशल फोर्सेस अधिकारी शामिल हुए।

ग्लोबल एजुकेशन की ओर कदम: JUIT छात्रों का अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश

जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेयूआईटी), वाकनाघाट, अमेरिका के साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसडी माइंस) और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से अपने वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत कर रहा है। एसडी माइंस के साथ नवगठित त्वरित मास्टर कार्यक्रम के तहत, जेयूआईटी के बी. टेक छात्रों को न केवल पहले की तरह अमेरिका में अपना आठवां सेमेस्टर पूरा करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे सीधे मास्टर डिग्री में प्रवेश भी ले सकते हैं। एक अन्य उपलब्धि के रूप में, जेयूआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के बी.टेक छात्र सात्विक (मंडी, हिमाचल प्रदेश) ने छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है।

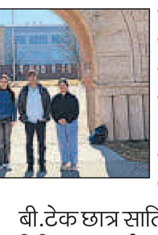

सी. वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बजाज (BEST) सर्विस टेक्नीशियन एक्सीलेंस प्रोग्राम का उद्घाटन

बजाज ऑटो फाउंडेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के तौर पर सी. वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के तौर पर टाटा STRIVE के साथ मिलकर 9 फरवरी को बजाज सर्विस टेक्नीशियन एक्सीलेंस प्रोग्राम (STEP) का उद्घाटन किया। बजाज STEP, बजाज ऑटो फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को फ्री, शॉर्ट टर्म, स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए नौकरी दिलाने की काबिलियत बढ़ाना है। यह हैंड्स-ऑन प्रोग्राम टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर ऑटोमोटिव सर्विस सेक्टर में एंट्री-लेवल नौकरी के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड का Q3 एवं 9M F 26 में मजबूत प्रदर्शन

इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड (BSE SME: 543620), भारत की अग्रणी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी, ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौ महीनों के लिए अपने अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम घोषित किए। Q3 FY26 के दौरान कंपनी ने 356 MW का उत्पादन और 364 MW का डिस्पैच किया। कंपनी की कुल स्थापित सोलर मॉड्यूल क्षमता 5.5 GW तक पहुंच चुकी है। चेयरमैन श्री मनीष गुप्ता ने कहा, Q3 FY26 में हमारा EBITDA ₹81.7 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। यह मजबूत प्रदर्शन बेहतर उत्पाद मिश्रण, सख्त लागत नियंत्रण और ऑपरेटिंग लीवरेज का परिणाम है। सेक्टर में मूल्य अस्थिरता के बावजूद हमने 14% EBITDA मार्जिन बनाए रखा है और FY25 के पूरे वित्तीय प्रदर्शन को 9M FY26 में ही पार कर लिया है।

मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन ने कहा, ऑटोमेशन, गुणवत्ता और एंड-टू-एंड विनिर्माण नियंत्रण हमारी रणनीति का केंद्र है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भव्य ई-नीलामी फरवरी-मई 2026 कार्यक्रम जारी

जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में प्राधिकरण की आय के स्त्रोत बढ़ाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रम में आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण की विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं के भूखण्ड़ों हेतु माह फरवरी-मई 2026 का ई-नीलामी कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। निदेशक वित्त मंजीत चारण ने बताया कि यह कार्यक्रम 25 फरवरी से 7 मई तक विभिन्न योजनाओं के आवासीय, व्यावसायिक एवं फार्म हाउस भूखण्डों सहित कुल 150 भूखण्डों की नीलामी की जाएगी। आवेदकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों को क्रय करने हेतु नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने के साथ-साथ ऑनलाईन बिड लगाते हुए ई-नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी की प्रक्रिया अरबन सर्विसेज के माध्यम से की जाएगी।

एडमस यूनिवर्सिटी ने गवर्नर की मौजूदगी में 9वें दीक्षांत समारोह का किया आयोजन

एडमस यूनिवर्सिटी ने बारासात कैंपस में अपने 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जो एक अहम अकादमिक उपलब्धि रही, क्योंकि इस अवसर पर अलग-अलग विधाओं के 1,527 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इसके अलावा, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए 12 गोल्ड मेडल और 20 सिल्वर मेडल भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के माननीय गवर्नर डॉ. सी. वी. आनंद बोस, एडमस यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रो. समित रे और एडमस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. सुरंजन दास, खास मेहमानों में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. टी. जी. सीताराम, वीएलएसआई सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सत्य गुप्ता और ए. के. चौधरी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रो. अमलान चक्रवर्ती शामिल थे। इस अवसर पर, जानी-मानी हस्तियों इंद्रजीत मित्रा, आशीष अग्रवाल, अजीत सिंह और प्रीतम नागरीगरी को मानद डॉक्टरेट (ऑनोरिस कॉसा) की उपाधि प्रदान की गई।

संपादकीय जागरण
सोमवार, 16 फरवरी, 2026 : फाल्गुन कृष्ण - 14 वि. 2082
सफलता का रहस्य है दृढ़ संकल्प, परिश्रम और साहस

एआइ शिखर सम्मेलन

नई दिल्ली में शुरू हो रहे एआइ इंपैक्ट शिखर सम्मेलन की महत्ता केवल इसलिए नहीं है कि यह एक पांच दिवसीय वैश्विक आयोजन है। इसका महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इसमें 15 से अधिक देशों के शासनाध्यक्षों के साथ 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। विश्व भर के एआइ विशेषज्ञ एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी इस सम्मेलन के आकर्षण को और बढ़ा रही है। इस आयोजन के प्रति दिलचस्पी को इससे समझा जा सकता है कि दो लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। एक तरह से यह सम्मेलन जी 20 शिखर सम्मेलन से भी अधिक प्रभावशाली एवं विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला हो सकता है। चूंकि यह भविष्य पर केंद्रित एक व्यापक सम्मेलन है, इसलिए यह आशा की जाती है कि इसके जरिये एआइ को एक जिम्मेदार, टिकाऊ और समावेशी तकनीक के रूप में विकसित एवं विस्तारित करने पर सहमति बनेगी। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व भर में एआइ का प्रभाव और उसका बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में एआइ का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह सर्वथा उचित है कि इस सम्मेलन में एआइ की चुनौतियों से निपटने पर भी विचार-विमर्श होगा, लेकिन बात तब बनेगी जब उससे निपटने के किसी प्रभावी तंत्र पर सहमति भी बनेगी। यह सहमति इसलिए आवश्यक है, क्योंकि फिलहाल एआइ पर चंद बड़े राष्ट्रों का ही वर्चस्व कायम है। यदि इस तकनीक का प्रसार अविकसित एवं निर्धन देशों तक नहीं पहुंचता तो इससे दुनिया में विषमता और अधिक बढ़ेगी ही। एआइ का उपयोग समावेशी, नैतिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसके लिए मेजबान भारत के साथ-साथ सभी देशों को प्रयत्न करने होंगे।

तकनीक के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रत्येक तकनीकी विकास अपने साथ कुछ विसंगतियां एवं खतरे भी लाता है। एआइ के साथ तो ऐसा कुछ अधिक ही है। इसके दुरुपयोग के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। निःसंदेह एआइ विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग जिस तरह बढ़ रहा है, उससे उपयोगकर्ताओं के बीच उसके प्रति विश्वसनीयता और भरोसे का संकट पैदा हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि एआइ का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों पर डाली जाए और इसके लिए उन्हें जवाबदेह भी बनाया जाए। एआइ अपने साथ जो चुनौतियां लेकर आई है, उनमें एक यह भी है कि उसके कारण कई परंपरागत नौकरियां खत्म हो रही हैं। निःसंदेह यह तकनीक परंपरागत नौकरियों को खत्म करने के साथ नई नौकरियों का सृजन भी कर रही है। एक तरह से एआइ चुनौतियों के साथ अवसर भी है। भारत को इस अवसर को भुनाने के लिए अपने लोगों को एआइ के उपयोग के प्रति सक्षम बनाने के लिए और अधिक सक्रियता दिखानी होगी।

ठोस प्रयास जरूरी

बाहरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में एक कारोबारी की हत्या की साजिश रच रहे शार्प शूटर को दिल्ली पुलिस ने हमले से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जो सराहनीय है। दिल्ली में संगठित अपराध, जबरन वसूली, हथियारों से लैस अपराधियों के हमले और हथियारों के गैर-कानूनी इस्तेमाल की घटनाओं में खासी वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे संगठित अपराधों के बीच इस शार्प शूटर की गिरफ्तारी कुछ हद तक संतोष की बात है कि पुलिस ऐसे खतरनाक अपराधियों पर नजर रख रही है और इनकी धर-पकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने तीन मामले सुलझाने का भी दावा किया है। राजधानी में संगठित अपराध कोई नई बात नहीं है। यहां कई गैंग सक्रिय हैं और कारोबारियों से उगाही, जान से मारने की धमकी, घर या कार्यालय पर फायरिंग और हत्या भी होती रही हैं। निराशाजनक यह है कि समय के साथ दिल्ली पुलिस का सर्विलांस सिस्टम मजबूत होने और तकनीकी रूप से दक्षता बढ़ने के बावजूद इन संगठित गिरोहों पर नकेल कसने में पुलिस सफल नहीं हो पा रही है। देश के किसी दूरदराज के इलाके की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी में भी कारोबारियों से उगाही जारी है। दिल्ली पुलिस को इसे एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और संगठित अपराध को राजधानी में जड़ से खत्म करना चाहिए।

> कारोबारियों से उगाही करने वाले गिरोह को एक चुनौती की तरह लेकर दिल्ली पुलिस को इन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहिए

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सेवा-तीर्थ जैसी पहल औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाने में उपयोगी होगी?

आज का सवाल

क्या एआइ समिट के आयोजन से इस उभरते तकनीकी परिदृश्य पर भारत का कद और मजबूत होगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

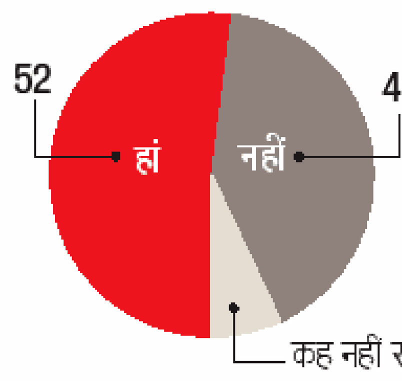

व्यापार समझौतों से आगे की चुनौतियां

शिवकांत शर्मा

मुक्त व्यापार समझौतों से भारत के लिए बड़े बाजारों के द्वार तो खुल गए, पर उसका फायदा तभी मिलेगा जब बेहतर उत्पाद किफायती दामों पर तैयार हो सकें

दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो व्यापार के बिना केवल आत्मनिर्भरता के बल पर आर्थिक महाशक्ति बना हो। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार भारत भी व्यापार के बल पर आर्थिक महाशक्ति बना था। उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के एक चौथाई से अधिक हो गई थी जिसके बल पर वह सोने की चिड़िया कहलाता था। आधुनिक युग में ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हर देश व्यापार के बल पर ही आर्थिक महाशक्ति बना है और अब चीन भी उसी राह पर है। उसने अमेरिका और यूरोप की मंडियों में धाक जमाने के बाद संरक्षणवाद की दीवारें खड़ी होने से पहले ही व्यापार समझौतों के द्वारा अपने माल के लिए नई मंडियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। चार साल पहले हुआ आरसीईपी या व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी समझौता उसकी ही एक कड़ी थी, जिसमें चीन और जापान से लेकर न्यूजीलैंड तक फैले 15 देश शामिल थे।

मुक्त व्यापार समझौते आपसी व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक महाशक्ति बनने की राह खोलते हैं। भारत ने भी यूरोप के साथ समझौता करके और अमेरिका के साथ उसकी रूपरेखा तय करके ऐसी ही राह खोली है। अमेरिका और यूरोप से पहले वह आसियान, जापान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ओमान, मारीशस और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार सदस्य देशों से व्यापार समझौते कर चुका है। खाड़ी सहयोग परिषद के साथ व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ताएं चल रही हैं। इन सबके पूरा होने पर दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक जीडीपी के बाजार भारत के लिए खुल जाएंगे। अर्थव्यवस्था को 40 वर्षों तक संरक्षणवाद की दीवारों में कैद कर दिवालिया कर लेने वाले देश के लिए यह परिवर्तन कायाकल्प से कम नहीं है।

यह भी सच है कि व्यापार समझौते और बड़ी-बड़ी मंडियों में प्रवेश पाने भर से भी कोई देश व्यापारिक और आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता। उसके लिए आकर्षक दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला माल बनाना और बेचना पड़ता है। लाइसेंस राज और बाबूशाही के शिकंजे खोलकर उद्योग लगाना सुगम बनाना पड़ता है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में शोध, विकास और नवाचार बढ़ाने के साथ-साथ उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना होता है, जिनमें देश दूसरों से आगे हो। पूंजी को सुलभ बनाना और बुनियादी सुविधाओं को सुधारना होता है। इन्हीं उपायों से चीन ने ट्रंप की टैरिफ जंग में भी अपना व्यापार बढ़ाकर भारत की जीडीपी से डेढ़ गुना कर लिया है। आज विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3.5 प्रतिशत है जबकि चीन की

अवधेश राजपूत

लगभग 14 प्रतिशत। अपने स्वर्णिम युग के दिनों में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत के आसपास थी।

बीते दिनों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर की चीन यात्रा के दौरान एक ब्रिटिश साइकिल निर्माता से पूछा गया कि चीन और अमेरिका में कहां कारोबार करना अधिक सुगम है? उसने तपाक से जवाब दिया चीन में, जहां कुछ ही हफ्तों के भीतर कारोबार संभव है और व्यापार नीति को लेकर भी निश्चितता रहती है। भारत को भी बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कारोबारियों में इसी तरह का भरोसा पैदा करना होगा। केंद्र के साथ राज्यों की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा, क्योंकि उद्योगों को पूंजी के अलावा जमीन, कर्मचारी, बिजली और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसे निवेश आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने के बजाय दिक्कतें खड़ी करने में लगे रहते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि तमिलनाडु का शहर तिरुपुर परिधान उद्योग का नया मैनचेस्टर बन सकता है, मगर कोलकाता और कानपुर वस्त्र उद्योग में अपनी खोई चमक को फिर से हासिल नहीं कर पाते? बंगाल की आबादी वियतनाम के बराबर है, मगर जीडीपी उससे आधी है। बिहार की आबादी वियतनाम से सवा गुनी है और जीडीपी एक चौथाई है। विकास की दौड़ में यदि आप 20 साल लंबी लड़ाई से तबाह हुए देश की बराबरी भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे?

व्यापार समझौते कर भारत ने अमेरिका, यूरोप, जापान और रूस जैसी विश्व की अमीर मंडियों के द्वार तो खुलवा लिए हैं, परंतु इनमें अपने माल की मांग बढ़ाने के लिए उसकी गुणवत्ता में निरंतर परिष्कार करना और उसे आकर्षक दामों पर बेचना होगा। उत्पादन का पैमाना बढ़ाए और शोध एवं विकास में निवेश किए बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। चीन और वियतनाम शोध एवं विकास पर अपने बजट का 2.5 प्रतिशत से ऊपर खर्च करते हैं, जबकि भारत मात्र 0.65 प्रतिशत। ट्रंप की टैरिफ जंग से उठी संरक्षणवाद की लहर में रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता सबसे अहम हो गई है, जो शोध एवं विकास में भारी निवेश के बिना संभव नहीं।

आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अब व्यापार बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। भारत को एआइ और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों और इनके लिए आवश्यक ऊर्जा की तकनीक में भी आगे रहना होगा। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में एआइ डाटा केंद्र बनाने के लिए लगभग 8,000 करोड़ डालर के निवेश का वादा किया है। इनमें एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट, गूगल और इंटेल जैसे नाम शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार घटते विदेशी निवेश से जूझती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यकीनन यह बहुत अच्छी खबर है। हालांकि इनके लिए जितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी, उसे पश्चिम के विकसित देश भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डाटा केंद्रों और भारी ऊर्जा खपत वाले एआइ माडल तैयार करने के लिए भारत को भी अपना ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर चीन के पैमाने पर लाना होगा जो इस समय अमेरिका से भी ढाई गुना बिजली पैदा कर रहा है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा के लिए सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना होगा, ताकि देश की हवा भी सांस लेने लायक बनी रहे। आज से दिल्ली में शुरू हुए एआइ प्रभाव शिखर सम्मेलन में इस प्रश्न के साथ-साथ एआइ को समावेशी, जन और जलवायु अनुकूल बनाने पर भी चर्चा होगी। इस सम्मेलन से भारत में एआइ के विकास, प्रयोग और निवेश को गति मिलने की आशा है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

विकसित भारत का आधार बनें एमएसएमई

ऋतु सारस्वत

यदि एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, तो वे विकसित भारत के आधार को सुदृढ़ कर सकते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ ने बीते दिनों बैंकों के लिए माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज (एमएसई) को गिरवी मुक्त या बिना किसी गारंटी के ऋण देने की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया। इस वर्ष अप्रैल के बाद से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋण पर रिजर्व बैंक का यह फैसला प्रभावी होगा। 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज' ऋण लेने वाले उद्यमियों की गारंटी लेगा। निश्चित रूप से आरबीआइ की यह पहल एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर पहल सिद्ध होगी। ध्यातव्य रहे कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने एमएसएमई की क्रेडिट सुविधा बढ़ाने और उनके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 बताती है कि एमएसएमई भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 35.4 प्रतिशत, कुल निर्यात का लगभग 48.58 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 31.1 प्रतिशत योगदान करता है। देश में 7.47 करोड़ से अधिक उद्यम, जो लगभग 32.82 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इस क्षेत्र को कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगारप्रदाता बनाते हैं। वैश्विक स्तर पर भी लगभग 90 प्रतिशत व्यवसाय एमएसएमई स्वरूप में ही हैं और कुल वैश्विक रोजगार का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रदान करते हैं। भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक एकीकरण की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में एमएसएमई की भूमिका प्रभावी आपूर्ति-श्रृंखला, स्थानीय मूल्य संवर्धन और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि 2024 में 'उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस' के अवसर पर यशस्विनी अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 2029 तक लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की सार्वजनिक खरीद में न्यूनतम तीन प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना है। गत वर्ष मिजोरम में संचालित अभियान से लगभग 8,400 महिला

एमएसएमई की समस्याओं पर देना होगा ध्यान ● फाइल

स्वामित्व वाले एमएसएमई का पंजीकरण संभव हुआ। इसके तहत अब तक 12.5 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण को सुगम बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआइडीओ) द्वारा प्रकाशित 'औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2024' में भारत का उल्लेख उभरती औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे देशों में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार तेजी से हो रहा है और औद्योगिक विविधीकरण बढ़ रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी मजबूत करने की क्षमता रखता है। हालांकि एमएसएमई क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कुछ संरचनात्मक चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। भुगतान में देरी की समस्या, तकनीकी आधुनिकीकरण की कमी, सीमित वैश्विक ब्रांड पहचान जैसे मुद्दे इस क्षेत्र की गति को प्रभावित करते हैं। पंजीकरण की संख्या निश्चित रूप से एक सशक्त तस्वीर पेश करती है, परंतु उसके साथ आवश्यकता प्रति उद्यम उत्पादकता, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने की है। यदि इन चुनौतियों का समाधान समयबद्ध एवं प्रभावी नीति के जरिये किया जाए तो एमएसएमई देश की आर्थिक छलांग का बड़ा आधार बन सकते हैं।

दक्षिण कोरिया और जापान की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता में लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। दक्षिण कोरिया ने 'लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रूपरेखा अधिनियम (फ्रेमवर्क एक्ट आन स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज)' तथा 'लघु, मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ एसएमईज एंड स्टार्टअप्स)' के माध्यम से छोटे उद्योगों को अनुसंधान-विकास सहायता, स्केल-अप रणनीति और कानूनी संरक्षण से जोड़ा है। वहीं दूसरी ओर जापान ने 'लघु एवं मध्यम उद्यम मूल अधिनियम (स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज बेसिक एक्ट)' के तहत अपने उद्योगों को आपूर्ति-श्रृंखला आधारित 'केइरेत्सु' माडल, उच्च गुणवत्ता मानकों और तकनीकी नवाचार से सशक्त किया। इन दोनों माडलों की समानता यह है कि उन्होंने एमएसएमई को केवल पोषणात्मक व्यवस्था ही प्रदान नहीं की है, अपितु उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाने की संरचित व्यवस्था विकसित की। यदि भारत भी इसी प्रकार स्पष्ट स्केल-अप नीति और गुणवत्ता-प्रधान औद्योगिक समन्वय को सुदृढ़ करे, तो एमएसएमई 'विकसित भारत' की आधारशिला को और अधिक मजबूत बना सकते।

आर्थिक-सामाजिक विकास में एमएसएमई कम पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार सृजित करता है, सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों को सहयोग देता है और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देता है। ऐसे में भारत को एमएसएमई के लिए दीर्घकालिक और किफायती पूंजी उपलब्ध कराने, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात-उन्मुख ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देने की दरकार है। समयबद्ध भुगतान तंत्र का क्रियान्वयन और हरित उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहन भी अनिवार्य होंगे। यदि एमएसएमई को केवल संरक्षण नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की स्पष्ट रणनीति दी जाए, तो वे विकसित भारत की आर्थिक संरचना को निर्णायक रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परमात्मा से द्वंद्व क्यों

परमात्मा दयालु है। वह कृपा कर मनुष्य को बहुत कुछ दे रहा है। मनुष्य पहले अपना स्वार्थ देखता है, फिर कुछ धारण करता है। स्वार्थ नहीं, तो परमात्मा को भी नकार देता है। परमात्मा ठंड देता है, तो वह गर्मी ढूंढ़ता है। वह गर्मी देता है, तो ठंड के प्रबंध में लग जाता है। परमात्मा के दिए वृक्ष नहीं भाते, तो काट देता है। स्वार्थ हो, तो कृत्रिम पौधों, फूलों से घर को सजाता है। पर्वत को गिरा रहा है, नदियां बांध रहा है।

मनुष्य के अधिकांश दुख इस कारण हैं कि उसका आचरण अपने सृजनकर्ता परमात्मा के अनुकूल नहीं है। यह सृष्टि की व्यवस्था में विरोधाभास उत्पन्न करता है। कभी परमात्मा की बनाई पद्धति को समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता। इसके विपरीत उसमें संशोधन के कार्य अवश्य मानव सभ्यता के विकास के काल से ही होते आए हैं। सुधार का अधिकार उसे होता है, जो रचनाकार से अधिक ज्ञानवान हो। सुधार सदैव उत्कृष्टता हेतु किए जाते हैं, किंतु अज्ञानी के सुधार जटिलताएं पैदा करते हैं। आज जीवन जितना चुनौतीपूर्ण हो गया है, वह इसी का परिणाम है। परमात्मा की व्यवस्था में हस्तक्षेप सदैव मूर्खता सिद्ध हुई है। मनुष्य का ज्ञान बढ़ा है, अहंकार बढ़ा है और सृष्टि में हस्तक्षेप का दुस्साहस बढ़ा है।

सहजता और सरलता में ही सुख है। यह परमात्मा के अनुकूल होने से ही संभव है। सृष्टि जैसी उसने रची है, उसे स्वीकार करने और उसका संरक्षण करने में मनुष्य का हित है। सृष्टि में परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं। पुष्प मुरझा जाते हैं, तो नई कलियां स्वयं आ जाती हैं। अधिक गर्मी हो तो मेघ बरसने लगते हैं। हम थकते हैं, तो नींद घेर लेती है। यह अवर्णनीय प्रक्रिया व्यापक स्तर पर, हर क्षेत्र में युगों-युगों से चल रही है। परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। परमात्मा हमारा जनक है, उसे स्वयं हमारी चिंता है। उसके नियमों में रह कर तो देखें।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

शहरों की सुध

संपादकीय 'शहरों के विकास का एजेंडा' पढ़ा। शहरों की चमक-दमक और रोजगार के अवसर लोगों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गांव सिकुड़ते जा रहे हैं और शहरों का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। छोटे शहर तेजी से बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन यह विस्तार योजनाबद्ध नहीं है। शहर बढ़ती आबादी का बोझ उठाने में सक्षम नहीं रह गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 'अर्बन चैलेंज फंड' की स्वीकृति शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और आधारभूत सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए शहरों के सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस योजना के माध्यम से केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास सराहनीय है। नगर निकायों की क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। शहरी विकास को पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ जल और किफायती आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का समाधान करना चाहिए। यदि योजना को दीर्घकालिक दृष्टि, जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू किया गया, तो शहर न केवल रहने योग्य बनेंगे, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के सशक्त केंद्र भी साबित होंगे।

himanshushekhar.mca@gmail.com

बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता

पिछले डेढ़-दो वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति में जिस प्रकार के उथल-पुथल भरे घटनाक्रम देखने को मिले, उन्होंने न केवल वहां की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। छात्र आंदोलनों और व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और अंतरिम व्यवस्था के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतरिम शासन से अपेक्षा थी कि वह देश में शांति, राजनीतिक संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, किंतु इस अवधि में कट्टरपंथी समूहों की सक्रियता और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं ने चिंताएं बढ़ाईं। इन घटनाओं ने वैश्विक मंच पर बांग्लादेश की छवि को प्रभावित किया और कई विश्लेषकों ने इसे अस्थिर राजनीतिक दौर का परिणाम बताया। हालिया चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत और अवामी लीग के कमजोर पड़ने से देश के सत्ता संतुलन को बदल दिया है। नई सरकार से अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू समाज, सुरक्षा और सम्मान की अपेक्षा कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यह भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश का आर्थिक भविष्य क्षेत्रीय सहयोग पर काफी हद तक निर्भर करेगा। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ व्यावहारिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने में सफल होती है, तो यह न केवल सामाजिक सौहार्द की दिशा में बल्कि आर्थिक प्रगति के लिए भी ऐतिहासिक कदम सिद्ध हो सकता है।

arvind.rawal69@gmail.com

सिमटती जिंदगी की रफ्तार

लखनऊ में 12वीं के छात्र द्वारा चलाई जा रही कार की टक्कर से छह लोगों के घायल होने और एक मासूम बच्चे की मृत्यु की घटना केवल समाचार नहीं होती, बल्कि समाज के भीतर बढ़ती एक गंभीर समस्या का आईना होती है। इससे पहले कानपुर में भी तेज रफ्तार कार से लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई थीं। कम उम्र में वाहन चलाने का उत्साह अक्सर जिम्मेदारी की समझ से बड़ा हो जाता है। अनुभव की कमी और जोखिम को रोमांच समझने की मानसिकता के अलावा दिखावा करने की प्रवृत्ति, तेज गति को कौशल मान लेने की गलत सोच और शराब या नशे के प्रभाव में वाहन चलाना इन हादसों को जन्म देता है। कई परिवार अनजाने में अपने बच्चों को महंगी और शक्तिशाली गाड़ियां तो दे देते हैं लेकिन सड़क अनुशासन, धैर्य और मानव जीवन की कीमत का पाठ नहीं पढ़ा पाते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि किसी घर का सहारा, किसी मां की उम्मीद, किसी पिता का गर्व, किसी बच्चे का भविष्य और किसी जीवनसाथी का संबल एक ही पल में छिन जाता है। हर युवा को यह समझना होगा कि सड़क पर उसकी एक गलती किसी अनजान व्यक्ति के पूरे परिवार का भविष्य समाप्त कर सकती है। सख्त लाइसेंस व्यवस्था, कम उम्र में वाहन चलाने पर कठोर कार्रवाई, अभिभावकों की जवाबदेही तय करना, स्कूल स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा और समाज में यह भावना विकसित करना कि वाहन चलाना अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

X पोस्ट

बांग्लादेश में 35 वर्षों में पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दुनिया में ऐसे विरले ही देश हैं।

डेविड बर्गमैन@TheDavidBergman

अगर कोई कहे कि देश के प्रधानमंत्री सवालों से परे हैं तो यह सही नहीं। भारतीय परंपरा में तो भगवान से भी सवाल किए जाते हैं।

संजय दीक्षित@Sanjay_Dixit

मुझे लगता है कि कांग्रेस के राजनीतिक पराभव में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी वजह नहीं रही, जितना बड़ा कारण पार्टी के नेताओं का अहंकारी रवैया रहा। यह बात इस समय सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी याद रखनी चाहिए।

अमित शाडिल्य@Schandillia

एआइ बड़ी ताकतवर तकनीक है। इससे लोग शानदार और उपयोगी कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रामक और गलत वीडियो भी तैयार कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें।

दिनेश कुमार@DineshRedBull

जनपथ

'टीपू जी' का दल करे टीपू का सम्मान,
उसके लिए महान है बस टीपू सुल्तान।
बस टीपू सुल्तान नहीं कम है कांग्रेसी,
रहे मियां ढाबे देख शिवा और राणा जैसी।
जो दिलवाए वोट वही छवि जाए पूजी,
पूज रही कांग्रेस उसे पूजे 'टीपू जी'!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जैतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 213

किस राह बांग्लादेश!

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 210 सीटें जीत कर करीब दो तिहाई बहुमत हासिल किया है। इससे बांग्लादेश में एक स्थिर निर्वाचित सरकार का रास्ता साफ हो गया है। धार्मिक कट्टरता और अपनी अतिवादी सोच के लिए जानी जाने वाली जमात-ए-इस्लामी की अगुआई वाले गठबंधन को लोगों ने नकार दिया है। चुनाव में बांग्लादेश के लोगों ने संविधान में बदलाव के पक्ष में वोट किया है। इसका मतलब है कि संविधान में बदलाव किए जाएंगे और इसके तहत प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रपति के पद को सशक्त बनाया जाएगा। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का माहौल है। खासकर एक करोड़ हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह देखना होगा कि बीएनपी की अगुआई में नई सरकार बांग्लादेश में स्थिरता कायम कर पाती है या नहीं। भारत के लिए भी एक मौका है कि वह नई सरकार के साथ काम करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाए, जो यूनुस सरकार में निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नई सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश एक उदार और समावेशी लोकतंत्र का रास्ता चुनेगा या अतिवादी सोच वाली इस्लामी ताकतें हावी होंगी, इसकी पड़ताल आज प्रासंगिक है...

भारत-बांग्लादेश: सहयोगपूर्ण लेकिन जटिल संबंध

- बंगाल क्षेत्र साझा भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहा है।
- 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की सहायता ने स्थायी मित्रता की नींव रखी।
- साहित्य, संगीत, भोजन और त्योहारों में समानता।

राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग

1972 मैत्री संधि। | 2015 भूमि सीमा समझौता- दशकों पुराने एन्क्लेव विवाद समाप्त।

- उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं और संवाद।

लोकतंत्र और स्थिरता

- लोकतांत्रिक सरकारों के दौरान संबंध अधिक मजबूत रहे।
- राजनीतिक बदलावों से कभी-कभी दूरी भी आई।

सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग

- पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई।
- सीमा पार आतंकवाद पर नियंत्रण।

सीमा प्रबंधन

- लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की संयुक्त निगरानी।
- तस्करी और मानव तस्करी रोकने के प्रयास।

समुद्री सहयोग

बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन।

आर्थिक और व्यापारिक सहयोग

- बांग्लादेश भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार।
- वस्त्र, दवाइयां, मशीनरी और खाद्य उत्पादों का व्यापार।

कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- रेल, सड़क और जलमार्ग संपर्क।
- ऊर्जा सहयोग और बिजली आपूर्ति।

क्षेत्रीय संपर्क

- पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को गति।

जल संसाधन और पर्यावरण सहयोग

- साझा नदियों के जल प्रबंधन पर सहयोग।
- 1996 गंगा जल संधि।
- तीस्ता नदी जल बंटवारा अभी भी लंबित मुद्दा।
- बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग आवश्यक।

सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क

- शैक्षणिक आदान-प्रदान और छात्रवृत्तियां।
- फिल्म, संगीत और मीडिया सहयोग।
- धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन।

भारत-बांग्लादेश व्यापार हाल के वर्ष में

(भारत को बांग्लादेश के साथ बड़ा व्यापार अधिशेष मिलता है।)

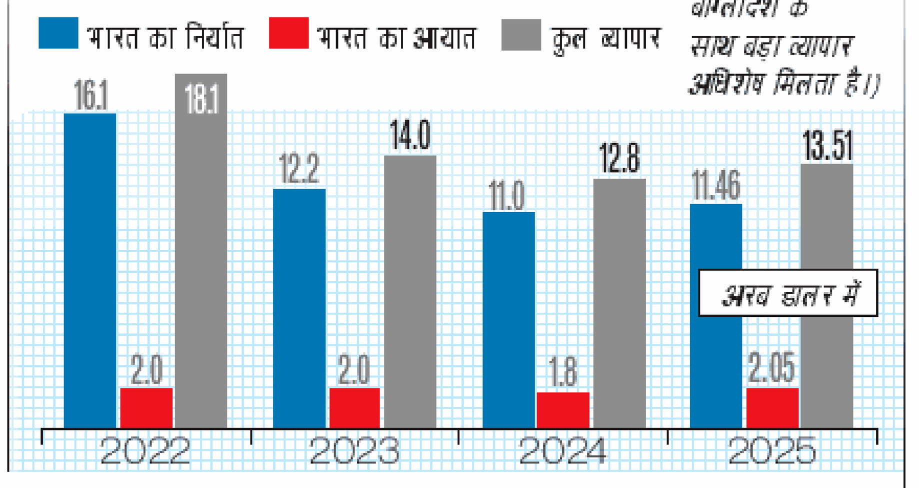

संबंधों की जटिलताएं

सुरक्षा: अवैध आव्रजन और सीमा सुरक्षा चिंताएं।

व्यापार असंतुलन: बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार घाटे की चिंता जताता है।

जल बंटवारा विवाद: विशेषकर तीस्ता जल समझौता लंबित।

घरेलू राजनीति का प्रभाव: राष्ट्रवादी भावनाएं और आंतरिक राजनीति संबंधों को प्रभावित करती हैं।

चीन का बढ़ता प्रभाव: बुनियादी ढांचा निवेश और रणनीतिक संतुलन का मुद्दा।

4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं भारत- बांग्लादेश

475 अरब डालर है बांग्लादेश की जीडीपी का आकार वर्तमान में

भारत की तुलना में तेजी से बढ़ा है चीन का निवेश

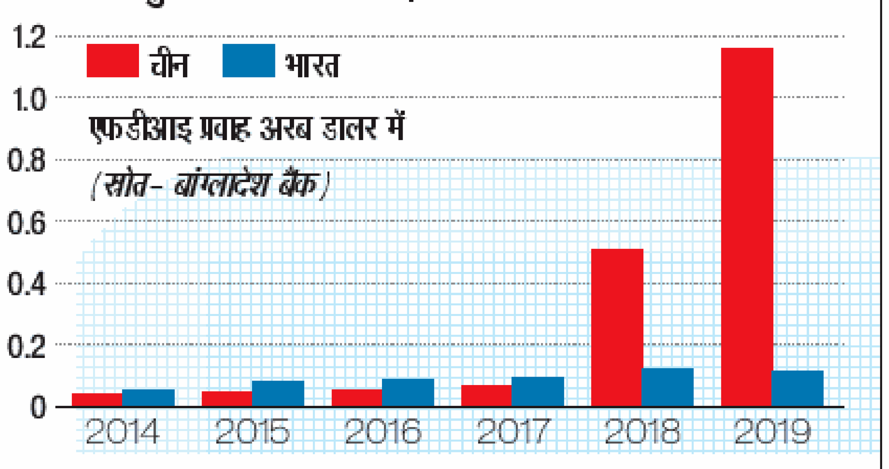

बांग्लादेश में चीन और अमेरिका की बढ़ती भूमिका

चीन का निवेश

- बंदरगाह, पुल, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश
- पदमा ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट में सहयोग
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) के तहत रणनीतिक पहुंच बढ़ाना
- सैन्य सहयोग (चीन-बांग्लादेश)
- बांग्लादेश की सेना को हथियार और नौसैनिक उपकरण की आपूर्ति
- पनडुब्बियां और रक्षा तकनीक सहयोग

अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति

- अमेरिका का क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर जोर
- लोकतंत्र, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार के नाम पर रणनीतिक साझेदारी
- समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की कोशिश

भारत की सुरक्षा चिंताएं

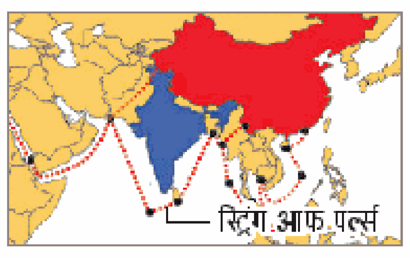

रणनीतिक घेराबंदी का खतरा

- चीन की 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' नीति से भारत के चारों ओर रणनीतिक दबाव
- बंदरगाहों और सैन्य पहुंच से निगरानी क्षमता बढ़ सकती है

पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा

- बांग्लादेश की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी है
- बाहरी शक्तियों की उपस्थिति से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है

समुद्री सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी

- बंगाल की खाड़ी में बढ़ती सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां
- भारत के समुद्री व्यापार मार्गों पर संभावित प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव और संतुलन

- बांग्लादेश की विदेश नीति में चीन और अमेरिका का बढ़ता प्रभाव
- भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय भूमिका को चुनौती

जागरण रिसर्च

आंतरिक स्थिरता की बहाली सबके हित में

डा. अभिषेक श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू

बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का असर शरणार्थियों की आवाजाही, अवैध प्रवासन, सीमा तनाव और कट्टरपंथी गतिविधियों के रूप में पड़ सकता है। इसलिए भारत का मुख्य हित यह सुनिश्चित करना है कि अगली सरकार आंतरिक व्यवस्था को बहाल करे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे और कट्टरपंथी नेटवर्क पर नियंत्रण रखे।

ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सत्ता में वापसी भारत की पूर्वी पड़ोस नीति में एक बड़ा बदलाव है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत दबाव और सामाजिक ध्रुवीकरण देखा गया है। अब नई दिल्ली के सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं, यह समय संतुलित और व्यावहारिक कूटनीति अपनाने का है।

पिछले एक दशक से भारत के संबंध अवामी लीग सरकार के साथ काफी मजबूत रहे, सुरक्षा सहयोग बढ़ा, उग्रवादी ठिकानों को खत्म किया गया, कनेक्टिविटी परियोजनाएं तेज हुईं और आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई। खासकर उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को खास फायदा मिला लेकिन लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए भारत को अब तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के साथ काम करने की तैयारी करनी होगी। ढाका की राजनीतिक अस्थिरता अक्सर सीमाओं के भीतर नहीं रहती है इसलिए भारत की पहली प्राथमिकता बांग्लादेश के भीतर स्थिरता होनी चाहिए क्योंकि इसका असर शरणार्थियों की आवाजाही, अवैध प्रवासन, सीमा तनाव और कट्टरपंथी गतिविधियों के रूप में पड़ सकता है। बंगाल और असम विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इसलिए भारत का मुख्य हित यह सुनिश्चित करना है कि अगली सरकार आंतरिक व्यवस्था को बहाल करे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे और कट्टरपंथी नेटवर्क पर नियंत्रण रखे। बांग्लादेश में चल रहे आर्थिक संकट तथा सामाजिक असंतोष के बीच भारत के लिए यह स्थिति जिम्मेदारी और अवसर दोनों लेकर आती है। ऊर्जा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के मामले में बांग्लादेश की भारत पर बड़ी निर्भरता है। भारत से बिजली आपूर्ति बांग्लादेश के बिजली तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रांजिट समझौते भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ते हैं। यदि इन व्यवस्थाओं में बाधा आती है, तो बांग्लादेश को नुकसान होगा। भारत के नजरिये से आर्थिक सहयोग को राजनीतिक उतार-चढ़ाव से अलग रखना जरूरी है। नई दिल्ली को स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि व्यापार, बिजली आपूर्ति और कनेक्टिविटी परियोजनाएं सरकार बदलने से प्रभावित नहीं होंगी। साथ ही, भारत को शांत तरीके से यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश की जमीन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत को दृढ़ रहना होगा।

बीएनपी पर पहले कुछ कट्टरपंथी समूहों के प्रति नरमी के आरोप लगते रहे हैं तथा हालिया चुनाव में कट्टरपंथी और इस्लामी संगठनों ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। खासकर भारत से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी जीत एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत को इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि राजनीतिक बदलाव का फायदा चरमपंथी ताकतें उठा सकती हैं। बंगाल और असम की सुरक्षा स्थिति पहले से ही संवेदनशील है। इसलिए दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग, सीमा निगरानी और आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करना जरूरी होगा।

चीन का पहलू इस पूरी स्थिति को और जटिल बनाता है। चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा, बंदरगाह और औद्योगिक निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाई है। बीएनपी सरकार अपने विदेशी संबंधों में संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में भारत का उद्देश्य चीन को यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि रणनीतिक संपत्तियां, खासकर बंदरगाह, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा न बनें। यहां भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता महत्वपूर्ण होगी। भारत की कई परियोजनाएं चीन की तुलना में धीमी रही हैं, यदि भारत अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, तो उसे समय पर और प्रभावी ढंग से परियोजनाएं पूरी करनी होंगी। बीबीआइएन जैसे क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रमों और पूर्वोत्तर के व्यापार मार्गों को तेज करना होगा। जब बांग्लादेश की आर्थिक समृद्धि भारत की विकास यात्रा से जुड़ जाएगी, तो दोनों देशों की दूरी कम होगी।

भारत के लिए बांग्लादेश उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय स्तंभ है। भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को स्थायी रूप से जोड़ते हैं। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद पारस्परिक सम्मान, समानता और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित होनी चाहिए। भारत का स्पष्ट और निरंतर संदेश यही होना चाहिए कि वह एक स्थिर, समृद्ध, लोकतांत्रिक और संप्रभु बांग्लादेश का पूर्ण समर्थन करता है।

आपकी आवाज

तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तारिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है। कट्टरपंथी पार्टी जमात विपक्ष में अवश्य बैठेगी। मगर उसकी नजरें भारत पर ही रहेंगी। जमात-ए-इस्लामी से आने वाली चुनौती के लिए भारत को तैयार रहना होगा। जमात गठबंधन ने संसद में 75 से अधिक सीटें जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत को अतीत में बीएनपी-नेतृत्व वाले राजनीतिक शासन के साथ काम करने का अनुभव है। **युगल किशोर राही**

हमें नहीं लगता है कि बांग्लादेश में नवनिर्वाचित सरकार तारिक रहमान के राज में भी हमारे देश के साथ संबंध मधुर हो पाएंगे और वहां हिंदुओं के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि यह भी वहां के उन कट्टरपंथी लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे जो हमारे देश के प्रति बेवजह की संकीर्ण मानसिकता पाले बैठे हैं। इन्हें उन लोगों ने चुना है जो शेख हसीना के कट्टर विरोधी थे, हमारे देश ने शेख हसीना को शरण दी और शेख हसीना हमेशा ही हमारे देश के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करती आई हैं, जबकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी हमारे देश के साथ नफरत की भावना भी रखते हैं। **राजेश कुमार चौहान**

बीएनपी के सत्ता में लौटते ही बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का माहौल समाप्त हो जाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि इस चुनाव में दूसरे पायदान पर रहने वाली पार्टी जमात चुनाव नतीजे से संतुष्ट नहीं है। पड़ोसी देश में आंदोलन, हिंसा और राजनीतिक उठा-पटक का एक लंबा इतिहास रहा है जिसका भुक्तभोगी अंततः वहां का अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू होता है। **देवानंद राय**

तारिक रहमान को जमीन पर उतारना होगा समावेशी बांग्लादेश का नारा

ऋषि गुप्ता
विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय मामले

तारिक रहमान ने चुनाव में समावेशी बांग्लादेश का वादा किया था। इसका मतलब है कि बीएनपी सभी नागरिकों की सुरक्षा और उनका विकास सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर खत्म करना है तो इस चुनावी वादे को जमीन पर लागू करना होगा।

बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अगुआई वाले गठबंधन ने दो तिहाई बहुमत हासिल किया है। इसी के साथ बीएनपी का बांग्लादेश में एक स्थिर निर्वाचित सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। धार्मिक कट्टरता और अपनी अतिवादी सोच के लिए जानी जाने वाली जमात की अगुआई वाले गठबंधन को लोगों ने नकार दिया है। जनता का वोट सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा प्रस्तुस किए गए जुलाई चार्टर पर भी वोट दिया जो बांग्लादेश के संविधान और नौकरशाही में सुधारों की वकालत करता है जिसके तहत प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रपति के पद को सशक्त बनाया जाएगा।

पिछले तीन दशकों में यह पहली बार था कि बांग्लादेशी राजनीति की दो बेगमों, अवामी लीग की शेख हसीना और बीएनपी की खालिदा जिया, चुनावी मैदान में नहीं थी। बीएनपी की नई पीढ़ी के नेता तारिक रहमान ने एक बदलाववादी और महिलाओं को बराबर की सहभागिता वाले बांग्लादेश को प्रस्तुत किया वहीं जमात एक इस्लामिक कानून और विचारों वाले देश पर जोर दे रहा था, लेकिन नतीजों से साफ है कि भले ही लोगों ने 2024 में आंदोलन के जरिये शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट किया हो लेकिन वह एक कट्टरपंथी विचारधारा को विकल्प नहीं मानते। खासकर उनकी महलाओं को लेकर सोच क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है, जहां महिलाओं ने देश का संचालन ही नहीं बल्कि कपड़ा निर्माण उद्योग में अपने प्रयासों से अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हालांकि जमात को सरकार बनाने लायक जनमत भले ना मिला हो लेकिन बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी है, जो भविष्य में चिंता का विषय भी बन सकता है। 16 फरवरी को तारिक रहमान अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखने की बात होगी कि क्या वह बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार देने में सफल हो पाएंगे।

तारिक रहमान को अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की मजबूती पर खास काम करना होगा। अंतरिम सकरार के डेढ़ साल के कार्यकाल में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा होती रही है, जिसका संज्ञान संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिक और भारत जैसे देशों ने लिया था लेकिन यूनुस सरकार इसे रोकने में विफल रही। चूंकि अवामी लीग हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए काम करती रही जिसके चलते शेख हसीना को चुनावी लाभ मिला। लेकिन इस बार अवामी लीग चुनाव ही नहीं लड़ पाई ऐसे में बीएनपी को अल्पसंख्यक वोट मिला है और जमात को अपनी विचारधारा के कारण इसका नुकसान झेलना पड़ा है। तारिक रहमान एक उदार और समावेशी लोकतंत्र की बात करते रहे हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि बांग्लादेश में अतिवादी सोच वाली इस्लामी ताकतें हावी नहीं होंगी। बीएनपी को मिले जनादेश का असर बांग्लादेश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भविष्य पर होगा। एक सामरिक चुनौती भी होगी जिसमें भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाना शामिल है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में ढाका और दिल्ली के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर रहे। यूनुस लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाकर भारत के साथ संबंधों का राजनीतिकरण करने के अलावा भारतीय मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते रहे।

जम्मू-कश्मीर में मनी लांड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश, 8000 बेनामी बैंक खाते फ्रीज

श्रीनगर, प्रेट्र: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने म्यूल यानी बेनामी खातों के तेजी से फैलते नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मनी लांड्रिंग को देखते हुए तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में संचालित 8,000 से अधिक म्यूल खातों की पहचान कर इन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों के जरिये भेजा जाने वाला पैसा साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है। आशंका है कि आतंकी समूह इन खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जांच में सामने आया कि म्यूल खाते साइबर अपराध की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। इन खातों के माध्यम से ठग चुराए गए धन को कई स्तरों पर स्थानांतरित करते हैं। बाद में इसे क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों में बदल कर ट्रैक करना मुश्किल बना दिया जाता है।

क्या है म्यूल अकाउंट: गुमनाम बैंक खातों को 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है। साइबर फ्राड करने वाले सामान्यतः अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे अपराध जनित धन को अलग-अलग जगहों पर भेजने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मामलों में, धोखेबाज किसी व्यक्ति को कुछ फायदे का लालच देकर उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल अपराध के लिए करते हैं।

विदेश में बैठे पंजाब के गैंग्सटरों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में पंजाब पुलिस

रोहित शर्मा • जागरण

चंडीगढ़ : विदेश में बैठकर गैंग चला रहे गैंग्सटरों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। इस बार उसके निशाने पर गैंग्सटर के साथ विदेश में बनाई गई उनकी संपत्ति भी है। पुलिस पहली बार इंटरपोल से ऐसे गैंग्सटरों के खिलाफ 'सिल्वर नोटिस' जारी कराने की प्रक्रिया में जुटी है, ताकि उनकी विदेश में चल-अचल संपत्ति को जब्त किया जा सके। ऐसा होने से गैंग्सटरों का आर्थिक नेटवर्क तोड़ा जा सकेगा।

सिल्वर नोटिस क्या है : इंटरपोल ने जनवरी, 2025 से सिल्वर नोटिस की शुरुआत की थी। यह नोटिस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी संपत्तियों की पहचान, निगरानी और जब्ती के लिए जारी किया जाता है। इसमें बैंक खाते, लग्जरी वाहन, प्रापर्टी और बिजनेस तक शामिल होते हैं।

नौवीं के छात्र ने बनाया गैस लीक डिटेक्टर, टाला जा सकेगा हादसा

शिलांग, प्रेट्र : मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के नौवीं कक्षा के एक छात्र ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो गैस लीक होने पर आपको अलर्ट कर देगा। इससे गैस रिसाव से आग लगने की आशंका को टालना संभव होगा। इस इनोवेशन के लिए उसे पुरस्कृत भी किया गया है।

जिला क्रिश्चियन मल्टीपर्पस स्कूल के छात्र जेम्स डोनाल्ड खारकोंगोर को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की गुवाहाटी स्थित इकाई राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में यह सम्मान प्राप्त हुआ। पूर्वोत्तर विज्ञान मेले और नवाचार महोत्सव में उसने निर्णायक मंडल का पुरस्कार जीता है। जेम्स के पिता स्कूल शिक्षक हैं, जबकि मां एक गृहिणी हैं। उसने अपने नवाचार के पीछे की प्रेरणा बताते हुए कहा कि मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहता हूं।

ऐसे काम करता है डिटेक्टर

- स्मार्ट एलपीजी गैस लीक डिटेक्टर उन्नत सेंसरों का उपयोग करके हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करता है। गैस की सघनता सुरक्षित स्तर से अधिक होने पर वह अलार्म बजाता है।
- इसके साथ ही स्वचालित एग्जास्ट फैन भी चालू हो जाता है। इससे जमा हुई गैस फैल जाती है और आग लगने का खतरा कम हो जाता है।
- इस उपकरण की एक प्रमुख विशेषता स्वचालित सोलेनोइड वाल्व है, जो रिसाव का पता चलने पर गैस की आपूर्ति बंद कर देता है। इससे रिसाव रुक जाता है और आग या विस्फोट का खतरा कम हो जाता है।

अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की व्यावहारिकता, तकनीकी और संभावित सामाजिक प्रभाव को देखते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया है।

10वीं पास लड़का करा रहा था गेट में नकल, तीन परीक्षार्थियों समेत छह धरे

- जूतों में छिपाया था ब्लूटूथ, बाहर से गूगल कर बताते थे जवाब
- प्रत्येक परीक्षार्थी ने दो- दो लाख रुपये में किया था पेपर का सौदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : रायपुर में शनिवार को आयोजित गेट (इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता परीक्षा) से नकल करने के आरोप में तीन परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए परीक्षार्थियों में शामिल 30 वर्षीय सुमित सहवाग जम्मू के चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में सहायक इंजीनियर है। साथ ही नकल में सहयोगी हरियाणा के तीन शातिर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपित परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर गूगल कर अंदर मौजूद परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे। मजेदार बात ये है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को नकल कराने का एक आरोपित महज 10वीं पास है।

इस काम के बदले परीक्षार्थियों ने दो-दो लाख रुपये दिए थे।

पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपित • नईदुनिया

सरोना स्थित सेंटर के बाहर से हुई गिरफ्तारी: पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायपुर के सरोना स्थित आइओएन डिजिटल जोन के आसपास कुछ लोग संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली तो उनके पास से इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने पूरी साजिश कबूली।

हरियाणा से जुड़ा है पूरा नेटवर्क: गिरफ्तार सभी छह आरोपित हरियाणा के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं। इनकी पहचान दर्शन सहवाग, बंटी कुमार, नरेंद्र कुमार (तीनों सहयोगी) व सुमित सहवाग, लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्की, अमर (तीनों परीक्षार्थी) के रूप में हुई है।

चिंतन

मोदी को न्योता बांग्लादेश की एक सार्थक शुरुआत

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उभरता राजनीतिक परिदृश्य दक्षिण एशिया की कूटनीति के लिए अहम संकेत दे रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा जाना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश है संवाद, संतुलन और सहयोग की नई संभावनाओं का। यानी बांग्लादेश ने मोदी को न्योता देकर एक सार्थक शुरुआत की है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बनी रहेगी या कुछ नरमाहट आएगी यह तो भविष्य पर निर्भर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रहमान के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय बैठक है, लेकिन भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि नई दिल्ली इस परिवर्तन को गंभीरता से ले रही है। तारिक की ताजपोशी कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। 36 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। 20 साल के निर्वासन के बाद देश लौटकर उन्होंने कम समय में जनता का विश्वास अर्जित किया और बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिलाया है। यह जनादेश केवल सरकार बदलने का संकेत नहीं, बल्कि नीति-प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव की ओर भी इशारा करता है। शपथ ग्रहण समारोह इस बार पारंपरिक राष्ट्रपति भवन के बजाय ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जा रहा है। यह स्थान परिवर्तन भी एक प्रतीक है संभवतः अधिक सार्वजनिक और खुली राजनीतिक संस्कृति का। पड़ोसी देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजना बताता है कि रहमान सरकार क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता देना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सहयोग का एक मजबूत आधार रहा है। पिछले एक दशक में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन यह भी सच है कि दोनों देशों के रिश्ते समय-समय पर राजनीतिक बदलावों के साथ नए मोड़ लेते रहे हैं। तारिक ने शपथ से पहले स्पष्ट कहा है कि भारत के साथ वार्ता में बांग्लादेश के हित सर्वोपरि रहेंगे। यह बयान किसी भी संप्रभु राष्ट्र की स्वाभाविक प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने चीन को भी विकास साझेदार बताया है। यहीं से नई सरकार की संतुलन नीति का संकेत मिलता है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता और भारत की पारंपरिक भूमिका के बीच बांग्लादेश का संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर का यह कहना कि भारत के साथ संबंधों की नई शुरुआत हो सकती है, सकारात्मक संकेत है, परंतु चुनाव जीतते ही शेख हसीना की वापसी की मांग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार कुछ मुद्दों पर आक्रामक रुख अपना सकती है। ऐसे में आने वाले समय में नई दिल्ली और ढाका के बीच संवाद की गुणवत्ता ही तय करेगी कि रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई सरकार का रुख कैसा रहेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे की कहानी सहयोग की होगी या प्रतिस्पर्धा की।

आर्थिकी
सतीश सिंह

महंगाई नए आधार वर्ष के पैमाने में

सरकार ने महंगाई को मापने का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इस क्रम में, 12 फरवरी को पहली बार जनवरी माह की खुदरा महंगाई को नए आधार पर मापा गया। नए आधार पर जनवरी 2026 में यह बढ़कर 2.75% हो गई, जो दिसंबर में 1.33% थी, और यह पिछले 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है। नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।

आगामी 10 वर्षों के लिए सरकार ने महंगाई को मापने का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इस क्रम में, 12 फरवरी को पहली बार जनवरी माह की खुदरा महंगाई को नए आधार पर मापा गया। नए आधार पर जनवरी 2026 में यह बढ़कर 2. 75% हो गई, जो दिसंबर में 1. 33% थी, और यह पिछले 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। इस दौरान, मई 2025 में यह 2. 82% तक पहुंच गई थी।

महंगाई का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन कैसा है। जब लोगों के पास अधिक पैसे होंगे, तो वे अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी। यदि आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत, जब मांग कम होती है और आपूर्ति अधिक होती है, तो महंगाई घट जाएगी। सरकार आमतौर पर हर 5 से 10 वर्षों में नया आधार वर्ष चुनती है, जो साल सूखा, बाढ़, महामारी या अत्यधिक महंगाई से मुक्त हो। पुराने सूचकांक में खाने-पीने की वस्तुओं का वेटेज लगभग 50% था, जिसे अब घटाकर 36. 8% कर दिया गया है। गौरतलब है कि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसे कीमतों के लिए मानक या आधार माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस वर्ष की वस्तुओं की औसत कीमत को 100 माना जाता है। फिर, अन्य वर्षों की कीमतों की तुलना उसी आधार वर्ष से की जाती है। इससे पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई है। उदाहरण के लिए, यदि 2022 को आधार वर्ष माना जाए और उस वर्ष एक किलो आलू की कीमत 50 रुपये थी, और 2025 में वह बढ़कर 80 रुपये हो गई, तो महंगाई दर = (80-50)/50×100 = 60% है। यह फॉर्मूला खुदरा महंगाई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में उपयोग होता है। हालांकि, यह बाजार के सभी सामानों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। महंगाई को मापने के लिए एक बकेट में वैसी वस्तुओं व सेवाओं को रखा जाता है, जो महंगाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस क्रम में हर वस्तु को उपभोक्ता के बजट में उसके महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। सीपीआई सूचकांक की मदद से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) हर महीने खुदरा महंगाई की गणना करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल आम लोग ज्यादा करते हैं, जैसे कि खाद्य, कपड़े, आवास, ईंधन, स्वास्थ्य आदि। यह सूचकांक इन वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है, जो आधार वर्ष 2012 के संदर्भ में होते थे और अब ये 2024 के संदर्भ में होंगे। विकास को सुनिश्चित करने के लिए महंगाई की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है ताकि जनता की घटती क्रय शक्ति, स्थिर आय, और जीवन यापन की लागत का सही आकलन किया जा सके। इससे उपयुक्त वित्तीय योजना, निवेश की सुरक्षा, मजदूरी की उचित मांग और सरकार के लिए सही मौद्रिक नीतियों का निर्धारण आसान हो जाता है। जब महंगाई का चित्र स्पष्ट होता है, तो सरकार सही कदम लेकर इन पर नियंत्रण कर सकती है, जिससे आम जनता के नुकसान को रोका जा सकता है। महंगाई बढ़ने से पैसे का मूल्य घट जाता है, और इससे पता है कि हमें कितनी ज्यादा कमाने या बचत करने की जरूरत है।

अगर महंगाई अधिक हो, तो निवेश का रिटर्न नकारात्मक हो जाता है। वहीं, सही महंगाई दर जानकर

सोना, शेयर जैसे बेहतर निवेश के विकल्प को चुनने में आसानी होती है। महंगाई के सही आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, और जरूरी वस्तुओं पर इसके असर को समझा जा सकता है। सरकारें इन आंकड़ों की मदद से ब्याज दरें और करों में बदलाव करती हैं। आंकड़ों के गलत रहने से सरकारी नीतियां जनता के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जब महंगाई स्थिर नहीं रहती, तो जनता को सही आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पिछले एक दशक के दौरान लोगों की जीवनशैली, खर्च करने के तरीके और लोगों के दैनिक आवश्यकताओं में आमूल-चूल बदलाव आया है। इसलिए, 2012 का आधार वर्ष महंगाई की सही तस्वीर नहीं दिखा पा रहा था। आंकड़े वास्तविक आयों के लिए सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले सूचकांक में 299 वस्तुएं थीं, जिन्हें नए ढांचे में बढ़ाकर 358 कर दिया गया है। नए सूचकांक की मुख्य विशेषता है कि यह उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है जिन पर आज अधिकांश लोग खर्च कर रहे हैं।

अब, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईयरफोन, फिटनेस बैंड जैसे उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जबकि पहले इनका उपयोग सीमित था। इस सूचकांक में नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। नया आधार वर्ष लाने का मकसद है सब्जियों, अनाज जैसी वस्तुओं की कीमतों में बदलाव से महंगाई के आंकड़ों पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। इस बदलाव से गैर-खाद्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव को भी महंगाई मापने में शामिल किया गया है, ताकि महंगाई की वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आ सके। नए सूचकांक में ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से वस्तुओं की कीमतों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। हवाई किराए, बिजली दरें, ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं और शॉपिंग की कीमतों को भी शामिल किया जाएगा।

इसी तरह, इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव का प्रभाव भी महंगाई के आंकड़ों में दिखाई देगा। ग्रामीण इलाकों में घर के किराए को सूचकांक में शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण महंगाई की तस्वीर और भी ज्यादा साफ होगी। इनके अलावा, वे वस्तुएं, जिनका उपयोग आज नहीं किया जाता है, जैसे वीडियो और ऑडियो कैसेट आदि, महंगाई मापने वाली सूची से हटा दी गई हैं। महंगाई की वास्तविक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे गलत तरीके से पेश किया गया, तो यह न सिर्फ जनता को परेशान कर सकता है, बल्कि विकास में भी बड़ी बाधा बन सकता है।

जब महंगाई की दर बढ़ती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को कम नहीं करता, जिससे बैंकों को सस्ती पूंजी नहीं मिलती और उन्हें उच्च ऋण दर पर ऋण देना पड़ता है। इससे उधार लेने की प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, और पूंजी की कमी के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद हो जाती हैं। इसलिए, महंगाई का सही स्तर समझना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आधार वर्ष में बदलाव और बकेट में उपयोगी वस्तुओं को शामिल करने से महंगाई की सच्चाई सामने आ सकती है, और सही उपाय अपनाकर विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार 2024 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुधार है। नई व्यवस्था न केवल गरीबी के अनुमानों को अधिक सटीक बनाएगी, बल्कि सरकार की नीतियों को भी बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगी।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष
सुनील कुमार महला

क्योटो प्रोटोकॉल : जलवायु समझौतों के लिए मार्गदर्शक

पर्यावरणीय दृष्टि से 16 फरवरी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल आधिकारिक रूप से लागू हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता था। इसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक (विकसित) देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम करना था, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से प्रभावित है, जिसका प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, तेज शहरीकरण, विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, परिवहन, कृषि गतिविधियां और प्रदूषण हैं, जिनसे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। ग्रीनहाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प तथा फ्लोरीनयुक्त गैसें आदि वायुमंडल में सूर्य की ऊष्मा को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, जिसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग 57.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.3% अधिक है। इस अवधि में उत्सर्जन वृद्धि में भारत का योगदान सबसे अधिक रहा, हालांकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी वैश्विक औसत से कम है। बता दें कि भारत में लगभग 3 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, जबकि वैश्विक औसत लगभग 6.4 टन है। कुल उत्सर्जन के मामले में भारत लगभग 4 गीगाटन वार्षिक उत्सर्जन के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन ऐतिहासिक योगदान विकसित देशों से कम है। जानकारी के अनुसार 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 423–425 पीपीएम तक पहुंच गई, जो औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में लगभग 50% अधिक है और जलवायु जोखिम को बढ़ा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 'साझा लेकिन भिन्न जिम्मेदारी' का सिद्धांत था। इसके अनुसार ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले विकसित देशों पर अधिक दायित्व डाला गया, जबकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को शुरुआती चरण में अनिवार्य उत्सर्जन कटौती से छूट दी गई। इस समझौते के अंतर्गत उत्सर्जन व्यापार, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) और संयुक्त कार्यान्वयन जैसे नवाचारपूर्ण तंत्र बनाए गए, जिन्हें फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कहा गया और इन्हीं के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा विकसित हुई, जिससे विकसित देश अन्य देशों में हरित परियोजनाओं या स्वच्छ तकनीक में निवेश करके कार्बन क्रेडिट खरीद सकते थे। भारत ने सीडीएम के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाएं विकसित कीं, जिससे तकनीकी आधुनिकीकरण, विदेशी निवेश और 'सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन' (सीईआर) क्रेडिट के रूप में आर्थिक लाभ मिला तथा भारत वैश्विक कार्बन बाजार का महत्वपूर्ण भागीदार बना। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन इसे अपनी संसद से अनुमोदित नहीं कराया, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठे, फिर भी इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन की सख्त वैश्विक प्रणाली विकसित की, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। आगे चलकर वैश्विक जलवायु प्रयासों को अधिक व्यापक बनाने के लिए 2015 में पेरिस समझौता अस्तित्व में आया, जिसमें लगभग सभी देशों को जलवायु कार्रवाई के साझा लक्ष्य में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2023-2024 में वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर के आसपास है और वर्तमान नीतियों के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि लक्ष्य हासिल करना कठिन दिखाई देता है। हालांकि, अब वैश्विक जलवायु नीति का केंद्र पेरिस समझौता बन चुका है, फिर भी क्योटो प्रोटोकॉल ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी। भारत ने वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किए हैं। आज जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह समझौता दुनिया को उत्सर्जन नियंत्रण की जिम्मेदारी याद दिलाता है। संक्षेप में, क्योटो प्रोटोकॉल आधुनिक वैश्विक जलवायु नीतियों का आधार माना जाता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जब मन अशांत हो तो इष्टदेव के मंत्रों का जप करें

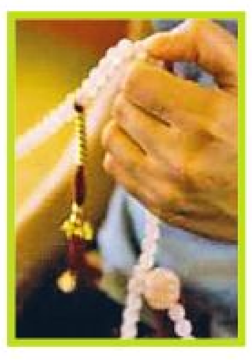

संकलित
दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

काम शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है काम करते रहना

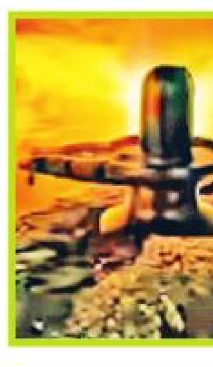

संकलित
प्रेरणा

एक प्राचीन कथा के मुताबिक, ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के मस्तक और पैरों की खोज शुरू की। ब्रह्मा को शिव का मस्तक ढूंढने का और विष्णु को शिव के पैर ढूंढने का कार्य सौंपा गया। सभी देवता इसके आरंभ और अंत के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा आरंभ की और वे आगे बढ़ते गए। कई लोक पीछे छूट गए और कई युग बीत गए। फिर भी ब्रह्मा शिव के मस्तक का पता नहीं लगा पाए। सृष्टि का एक अंत है। सृजन एक बिंदु पर समाप्त होता है। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा उसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने एक केतकी का पुष्प देखा जो आकाश से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से पूछा, 'तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने शिव का मस्तक देखा है? यहां से शिव का मस्तक कितनी दूर है?' केतकी पुष्प ने कहा, 'मैं शिव के मस्तक से आ रहा हूं।' तो ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि शिव का एक मस्तक था और वे पुष्प लेकर नीचे आए। विष्णु का कार्य शिव के पैरों की खोज करना था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु बहुत विनम्र हैं। पालनकर्ता को हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए। रचयिता जैसा भी हो, यदि पालनकर्ता विनम्र हो, तभी पालन कार्य संभव है। व्यवसाय आरंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सतर्क, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार डूब जाएगा। विष्णु की विनम्रता ने ही उन्हें शिव के चरणों को ढूंढने का कार्य करने योग्य बनाया। युगों तक यात्रा करने के बाद, विष्णु शिव के चरणों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए।

अंतर्मन

आज की पाती

महाशिवरात्रि : भीतर के अंधकार से संवाद

महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का वह विराट क्षण है जहां आस्था, दर्शन और आत्मबोध एक-दूसरे से संवाद करते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की यह चतुर्दशी, शिव-तत्व के स्मरण और साधना का पर्व है- वह शिव, जो संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन और कल्याण के अधिष्ठाता हैं। भारतीय दर्शन में शिव को आदि और अनंत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि नवसृजन के भी मूल स्रोत हैं। शिव का डमरु ब्रह्मांड की लय को उद्घोषित करता है, गंगा का अवतरण करुणा का प्रतीक है और भस्म-विभूषण यह संदेश देता है कि भौतिकता अंततः नश्वर है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना की रात्रि है।

- जगदीश पाठक, बेमेतरा

करंट अफेयर

नाइजीरिया में हुई मछली पकड़ने की प्रतियोगिता

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित अर्गुगु शहर में हरियाली के बीच बहने वाली मतान फदान नदी में शनिवार को हजारों मछुआरे मछली पकड़ने के पारंपरिक पर्व में शामिल हुए। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू सहित हजारों दर्शकों ने सबसे बड़ी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। हालांकि सुरक्षा संबंधी कारणों से कुछ लोगों ने उत्सव से दूरी बनाए रखी। इस पर्व पर मछली पकड़ने के लिए लोगों ने हाथ से बुने जाल और लौकी से बने बर्तन जैसे केवल पारंपरिक समानों का इस्तेमाल किया। कुछ ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए केवल हाथों से ही मछली पकड़ी। इस साल के विजेता ने 59 किलोग्राम की क्रोकर मछली पकड़ी। प्रतियोगिता के विजेता को नकद इनाम दिया जाता है, जबकि बाकी प्रतिभागी अपनी पकड़ी मछलियां बेचते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साल के बाकी समय इस नदी में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती और इसकी देखरेख एक पदवीधारी प्रमुख करते हैं, जिन्हें 'सरकिन रुवा' यानी पानी का मुखिया कहा जाता है। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता वार्षिक अंतरराष्ट्रीय मछली पकड़ने के उत्सव का समापन था। पर्व के दौरान पारंपरिक कुश्ती, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।

ऑफ बीट

रूमाल या टिश्यू, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन बेहतर

आज, हम जानते हैं कि नाक से निकलने वाले स्राव में ठंडे प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जो कई सतहों पर स्थानांतरित हो सकते हैं - हाथ, रूमाल, टिश्यू, दरवाज़े के हैंडल, कीबोर्ड - कभी-कभी शुरुआती जोखिम के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इसलिए दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले सूती रूमाल में अपनी नाक साफ करना, फिर किसी अन्य वस्तु को छूना, इसका मतलब है कि ये वायरस फैल सकते हैं। यहां तक कि अगर आप अपने सूती रूमाल को तुरंत धोने के लिए रख देते हैं, तो भी आप दरवाजे की कुंडी जैसी सतहों को दूषित कर देंगे, और वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए अपने संक्रमित हाथों का उपयोग करेंगे। वायरस टिशू पर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। बशर्ते आप टिश्यू का उपयोग करने के बाद उन्हें फेंक दें, और उन्हें दूसरों के उठाने के लिए इधर-उधर नहीं छोड़ें, तभी इस्तेमाल किए गए टिश्यू से दूसरों तक रोगाणु पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। फिर सवाल यह है कि क्या रुमाल या टिश्यू खांसी और सांस के रास्ते निकलने वाले थूक को रोकने के लिए प्रभावी हैं। रूमाल जैसे बुनियादी कपड़े के आवरण, टिश्यू की तरह, थूक को पकड़ सकते हैं। लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि वे श्वसन एरोसोल को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं करते हैं।

ट्रेंड

कांग्रेस की बौखलाहट

कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। इसलिए आज जब हम अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, टनल्स, ऊंचे-ऊंचे ब्रिज और आधुनिक एयरफील्ड्स के साथ देश की सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं, तो वो बौखलाहट से भर गई है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिक्षा से रोजगार तक

औद्योगिक विकास के साथ-साथ कौशल विकास को केंद्र में रखा गया है, उद्योग-अकादमिक साझेदारी, अप-स्किलिंग, एआई और डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि शिक्षा से रोजगार तक का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो और स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलें।

- धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

किसानों से विश्वासघात

हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के नाम पर भारत के किसानों के साथ हो रहे विश्वासघात को देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं,. डीडीजी आयात करने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब भारतीय पशुओं को जीएम अमेरिकी मक्के से बना डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाया जाएगा?

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

सोलर से समृद्धि

दिल्ली ने सोलर से समृद्धि का रास्ता प्रशस्त कर लिया है। अब किसान बिना एनओसी के कृषि भूमि पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। हमारी सरकार ने प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि किसानों की आय बढ़े।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि त्योहार, पीएम समेत कई नेताओं ने दीं बधाई

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

हर-हर महादेव के उद्घोष और भक्ति के असीम उत्साह के साथ रविवार को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया। काशी से लेकर हरिद्वार और देवघर से लेकर उज्जैन तक, शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए घंटों लंबी कतारों में लगे थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'एक्स' पर लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहे।

देशभर में 'बम-बम भोले' की गूंज

काशी से लेकर हरिद्वार और देवघर से लेकर उज्जैन तक, शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्त आराध्य देव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए घंटों लंबी कतारों में लगे थे

सभी शिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई

हरिद्वारः कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान शिव की ससुराल माना जाता है

भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान होः पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने लिखा कि सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

महादेव का आशीर्वाद बना रहेः रेखा गुप्ता

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजस्थान के उदयपुर के अम्बेरी स्थित प्राचीन अमरख महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद दिल्ली और समस्त देशवासियों पर बना रहे, और हम सभी को सेवा और लोककल्याण के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान करें।

कुणाल खेमू और सोहा अली ने मनाई शिवरात्रि, दी शुभकामनाएं

कुणाल खेमू और सोहा अली खान ने महाशिवरात्रि पर अपने घर में खास पूजा रखी और सभी को शुभकामनाएं दीं। उनका परिवार भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। सोहा और कुणाल पूरे परिवार के साथ मिलकर शिवजी की आरती की। घर को दीपों और फूलों से सजाया और भगवान को भोग अर्पित किया।

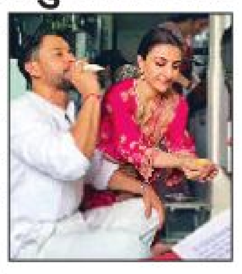

अमृता का 'शंभू रे' गाना रिलीज 55 लाख लोगों ने देखा

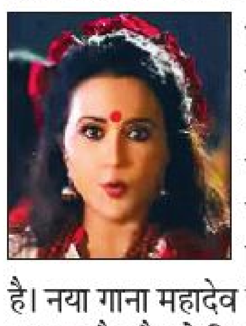

एक्ट्रेस-गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता अमृता फडणवीस ने महाशिवरात्रि पर अपना नया गाना शंभू रे भगवान शिव को समर्पित किया है। नया गाना महादेव के भक्तों को खूब पसंद आ रहा है और दो दिन में 55 लाख लोगों ने इसे यूट्यूब पर देखा और सराहा।

खबर संक्षेप

शिअद में शामिल हुए भाजपा उपाध्यक्ष खन्ना

चंडीगढ़। पंजाब में संगरूर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना शिअद में शामिल हो गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिअद प्रमुख सुखबीर बादल अरविंद खन्ना के संगरूर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे और अरविंद खन्ना को पार्टी में शामिल करवाया। अरविंद खन्ना भाजपा के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष थे।

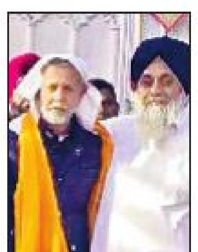

सराज में जीप दुर्घटनाग्रस्त 3 युवकों की मौत

थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के सराज में 4 में से 3 युवकों की जीप दुर्घटनाग्रस्त होने पर मौत हो गई। चारों बगस्याड़-रहीधार क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल पहुंचने के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

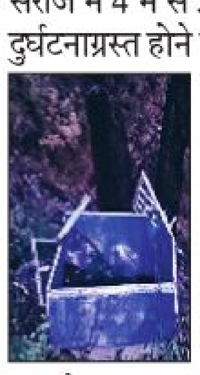

कर्नाटक में फैक्ट्री में धमाका, 2 मजदूरों की मौत

बेंगलुरु। कर्नाटक के मांड्या जिले में रविवार को केरेकाटे गांव के पास स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में स्टोरेज टैंक फटने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका उस समय हुआ जब फैक्टरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी और टैंक की सफाई की जा रही थी।

बस और कार में टक्कर, 5 युवकों की मौत

बेंगलुरु। बेंगलुरु के नेलमंगला के एक कार और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पांच लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि कार बेंगलुरु की ओर जा रही थी। इस दौरान अचानक कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंच गई।

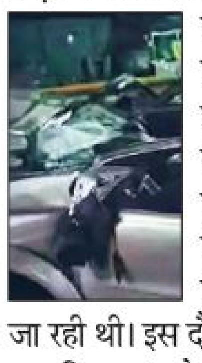

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राहुल को दी किसी भी मंच पर आने की चुनौती

कहा- बहस कर लें, किसानों का नुकसान किसने किया, कांग्रेस 'गुमराह' कर रही

शाह ने कहा कि समझौतों में डेयरी क्षेत्र को भी पूरी तरह सुरक्षा देने का काम पीएम मोदी ने किया है। इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और मत्स्य उत्पादों को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का रास्ता भी खोला है

एजेंसी ▶▶ गांधीनगर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया और यूएस ट्रेड डील पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड के साथ एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में पीएम मोदी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं, कोई भी मंच तय कर लीजिए, भाजपा के युवा मोर्चा का अध्यक्ष आकर बहस कर लेगा कि किसानों का नुकसान किसने किया है।

भाजपा के युवा मोर्चा का अध्यक्ष आकर बहस कर लेगा

मनमोहन सरकार ने डंकल प्रस्ताव पर साइन कर विश्व बाजार खोला

पीएम मोदी किसानों की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हुए

गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह

पीएम ने किसानों को पूरी सुरक्षा दी

शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिका से हुई ट्रेड डील में पीएम मोदी ने किसानों के हितों की सुरक्षा की है।

पीएम मोदी ने डंकल समझौता बदलकर देश को बचाया

शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने डंकल प्रस्ताव पर साइन करके किया था। देश की जनता ने 2014 में कांग्रेस को 'टाटा बाय-बाय' कर दिया, पीएम मोदी आए और उस समझौते को बदल दिया।

कांग्रेस ने कर्जमाफी का झुनझुना पकड़ाया

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने 70 साल में एक बार कर्जमाफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह किया। पीएम मोदी ने 10 साल से 6,000 रुपए प्रति वर्ष देकर किसानों को लोन लेने की नौबत ही न आए, ऐसी व्यवस्था की। कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा है। कांग्रेस बताए किसानों का कितना अनाज खरीदा था?

डील किसानों के साथ विश्वासघातः राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के किसानों के साथ विश्वासघात करने का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि अमेरिका ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं।

राहुल गांधी ने पूछे 5 सवाल?

- डीजीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स अनाज खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
- अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
- जब आप 'अतिरिक्त उत्पाद' कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
- 'गैर-व्यापार बाधाएं' हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, खरीद प्रक्रिया को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
- एक बार यह दरवाजा खुल गया, तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा?

केंद्र ने स्टार्टअप फंड को दी मंजूरी

10000 करोड़ की मदद से नए निवेशकों को होगा बड़ा लाभ

पहले चरण में 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स को लाभ

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टार्टअप्स को शुरुआती निवेश उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए फंड 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0' को मंजूरी दे दी है। इस फंड का विशेष फोकस डीप टेक, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के संस्थापकों पर रहेगा, ताकि नवाचार को शुरुआती वित्तीय कमी के कारण रुकना न पड़े। यह योजना 2016 में शुरू किए गए पहले फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण के रूप में लाई गई है। पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए के पूरे कोष को विभिन्न निवेश फंड्स के माध्यम से तैनात किया गया। इनके जरिए 1,370 से अधिक स्टार्टअप्स को समर्थन मिला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थकेयर तथा स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में 25,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। नए फंड का प्रमुख उद्देश्य डीप टेक और नवोन्मेषी विनिर्माण जैसे लंबे समय में विकसित होने वाले क्षेत्रों को 'लंबी अवधि की धैर्यपूर्ण पूंजी' उपलब्ध कराना है। इन क्षेत्रों में जोखिम अधिक होने के कारण निजी निवेशक अक्सर निवेश से बचते हैं, जिससे उच्च-जोखिम पूंजी की कमी बनी रहती है।

इनमें 25,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ

विदेशी निवेश पर निर्भरता कम होगी

नई योजना का एक अहम लक्ष्य निवेश को केवल बड़े स्टार्टअप हब जैसे बेंगलुरु या दिल्ली तक सीमित न रखकर देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना भी है, ताकि नवाचार का दायरा व्यापक हो सके और घरेलू दीर्घकालिक पूंजी को बढ़ावा मिले। इससे विदेशी निवेश पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2016 से अब तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो चुकी है। सरकार का मानना है कि यह नया फंड आर्थिक मजबूती, विनिर्माण क्षमता में वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा व 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा।

देश के सभी हाई कोर्ट को 'सुप्रीम' निर्देश

फरार आरोपियों को अग्रिम जमानत न दें, 'अनावश्यक' इस्तेमाल रोकें

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे उन आरोपियों को अग्रिम जमानत न दें जो फरार हो जाते हैं। कोर्ट ने फरार आरोपियों के बारे में कहा कि ये ट्रायल पूरा होने पर अपने सह-आरोपियों के बरी होने के बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और विजय बिश्नोई की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फरार आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी, उसे सरेंडर करने और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम बेल की राहत देना, एक बुरी मिसाल कायम करता है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत था। और इसके अलावा यह लोगों को बिना किसी सजा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है। जज बिश्नोई ने कहा कि एक फरार व्यक्ति आमतौर पर अग्रिम बेल की राहत का हकदार नहीं है, हालांकि, कुछ खास मामलों में, जहां एफआईआर, केस डायरी और रिकॉर्ड में मौजूद दूसरी जरूरी चीजों को देखने पर, कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि फरार आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, तो अग्रिम बेल देने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सबरीमाला मंदिर का मुद्दा फिर गरमाया

महिलाओं के प्रवेश पर सरकार से मांगा जवाब, आज कोर्ट में सुनवाई

एजेंसी ▶▶ तिरुवनंतपुरम

केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार से साफ रुख बताने की मांग की है। सवाल यह है कि सरकार अदालत में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करेगी या अपना पुराना हलफनामा वापस लेगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2018 के फैसले से जुड़े रिव्यू और रिट याचिकाओं पर विचार करने वाला है। उस फैसले में हर उम्र की महिलाओं को भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अदालत में जाने से पहले जनता को अपना रुख साफ-साफ बताना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर अब तक असमंजस की स्थिति में है।

सबरीमाला मंदिर

टॉय ट्रेन में सरिता पहली महिला टिकट कलेक्टर

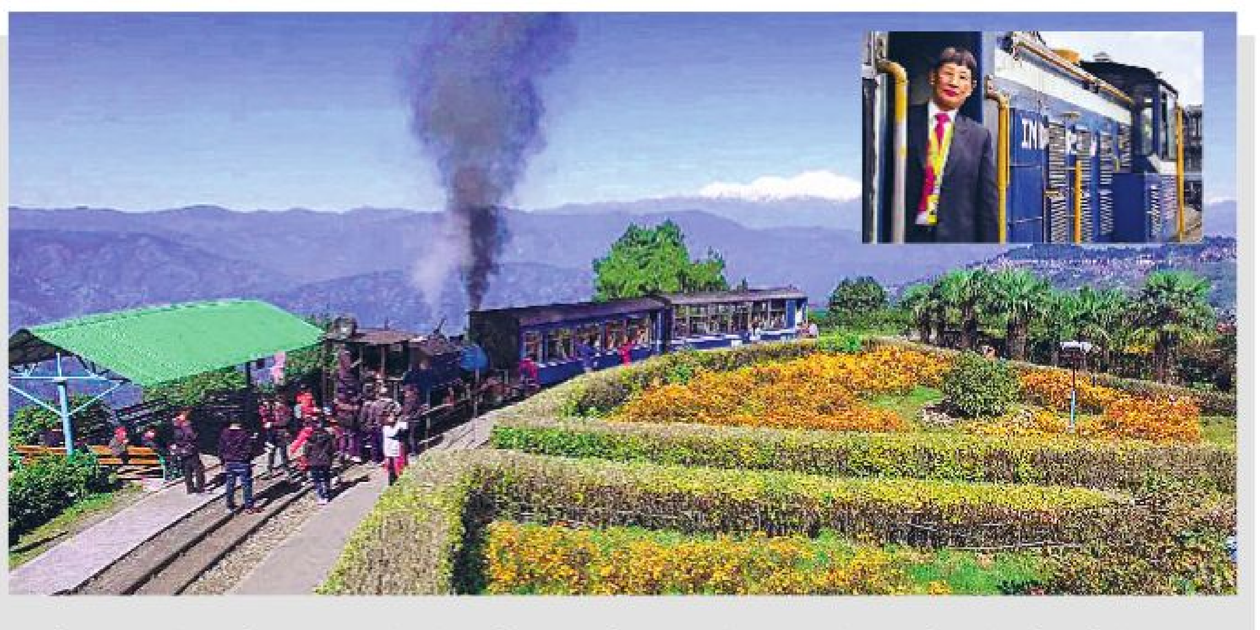

दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन में पहली बार किसी महिला को टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। सरिता योलमो ने 145 साल पुराने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) में वरिष्ठ वाणिज्यिक-सह-टिकट संग्राहक बनकर इतिहास रच दिया है। यह रेलवे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। 55 वर्षीय सरिता योलमो गोरखा समुदाय से आती हैं। इससे पहले वे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर सीटीसी के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी-बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला जो समाज के लिए एक चेतावनी भी

सहमति से लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद शादी का वादा तोड़ना बलात्कार नहीं

एजेंसी ▶▶ नैनीताल

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सहमति से लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद शादी का वादा तोड़ना रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब दो व्यस्कों के बीच सहमति से संबंध बनते हैं तो रेप केस के लिए, यह साबित करना जरूरी है कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था। कोर्ट ने कहा है कि जब दो वयस्क आपसी सहमति से लंबे समय तक संबंध में हों तो शादी के वादे को पूरा न करना आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार नहीं माना जा सकता।

कई बार मिलना आपसी सहमति का संकेत

उत्तराखंड हाई कोर्ट

कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष लंबे समय से रिश्ते में थे और उनके बीच बार-बार शारीरिक संबंध बने थे, जिससे प्रारंभिक धोखाधड़ी के बजाय आपसी सहमति का संकेत मिलता है। हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि ठोस आधार के अभाव में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आरोपी का उत्पीड़न होगा।

महिला अपराध सिद्ध न कर सकी

जस्टिस आशीष नैथानी ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी वयस्क महिला द्वारा दी गई सहमति मात्र इसलिए अमान्य नहीं हो जाती क्योंकि संबंध शादी में नहीं बदला। इसे धारा 376 के तहत अपराध मानने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि शादी का वादा केवल संबंध बनाने के लिए सहमति पाने का एक साधन था और आरोपी का शादी करने का कोई इरादा नहीं था।

गरीबों को मिलने वाले अनाज वितरण की प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर

पूरे देश में अब 'ग्रेन एटीएम' से निकलेगा अनाज

एजेंसी ▶▶ गांधीनगर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (सीबीडीसी) पर आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) का उद्घाटन किया। यह पहल पीएम नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है। इस नई प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय खाद्य निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अनाज वितरण की प्रक्रिया से बिचौलियों को पूरी तरह बाहर करना है।

खास बात

- गृह मंत्री ने 'अन्नपूर्ति' मशीन का उद्घाटन किया
- 4 साल के भीतर पूरे देश में लागू होगी यह योजना

गेहूं, चावल, दाल, चना भी मशीन से मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

इस कार्यक्रम के दौरान 'अन्नपूर्ति' मशीन का भी उद्घाटन किया गया, जो गुजरात में विकसित एक 'ग्रेन एटीएम' है। अमित शाह ने इसे तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता का अद्भुत संगम बताया। इस एटीएम के जरिए अब गरीबों को केवल गेहूं या चावल ही नहीं, बल्कि 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो चने, नमक और चीनी भी वितरित की जाएगी। यह मशीन 'मेड इन गुजरात' का प्रतीक है और देश की तकनीकी प्रगति को दर्शाती है।

खाद्य सुरक्षा में बड़ा बदलाव

गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि अगले 3 से 4 साल के भीतर इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इससे हर गरीब व्यक्ति को उसके हक का पूरा 5 किलो अनाज सुरक्षित तरीके से मिल सकेगा। यह डिजिटल कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शिता पर जोर

अमित शाह ने कहा कि कई सालों से देश के पिछड़े इलाकों में भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस नई डिजिटल व्यवस्था के आने से खाद्य और आपूर्ति विभाग के काम करने के तरीके में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। यह सिस्टम आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और सटीक होगी।